

माक्सवादी अर्थशास्त्र

लेखक

शंकर दयाल तिवारी

५

समाजवादी साहित्य सदन, कानपुर

लेखक :

शंकर दयाल तिवारी

०

मुद्रक :

शान्ति प्रेस, लखनऊ

मूल्य : ४ रुपया

विषय-सूची

- १—मावर्तवादी-अर्थशास्त्र ... १७
 अर्थशास्त्र का विषय
- २—पूँजीवाद की विशेषता ... १२
- ३—वस्तु, मूल्य और मुद्रा ... १५
 वस्तु उत्पादन — मूल्य — मूल्य धम और अमूल्य धम
 —मूल्य के स्वरूप—मुद्रा—मूल्य का नियम—वस्तु का
 चमत्कार या दैवी स्वरूप
- ४—पूँजी, अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी ... २८
 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त — पूँजी क्या है ?—सतत
 पूँजी तथा परिवर्तनशील पूँजी — स्थिर पूँजी और
 चलनशील पूँजी — शोषण के विभिन्न स्वरूप — पूँजी-
 वाद का विकास — मजदूरी के विभिन्न स्वरूप — नाम
 की मजदूरी — वास्तविक मजदूरी
- ५—पूँजी का संवय तथा पूँजी का दैहिक अनुपात ... ४९
 पुनरोत्पादन—माधारण तथा परिवर्द्धित—पूँजी का दैहिक
 अनुपात — बेकारी और गरीबी की वृद्धि — पूँजी के
 मंचय का नियम
- ६—अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा ... ५८
 पूँजी का आवर्तन—लाभ की दर और अतिरिक्त मूल्य
 की दर — औसत लाभ और उत्पादन के दाम — लाभ की
 दर और लाभ का योग — ध्यापारिक लाभ — उधार पूँजी

और व्याज — धर्मों का काम — उगाड़ण्ट म्याक कम्पनी
— पूजीवादी लगान क्या है ? — निर्वाचित लगान — मंती में
मूल्य का नियम — विजय लगान — कृषि में पूजीवाद का प्रचार

७—पूजीवादी पुनरोत्पादन और आर्थिक संकट ... ८६

साधारण पुनरोत्पादन—परिवर्द्धित पुनरोत्पादन—राष्ट्रीय
आय और उगका विभाजन—पूजीवाद का आर्थिक संकट

८—एकाधिकारी पूजीवाद और साम्राज्यवाद ... ९९

एकाधिकारी पूजी के संगठन — साम्राज्यवाद — महाजती
पूजी का आधिपत्य—पूजी का निर्यात—विश्व का आर्थिक
और क्षेत्रीय विभाजन—पूजीवाद के पतन का समय
—नव-उपनिवेशवाद—राजकीय एकाधिकारी पूजी और
राजकीय पूजीवाद

९—पूजीवाद का आम संकट ... १०७

१०—समाजवाद और साम्यवाद ... १२३

समाजवाद के सामान्य आर्थिक नियम — मजदूर वर्ग का
अधिनायक तंत्र—समाजवादी क्षेत्र का निर्माण—समाज-
वादी कृषि — परिस्थितियों का प्रभाव — समाजवादी
औद्योगीकरण — सम्पत्ति के स्वरूप — समाजवाद का
मौलिक नियम—नियोजित अर्थ व्यवस्था—वस्तु-उत्पादन,
मूल्य का नियम, व्यापार — श्रम की उत्पादकता में वृद्धि
—परिवर्द्धित पुनरोत्पादन—पिछड़ी जातियों और क्षेत्रों
का विकास — सांस्कृति उन्नति — अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक
सम्बन्ध—समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण—साम्यवाद
लगभग साथ साथ आयेगा—साम्यवाद का आर्थिक आधार
—सामाजिक विभेद का अन्त — नवीन मानव का उदय

भूमिका

द्वितीय खण्ड, १९६९, पृ. १

मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है। द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद उस दर्शन का सारतत्व है। विश्व की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर मार्क्स इस नतीजे पर पहुँचे थे कि समाज में भी उसकी तत्कालीन "आर्थिक व्यवस्था ही वह बुनियाद होती है जिस पर (उसका) राजनीतिक ढांचा खड़ा किया जाता है" (लेनिन)। इस निष्कर्ष पर पहुँचने ही मार्क्स समाज की आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन में जुट गये। उनका महान ग्रन्थ "तूजी" इसी अध्ययन का परिणाम था। इस ग्रन्थ में आधुनिक पूँजीवादी युग की अर्थ-व्यवस्था का गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और बतलाया गया है कि मीत्रवादी पूँजीवादी समाज की सभी मान्यताओं सभी कायदे-कानूनों का आधार उसकी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था है जिसका आमूल परिवर्तन किए बिना समाज व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

लेनिन के शब्दों में, "उत्पत्ति, विकास और अद्वयमान सभी अवस्थाओं में ऐतिहासिक तौर पर पारिभाषित समाज के उत्पादन के सम्बन्धों की जीव पड़ताल ही मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का सारतत्व है।"

यदि हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं तो हमें मार्क्स के विचारों के सभी पक्षों—दार्शनिक, अर्थनीतिक और राजनीतिक—का बोध होता है और इनमें से किसी भी पक्ष को मार्क्सवाद से अलग नहीं किया जा सकता। मार्क्स की विचारधारा के केवल दार्शनिक अथवा

अर्थ-वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ पक्ष को मार्क्सवाद नहीं कहा जा सकता । फिर भी मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण उनकी विचारधारा का एक प्रथम अंग है और मार्क्सवाद में मार्क्स के आर्थिक विश्लेषणों के अलावा लिए बर्गेस मुद्रिका व ईडल्लु समाजशास्त्र के अन्वयन आवश्यक है ।

मार्क्स के राजनीतिक पक्ष अर्थात् अन्वयन व और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर हिन्दी में कई एक पुस्तकें उपलब्ध रही भी । उमरी आर्थिक पक्ष अर्थात् मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पर कोई पुस्तक (कन्नड़ी या तुरी) उपलब्ध नहीं । का० अरुण शर्मा व मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पर यह पुस्तक नियन्त्रण हिन्दी साहित्य के दम बन्दूक बंदे अज्ञान को पूरा किया है । पुस्तक की भाषा तुरी आसान है और हमने कठिन विषय को रोचक तथा सरल शैली में प्रस्तुत कर सकने के लिए नेग्रर निरन्तर ही बधाई का पात्र है ।

पूँजीवाद में समाजवाद में संकल्प के अन्तर्गत इन युग में समाजवाद के लिए नव्यंत्रण अपने मापिषो के लिए यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है । पूँजीवाद कैसे आया, पत्नीपति मजदूर को कैसे ठगता है, कैसे उसका शोषण करता है, इस समाज की क्या अनभिनियां है, जनता के हित में इस समाज व्यवस्था का अन्त क्यों आवश्यक है, पूँजीवाद का पतन क्यों अवश्यम्भायी है आदि विषयों पर प्रकाश डालने के साथ साथ पुस्तक के अन्त में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । पुस्तक समाजवाद, साम्यवाद के लिए प्रयत्नशील कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं, मार्क्सवाद के विद्यार्थियों, स्कूलों और कालेजों के छात्रों सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ।

शिव वर्मा

पहला अध्याय / मार्क्सवादी अर्थशास्त्र

मार्क्सवादी विचारधारा के तीन मुख्य अंग हैं—(१) वर्गों का दंगन (२) उसका अर्थशास्त्र और (३) समाजवाद के मध्यम में विचार। मार्क्सवाद के इन तीनों अंगों का उल्लेख करते हुए लेनिन ने लिखा है कि यही मार्क्सवाद के तीन स्तंभ भी हैं। (लेनिन—लेनिनसट्टेड वरुथं पृ० ५९, मानवो सुस्वरण १९४६ ई०)

मार्क्सवादी दंगन एक भौतिकवादी दंगन है। मार्क्स और एन्गेल्स ने लगातार भौतिकवादी दृष्टिकोण की उसके विरोधियों में रक्षा की तथा इस दृष्टिकोण को और भी अधिक गहन बनाया। मार्क्स ने भौतिकवादी दृष्टिकोण को केवल प्रकृति पर ही नहीं लागू किया बल्कि इसी दृष्टिकोण में इतिहास का भी अध्ययन और विश्लेषण किया। इतिहास और मानव समाज पर दृष्टात्मक भौतिकवाद की दृष्टि में विचार करते हुए मार्क्स ने यह नतीजा निकाला कि मानव समाज की सभी विचारधाराओं और उसके विभिन्न प्रकार के संगठनों (राजनीतिक, सांस्कृतिक वर्ग-रह) का निर्माण आर्थिक ढाँचे की बुनियाद पर होता है।

यह प्रदर्शित करके कि समाज का राजनीतिक ढाँचा उसकी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर कायम होता है, मार्क्स ने पूँजीवादी समाज की आर्थिक प्रणाली के नियमों का अध्ययन किया और यह बतलाया कि पूँजीवादी समाज की विशेषता क्या है, इस समाज में किस प्रकार मजदूर अपनी श्रम-शक्ति बेचने के लिए मजदूर होता है और जमीन, कारखानों तथा उत्पादन के अन्य साधनों के मालिक मजदूर को केवल उसके

गुजर-बसर के लिए वेतन देकर उसकी श्रम-शक्ति खरीद लेते हैं और इस श्रम-शक्ति का उपयोग मजदूर के वेतन से कहीं अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मार्क्स ने कहा, मजदूर के काम के समय का एक भाग उसकी मजदूरी पैदा करने के काम में आता है तथा दूसरा भाग मालिक के लिए अतिरिक्त-मूल्य पैदा करने के काम में आता है। यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति वर्ग के मुनाफे का स्रोत है।

मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का आधार यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त है।

मार्क्स से पहले भी अन्य ऐसे विचारक हो चुके थे जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी थी और समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार समाजवाद की स्थापना की कल्पना की थी। मार्क्सवादी—लेनिनवादी साहित्य में इन्हीं विचारकों का उल्लेख "काल्पनिक समाजवादियों" के नाम से किया जाता है।

काल्पनिक समाजवादियों की कमजोरी यह थी कि वे पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास के नियमों को समझने में असमर्थ थे। उन्हें नहीं मालूम था कि पूंजीवाद के अन्तर्गत मजदूरी के आधार पर स्थापित गुलामी का सारतत्त्व क्या है और पूंजीवादी व्यवस्था को खतम करने वाली सामाजिक शक्ति कौन सी है। मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए यह भी बतलाया कि इस अर्थव्यवस्था को खतम करने वाली शक्ति कहीं बाहर नहीं है बल्कि इसी व्यवस्था के अन्तर्गत पैदा होती है। वह शक्ति है—मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग ही समाजवाद का निर्माण करेगा। मार्क्स का यह निष्कर्ष इतिहास के विकास के अनुभव के आधार पर निकाला गया था जो यह बतलाता है कि समाज के विकास को अगे ले जाने वाली शक्ति है समाज के विभिन्न वर्गों का संघर्ष। यही मार्क्स का वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त कहलाता है।

इस प्रकार मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के सिद्धान्त न केवल पूँजीवादी समाज की आर्थिक गतिविधि और उनके अन्तर्विरोधों की जानकारी में मदद देते हैं वरन् उनसे यह भी मान्य होता है कि आगे चलकर समाजवाद का निर्माण किस प्रकार होगा।

अर्थशास्त्र का विषय

प्रकृति के नियमों की भाँति समाज की अर्थव्यवस्था के भी नियम होते हैं। प्राकृतिक नियमों और अर्थव्यवस्था के नियमों में इस अर्थ में समानता होती है कि यह दोनों ही अपना अस्तित्व वस्तुगत रूप से रखते हैं। इसका अर्थ है कि यह नियम किसी भी विचारक के मस्तिष्क की उपज नहीं होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनकी जानकारी प्राप्त करना विचारकों का काम है।

इससे साथ ही साथ प्राकृतिक नियमों तथा आर्थिक व्यवस्था के नियमों में एक बड़ा अन्तर भी होता है। अर्थ व्यवस्था के नियम प्राकृतिक नियमों की भाँति व्यापक और स्थायी नहीं होते हैं। एक-अर्थव्यवस्था के नियम दूसरी अर्थव्यवस्था पर नहीं लागू किये जा सकते हैं अर्थात् आर्थिक व्यवस्थाओं के परिवर्तनों के साथ साथ इन नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के रूप में आज की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के नियम सूतकाप की सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था में भिन्न हैं और समाजवादी अर्थ व्यवस्था के नियम पूँजीवाद तथा सामन्तवाद दोनों से ही भिन्न होंगे।

अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक अर्थशास्त्र का विकास एक विज्ञान के रूप में पूँजीवाद के अभ्युदय के साथ साथ हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इससे पहले किसी ने भी समाज की आर्थिक व्यवस्था के नियमों के सम्बन्ध में विचार ही नहीं किया था। भारत में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना उस समय की थी जब भारत का सामन्तवाद अपने प्रारम्भिक

दौर में था और ईसा से तीन शताब्दी पूर्व मौर्य साम्राज्य का उत्थान हो रहा था। इसके बाद अथवा इसके समकालीन स्मृतिग्रंथों ने भी आर्थिक व्यवस्था पर किसी हद तक अपने विचार व्यक्त किये। किन्तु इन ग्रंथों में भारतीय समाज की अर्थ-व्यवस्था के नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के स्थान पर राज्य की ओर से जारी किये जाने वाले आर्थिक कानूनों का उल्लेख था।

यूरोप में जब पूँजीवाद ने जन्म लिया और प्रगति के मार्ग पर बढ़ा लगा तो उस समय खासकर ब्रिटेन में (जो पूँजीवाद की प्राचीन भूमि है) ऐडम स्मिथ, विलियम पट्टी और डेविड रिकार्डों जैसे महान अर्थशास्त्र वेत्त पैदा हुए जिन्होंने नवजात पूँजीवाद के आर्थिक नियमों की वैज्ञानिक खोज की। इन लेखकों के सामने प्रश्न यह नहीं था कि पूँजीवाद की बुराइयों पर किस तरह पर्दा डाला जाय, जैसा कि आजकल पूँजीवाद के पतन के दौर में पूँजीवादी अर्थशास्त्रो करते हैं। उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था को चलाने वाले वस्तुगत नियमों को जानने की कोशिश की। मार्क्स ने अर्थशास्त्र के इन्हीं पण्डितों के विचारों को अपने चिन्तन का आधार बनाया और इन विचारों को और आगे बढ़ाया, उनकी त्रुटियों तथा कमजोरियों को दूर किया। इस प्रकार मार्क्स ने अर्थशास्त्र की सर्वोत्तम प्राप्य सामग्री का इस्तेमाल किया।

मार्क्सवादी अर्थशास्त्र केवल समाज की उत्पादन प्रणाली पर ही विचार नहीं करता है बल्कि उसका विचारणीय विषय यह भी है कि उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत समाज के विभिन्न अंगों में किस प्रकार के सम्बन्ध कायम हैं। इस प्रकार मार्क्स का राजनीतिक अर्थशास्त्र सामाजिक उत्पादन और सामाजिक वितरण दोनों ही के नियमों पर विचार करता है।

श्री जे. वगारहट्टा, श्री रामचन्द्र शर्मा
 श्री हगिंकर शर्मा एवम्
 श्री याज्ञिकराय शर्मा की स्मृति में भेंट

द्वारा :- हर प्रसाद वगारहट्टा
 प्यासे गेहलन वगारहट्टा

दूसरा अध्याय / पूँजीवाद की विशेषताएँ

माक्स ने पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था को मानव-समाज के विकास की एक ऐतिहासिक मजिल के तौर पर माना। इस मजिल पर पहुँचने के पहले मानव-समाज और भी कई मजिलें पार कर चुका था। माक्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त के अनुसार इन अवस्थाओं का वर्णन किया। पूँजीवाद से पहले की अवस्थाओं के नामक्रमशः इस प्रकार हैं— आदिम साम्यवाद, दास-प्रथा और सामन्तवाद।

समाज की आर्थिक व्यवस्थाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालते हुए माक्स ने नतीजा निकाला कि जिस प्रकार अब तक की सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं उसी प्रकार हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अर्थात् पूँजीवाद का भी बदलना अनिवार्य है। भविष्य में पूँजीवाद का अन्त होगा और समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना होगी।

समाज की प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था की अपनी विशेषता होती है जिसके आधार पर अन्य व्यवस्थाओं के साथ उसका विभेद किया जा सकता है। आदिम साम्यवाद के काल में उत्पादन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ था। मनुष्य मिल-जुलकर अपने सामुहिक प्रयास से किसी प्रकार अपनी जीविका निर्वाह करते थे। उनके आपसी सहयोग का आधार था उत्पादन के साधनों का पिछड़ापन। इस अवस्था में स्वाभाविक रूप से लोग अपने सामुहिक उत्पादन का इस्तेमाल सामुहिक ढंग से करते थे। उस समय तक समाज में वर्ग नहीं पैदा हुए थे।

क्रमशः पैदावार के साधनों में उदरति हुई । अथ मनुष्य के लिए सम्भव हो गया कि अपने श्रम के बजाय अपनी जिन्दगी बसर करते-करते अनावा कुछ बनास भी कर सके । यही में दास-प्रथा का आरम्भ होता है । अब गुन्वामों या दासों की महत्ता में फायदा उठाना सम्भव था । आदि-साम्यवाद के युग में दास प्रथा की कोई उपयोगिता न थी इसीलिए उस समय न तो दास होते थे और न दासों के मानिक । किन्तु आदिम साम्यवाद की तुलना में दास-प्रथा अधिक प्रगतिशील थी क्योंकि उन्ने उत्पादन के उन्नत साधनों ने जन्म दिया था और उस दौर में दास-प्रथा उत्पादन के बढ़ाने में मददगार भी थी ।

और अधिक समय बीतने पर दास-प्रथा का स्थान सामन्तवाद ने ग्रहण कर लिया । सामन्तवाद के युग में जमीन पैदावार का मुख्य साधन थी । और सामन्त जमीन के स्वामी थे । इसके अलावा छोटे छोटे दस्तकार और कारीगर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे । उत्पादन की व्यवस्था में अब दासों का महत्व नहीं रहा था और उनकी जगह पर अर्द्ध-दास या भू-दास आ गये थे । यह भू-दास स्वयं खेती करते थे और सामन्तों के खेतों पर भी काम करते थे । लगान के रूप में पैदावार का एक भाग सामन्त को देकर और सामन्त के खेतों पर काम करके यह सामन्तों की दौलत को बढ़ाते थे । आखिरकार सामन्तवाद का भी खात्मा लाजिमी हो गया ।

सामन्तवाद के अन्तर्गत उत्पादन की शक्तियों का बढ़ना जारी रहा । यातायात के साधनों में सुधार हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई । सामन्तवादी व्यवस्था में ही व्यापारियों का एक धनी वर्ग पैदा हुआ । कारखानों की पैदावार बढ़ाने और व्यापार के बन्धनों को दूर करने में इस वर्ग का हित था । सामन्तवाद का ढाँचा अब उत्पादन की शक्तियों के विकास में बाधक था । उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि कारखानों में काम करने के लिए आजादी के साथ मजदूर मिल सकें और छोटे-छोटे सामन्ती राज्यों की सीमाओं पर लगने वाले करों तथा वसूलियावियों से व्यापार को

मुक्त किया जाय। इसलिए तत्कालीन व्यापारियों और कारखानेदारों ने जो आजकल के पूंजीपति वर्ग के पूर्वज कहे जा सकते हैं, सामन्तवाद के खिलाफ आवाज उठायी। इस संघर्ष में सामन्तवाद की पराजय हुई और पूंजीवाद की विजय हुई।

संक्षेप में यही हमारे ऐतिहासिक विकास का क्रम है। जब कोई सामाजिक व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों के विकास में बाधक होने लगती है तो उस व्यवस्था का टूटना अनिवार्य हो जाता है और उसके स्थान पर एक नयी सामाजिक व्यवस्था कायम होती है जिसमें उत्पादन करने वाले मनुष्यों के बीच नये प्रकार के सम्बन्ध कायम होते हैं। मार्क्स के सहयोगी एङ्गल्स ने अपनी पुस्तक 'ऐण्टी-ड्यूरिङ्ग' में इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

“इतिहास का भौतिकवादी विचार (अवधारणा) इस प्रस्थापना से आरम्भ होता है कि उत्पादन, और उत्पादन के बाद उत्पादित वस्तुओं का विनिमय समस्त सामाजिक संरचना का आधार होता है, और अभी तक इतिहास में जितनी समाज-व्यवस्थायें देखी गयी हैं उनमें वस्तुओं के वितरण का ढंग तथा वर्गों अथवा सामाजिक श्रेणियों के बीच के विभाजन का ढंग इस पर निर्भर होता है कि उस समाज में किन चीजों का उत्पादन होता है, किन तरह होता है और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय कैसे होता है। इस दृष्टिकोण में, समस्त सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रान्तियों के मूल कारणों को हमें मनुष्यों के दिमागों में या शाश्वत मूल्य एवं न्याय की मनुष्यों की बेहतर समझ में न खोज कर, उत्पादन तथा विनिमय की प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों में खोजना चाहिए। इन कारणों को हमें प्रत्येक विशिष्ट युग के बर्तमान शास्त्र में नहीं, बल्कि उसके अर्थशास्त्र में खोजना चाहिए। यह बढ़ती हुई समझ कि मौजूदा सामाजिक प्रथायें अबुद्धिसंगत तथा अन्याय-पूर्ण हैं और “विवेक अविवेक बन गया है तथा न्याय अन्याय में रूपान्तरित हो गया है”—यह तो केवल इस बात का प्रमाण है कि उत्पादन तथा विनिमय की प्रणालियों में चुपचाप कुछ ऐसे परिवर्तन हो गये हैं जिनसे यह समाज

व्यवस्था जो पुरानी आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप है, मेल नहीं खाती। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि हमें जिन विपमताओं का पता चलता है, उनको दूर करने के साधन भी न्यूनाधिक विकसित रूप में स्वयं उत्पादन की बदली हुई परिस्थितियों में मंजूर होंगे। इन साधनों को अपने मस्तिष्क से निकाल कर उनका आविष्कार नहीं करना है, बल्कि मस्तिष्क की सहायता से उनको उत्पादन के वर्तमान भौतिक तथ्यों में से खोजकर निकालना है।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की विशेषता क्या है ? पूँजीवाद की विशेषता यही नहीं है कि उत्पादन के साधन कुछ मुट्ठी भर लोगों अर्थात् पूँजीपति वर्ग के हाथ में रहते हैं बल्कि उसकी विशेषता यह है कि वह वस्तु-उत्पादन का सर्वोच्च स्वरूप है। पूँजीवाद में सामाजिक उत्पादन मुख्यतः वस्तु उत्पादन के रूप में होता है।

अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु उस चीज को कहते हैं जो बाजार में बेचने के लिए बनायी जाती है। पूँजीवाद से पहले आर्थिक व्यवस्थाओं में "वस्तु-उत्पादन" को प्रमुख स्थान नहीं प्राप्त था। लोग अधिकांशतः अपने निजी उपयोग के लिए सामान तैयार करते थे। केवल कुछ अतिरिक्त सामान पैदा होता था जिसे बेच कर या बदल कर लोग अपनी जरूरत की अन्य चीजों का प्रबन्ध करते थे।

इसके विपरीत पूँजीवाद में पैदावार मुख्यतः अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए "वस्तुओं" के रूप में होती है। पूँजीवाद की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने बताया है कि पूँजीवाद वस्तु उत्पादन का सर्वोच्च स्वरूप है। पूँजीवाद समाज की वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य की श्रम-शक्ति भी एक वस्तु का रूप धारण कर लेती है, अर्थात् श्रम-शक्ति भी अन्य वस्तुओं की भाँति बिकने लगती है।

तीसरा अध्याय | वस्तु, मूल्य और मुद्रा

सामाजिक उत्पादन की उम्र व्यवस्था को, जिसमें उत्पादन मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होता था, प्राकृतिक अर्थ व्यवस्था (नेचुरल इकॉनमी) कहते हैं। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्राकृतिक अर्थव्यवस्था से भिन्न है। यही उत्पादन का नव्य आवश्यकता की पूर्ति न होकर बाजार में बिखी करना होता है।

वस्तु उत्पादन

इतिहास में वस्तुओं का उत्पादन उनी समय शुरू हो चुका था जब कि आदिम साम्यवाद की व्यवस्था का अन्त हो रहा था। दास प्रथा और सामन्तवाद के युग में वस्तु-उत्पादन जारी रहा किन्तु इन दोनों युगों की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक अर्थव्यवस्था थी। इस काल का वस्तु उत्पादन साधारण वस्तु-उत्पादन (विभिन्न कर्मोंद्वारा प्रोद्योगन) कहलाता है। साधारण वस्तु उत्पादन कारीगरों और दस्तकारों की अपनी मेहनत के द्वारा होता है। वह किसी अन्य से काम लेकर उसका घोषण नहीं करते हैं। वस्तु उत्पादन के लिए दो शर्तें आवश्यक थी— समाज में धर्म का विभाजन और उत्पादन के माध्यमों पर व्यक्तिगत स्वामित्व।

पूँजीवादी व्यवस्था के समाप्त सामाजिक सम्बन्धों को समझने के लिए वस्तु-उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को जानना जरूरी है।

वस्तु के सम्बन्ध में इनका ज्ञान लेना चाहिये कि हमारे धर्म की हर एक पीढ़ावार या उपज को वस्तु नहीं कहा जा सकता है। वस्तु के लिए

मूल्य

साधारण में वस्तुओं का विनिमय किस प्रकार होता है ? यदि में व्यक्ति साधारण में अपने कमाने हुए मूल्य जोड़ी वृद्धि के बदले में कार्य करता होता है तो कब से और कृषि की उदाहरण के विषय आधार पर होता है ? जाहिर है कि यह विनिमय उन वस्तुओं के आधार, या बचत का मूल्य आदि के आधार पर नहीं हो सकता है । उनके आधार, मूल्य और मूल्य आदि में बहुत अन्तर है । हमारे विनिमय के लिए किसी ऐसी चीज के आधार बनाया जा सकता है जो सभी वस्तुओं में सामान्य रूप में मौजूद है विभिन्न वस्तुओं में सामान्यता उसी दृष्टि में पायी जाती है कि उनमें श्रम लगता है । वस्तुओं में लगे हुए इसी श्रम के आधार पर उनका विनिमय मूल्य निश्चित होता है ।

किसी वस्तु के बदले में अन्य कोई वस्तु किन्ती मात्रा में मिलेगी यह सवाल पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुओं में लगे हुए श्रम का अनुपात क्या है । वास्तव में वस्तुओं में लगा हुआ श्रम ही उनका विनिमय मूल्य अथवा मूल्य को जन्म देता है । जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य उन वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है जिसमें कम श्रम लगा होता है ।

किन्तु इतना ही कहना काफी नहीं है कि वस्तुओं का मूल्य उनमें लगे हुए श्रम के अनुसार तय होता है। यदि मिल्फ यही होता तो प्रत्येक उत्पादक अपनी पैदा की हुई वस्तु को अधिक श्रम लगाकर मँहगा बना सकता था और इस प्रकार किसी अकुशल कारीगर को अगर १० गज कपड़ा बनाने में दो दिन लगने लें तो उसे दो दिन की मेहनत के बदले में अन्य वस्तुयें मिल जाती और एक ही दिन में १० गज कपड़ा बनाने वाले कुशल कारीगर को मिल्फ एक दिन की मेहनत के बदले उससे कम वस्तुयें मिलती। या फिर अच्छे औजारों की सहायता से कम समय में और कम मेहनत में किसी वस्तु को बनाने वाले को कम मूल्य मिलेगा और घराब औजारों की मदद से, अधिक समय में तथा अधिक श्रम से उसी वस्तु को बनाने वाले को अधिक मूल्य प्राप्त होगा। किन्तु ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि वस्तु का मूल्य अकने समय देखा जाता है कि उसमें कितना सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम लगा है। वस्तु का मूल्य इसमें निर्धारित होता है कि समाज में उत्पादन की शक्तियों की अवस्था को देखते हुए उसके उत्पादन में सामान्य रूप से या औसतन कितना श्रम लगता है। इन्हीं को सामाजिक रूप में आवश्यक श्रम कहते हैं।

किसी वस्तु के उत्पादन में कितना श्रम लगा है, यह जानने के लिये देखना होगा कि उसके उत्पादन में कितने समय तक मेहनत की गयी है। अतएव हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे हुए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम के समय (सोशली नेसेसरी लेबर-टाइम) द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स के कथनानुसार "सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम का समय वह है जिसकी आवश्यकता किसी वस्तु का उत्पादन की साधारण परिस्थितियों में और औसत दर्जे की कुशलता तथा उस समय में प्रचलित काम के घनत्व (तेजी) के साथ तैयार करने के लिए होती है।" (कैपिटल, प्रथम भाग, पृ० ३९, मार्को, १९६१ ई०)

मूर्तश्रम तथा अमूर्तश्रम

हम पहले देख चुके हैं कि किसी वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं।

वस्तु, मूल्य और मुद्रा

एक तो वह मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसी को वस्तु की उपयोगिता अथवा उपयोगिता-मूल्य कहते हैं। दूसरे प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु के साथ विनिमय हो सकता है या उसे बाजार में बेचा जा सकता है, इसे हम वस्तु का विनिमय-मूल्य कहते हैं। वस्तु के इन्हीं दो स्वरूपों के अनुसार श्रम के भी दो स्वरूप होते हैं।

वस्तुओं के उत्पादन पर गौर करने से मालूम होगा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन के लिए अलग-अलग तरह के औजारों और खास तौर के कारीगरों तथा कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कपड़ा बनाने के लिए एक खास किस्म के औजार और कारीगर चाहिए और कपड़ा बनाने वाले कारीगर अपने शरीर से एक विशेष ढंग से काम लेते हैं। इसके विपरीत लकड़ी की अलमारी बनाने के लिए अन्य प्रकार के कारीगर चाहिए। उनके औजार और काम के तरीके भिन्न प्रकार के होते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के श्रम की आवश्यकता है। बुनकर का श्रम अलग किस्म का है और उससे कपड़े की उपयोगिता प्राप्त होती है। बड़ई का श्रम एक अन्य प्रकार का होता है जिससे अलमारी बनती है। श्रम की यह विभिन्नता ही वस्तुओं को विभिन्न प्रकार का उपयोगिता-मूल्य प्रदान करती है। वस्तुओं की उपयोगिता पैदा करने वाला विभिन्न प्रकार का श्रम अर्थशास्त्र की भाषा में मूर्तश्रम (कॉन्क्रीट लेबर) कहलाता है।

मनुष्य हर किस्म की वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक खास ढंग में अपनी श्रम-शक्ति का व्यय करते हैं अर्थात् प्रत्येक वस्तु में लगा हुआ मूर्तश्रम अलग तरह का होता है। चिन्तु सभी प्रकार के मूर्तश्रम में एक बात समान रूप में पायी जाती है और वह यह है कि हर तरह का श्रम मनुष्य की श्रम-शक्ति का व्यय है। जब हम श्रम को केवल मनुष्य की श्रम-शक्ति के व्यय के रूप में, अर्थात् मूर्तश्रम में प्रयोग करते देखते हैं तो उसे अमूर्त-श्रम (अब्स्ट्रैक्ट लेबर) कहते हैं। अमूर्त-श्रम में ही वस्तुओं का विनिमय-मूल्य

प्रत्यक्ष होता है। विनिमय में देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु में कितना मूर्त-श्रम लगा है।

दो प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए मूर्त-श्रम में गुणात्मक अन्तर होता है, जैसे कि बुनकर और बढ़ई के श्रम में। लेकिन जब हम दो प्रकार की वस्तुओं में लगे हुए श्रम को अमूर्त-श्रम के रूप में देखते हैं तो यह गुणात्मक अन्तर नहीं मिलता है बल्कि केवल परिमाणात्मक अन्तर दिखाई देता है।

जब बाजार में उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान-प्रदान करते हैं तो वे आपस में विभिन्न प्रकार के मूर्त-श्रम का विनिमय करते हैं। वस्तुओं का यह विनिमय परस्पर मूल्य के विनिमय के रूप में प्रकट होता है। इसके पीछे समाज का श्रम-विभाजन छिपा रहता है। वस्तुओं का विनिमय अन्तर्निगन्वा मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को प्रकट करता है।

मूल्य के स्वरूप

आज हम बाजार में रुपया लेकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं और रुपया देकर अन्य वस्तुओं खरीदते हैं। किन्तु समाज में विनिमय की व्यवस्था का हमेशा यही स्वरूप नहीं था। एक समय था जब कि रुपया या अन्य किसी मुद्रा का अस्तित्व नहीं हुआ था। लोग आपस में अपनी वस्तुओं का ही विनिमय करते थे।

विनिमय पर विचार करते समय सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि विनिमय एक ही प्रकार की वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में होता है। मिसाल के तौर पर गेहूँ और खट्टर के बीच में विनिमय होगा। गेहूँ देकर उससे बदले गेहूँ नहीं लिया जाता है। विनिमय में एक वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु निश्चित परिमाण में प्राप्त होती है अर्थात् एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के द्वारा बताया जाता है जैसे कि एक किलोग्राम गेहूँ = एक मीटर खट्टर। जिस वस्तु का मूल्य प्रकट किया जाता है वह सापेक्ष रूप से मूल्य रखती है

और जिस वस्तु के द्वारा मूल्य प्रकट किया जाता है उसमें पर्यायवाची रूप से मूल्य रहता है। हमारे इस उदाहरण में १ किलोग्राम गेहूँ में सापेक्ष रूप से मूल्य (रिलेटिव फार्म आफ वैल्यू) है और १ मीटर खट्टर में पर्यायवाची रूप से मूल्य (इकुइवैलेन्ट फार्म आफ वैल्यू) है।

प्राकृतिक अर्थ व्यवस्था में लोग मुख्यतः अपनी निजी आवश्यकता के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। विनिमय के लिए कभी कभी कोई वस्तु संयोग से वच जाती थी और उसके द्वारा उत्पादक अन्य कोई वस्तु प्राप्त कर लेते थे। यह विनिमय का प्रारम्भिक काल था। इस काल में विनिमय की वस्तुओं में लगे हुए श्रम को पूरी तरह नहीं नापा जाता है। विनिमय अधिकतर संयोग पर निर्भर करता था। अतः विनिमय में वस्तुओं का प्रारम्भिक मूल्य अथवा संयोग जन्य मूल्य, या एक मात्र मूल्य प्राप्त होता था।

क्रमशः समाज का विकास हुआ। पशुपालन के साथ साथ खेती का विकास हुआ। पशु पालन करने वाली और खेती करने वाली जातियों के बीच वस्तुओं का विनिमय आरम्भ हुआ। विनिमय के दौर में लोगों को मालम हुआ कि अनेक वस्तुओं के बीच में लोग एक किसी वस्तु को लेना अधिक पसन्द करते हैं और उसके बदले में अनेक प्रकार की वस्तुयें मिल सकती है। ऐतिहासिक विकास के इस दौर में पशुओं का अधिक महत्व था। इसलिए जिस प्रकार आजकल मुद्रा देकर हम अनेक प्रकार की वस्तुयें खरीद सकते हैं उसी तरह उस युग में पशुओं के बदले अनेक प्रकार की वस्तुयें प्राप्त की जा सकती थी। सबसे पहले पशुओं से ही मुद्रा का कार्य लिया गया।

जब किसी एक वस्तु का मूल्य अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे उस वस्तु के मूल्य का **विस्तारित (एक्सपैंडेड)** अथवा **पूर्ण स्वरूप (टोटल फार्म आफ वैल्यू)** कहते हैं। उदाहरण के रूप में:—

$$१ \text{ भैंड़ } \left\{ \begin{array}{l} = २० \text{ मीटर कपड़ा} \\ = १५ \text{ किलोग्राम अनाज} \\ = १ \text{ ग्राम सोना} \end{array} \right.$$

यहाँ भेद का विभाजित मूल्य उपर्युक्त वस्तुओं से प्रकट होता है ।

इनके विपरीत जब कई वस्तुओं का मूल्य एक ही वस्तु में प्रकट होता है तो उसे मूल्य का सार्वभौमिक स्वरूप (यूनिवर्सल फार्म आफ वस्तु) कहते हैं, जैसे कि —

$$\left. \begin{array}{l} 20 \text{ मीटर कपड़ा} \\ 95 \text{ किलो चाय अनाज} \\ 9 \text{ घाम मोना} \end{array} \right\} = 1 \text{ भेंद}$$

मूल्य के सार्वभौमिक स्वरूप की सोच में वस्तुओं के गुणानुसार (गुणानुसंगत) का प्रचलन हुआ । प्रारम्भ में ही सभी वस्तुओं के मूल्य का सार्वभौमिक रूप में व्यक्त करने वाली किसी एक ही चीज का आविष्कार नहीं हो गया था । समाज की प्रारम्भिक अवस्था में कई वस्तुओं के द्वारा अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य व्यक्त होता था । धीरे धीरे हम उस मंत्रिम पर आ गये जब कि सभी वस्तुओं के मूल्य को व्यक्त करने के लिए सोना या चाँदी जैसी किसी एक वस्तु का प्रयोग होने लगा अर्थात् मुद्रा प्रणाली ने जन्म लिया ।

जब सोने जैसी किसी एक ही वस्तु के द्वारा अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य व्यक्त होता है तो हम उसे मुद्रा के रूप में मूल्य (मनी फार्म आफ वस्तु) कहते हैं । मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जो अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य को व्यक्त करने के सामाजिक कार्य को पूरा करती है । मुद्रा का प्रचलन उस युग में आरम्भ होता है जब कि समाज में श्रम का दूसरी बार बँटवारा हा चुका था और भेती और दस्तकारी अलग अलग हो गये थे ।

मुद्रा

मुद्रा का प्रचलन आज जिस रूप में दिखाई देता है वह ऐतिहासिक विकास का नतीजा है । सबसे पहले उस वस्तु ने मुद्रा का काम किया जिसकी सबसे अधिक माँग थी । अन्त में स्वर्ण की मुद्राओं का प्रचलन हुआ और आज कल मुद्रा के रूप में स्वर्ण को कागज के नोटों ने स्थानान्तरित कर दिया है ।

मुद्रा, चाहे उसका रूप सोने का हो या कागज का, बुनियादी तौर पर वस्तुओं के मूल्य को नापने का काम करती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का वजन जानने के लिए मंग या किन्नाग्राम काम में लाया जाता है और लम्बाई जानने के लिए मीटर या गज का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह मूल्य जानने के लिए मुद्रा का (रुपया, पाण्ड या डॉलर आदि का) प्रयोग किया जाता है। किसी मुद्रा के निश्चित भाग भी होते हैं जैसे कि एक रुपये में सौ पैसे। मुद्रा के इन अंशों का भी प्रयोग मूल्य प्रकट करने के लिए ही होता है।

जब किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तो उसे दाम कहते हैं। मूल्य का नगदी स्वरूप ही दाम है। इम्तिना मुद्रा दाम का मापदण्ड है।

मुद्रा वस्तुओं के संचार का माध्यम होती है। हम बाजार में रुपया लेकर कोई चीज खरीदते हैं। हमने रुपया लेकर व्यापारी अपनी आवश्यकता को कोई वस्तु खरीदता है। इस तरह मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है और उसके बदले में वस्तुओं का हस्तान्तरण होता रहता है। कोई वस्तु जब विक्रेता के हाथ से खरीददार के हाथ में पहुँच जाती है तो उसका संचार (सर्कूलेशन) समाप्त ही जाता है। किन्तु मुद्रा का संचार इस तरह समाप्त नहीं हो जाता। वह वस्तुओं के संचार के माध्यम के रूप में बनी रहती है। मुद्रा की यही मौलिक उपयोगिता है।

चूँकि मुद्रा वस्तुओं के संचार का माध्यम है और मुद्रा के द्वारा अन्य वस्तुयें प्राप्त की जा सकती हैं इसी लिए लोग मुद्रा का संग्रह या जखीरेबाजी भी करते हैं। मुद्रा के संग्रह का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का संग्रह करना यह मुद्रा का दूसरा उपयोग है।

व्यापार और वस्तुओं के संचार में उन्नति के साथ कागज की मुद्रा का भी स्थान बहुत कुछ उधार मुद्रा (क्रेडिट मनी) ने ले लिया है। अब बड़े बड़े व्यापारिक सौदे आम तौर से बैंकों के नोटों या चेकों अथवा हुण्डी (बिल आफ एक्सचेंज) के द्वारा होते हैं। हजारों मील दूर के दो

जों के बोध का व्यापार, हृष्टियों के द्वारा हो जाता है। सामान्य मृगीजन-
 विना माय में स्वयं या मुद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

एक ब्रह्माना या जब कि व्यापारी वस्तुओं के मूल्य का भुगतान निश्चित
 करने की सोचने या धारणा की छटा में बिना करने में। फिर इन छंटों के
 पान पर मुद्रा धारण विभिन्न राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा
 का प्रथम प्रारम्भ में चाहे जो भी हो किन्तु बाद में गिन जाने पर भी वह
 एक निश्चित मूल्य के बराबर मानी जाती है। फिर वाण्य की मुद्रा न
 वस्तुओं की मुद्रा की जगह से ली और लोगों का यह भ्रम दूर हो गया कि
 वस्तुओं का मूल्य सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के द्वारा ही मापा जा
 सकता है। अब सभी देशों में वाण्य के नोटों का ही प्रचलन है और बहुत
 छोटे पैमाने पर इन नोटों की जगह उद्योग-मुद्रा (बैंकों के चेक, हण्टी आदि)
 ने ही ली है नये हो जाने हैं। पूंजीवाद के युग में आने आने मुद्रा ने यह नये
 प्रकल्प ग्रहण किये हैं। उद्योग-मुद्रा ने सोने, चांदी की मुद्रा तथा वाण्य की
 मुद्रा की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है।

विश्वी देश में वस्तुओं के संचार के लिए जितनी मुद्राओं की आवश्यक-
 कता है वह इस पर निर्भर करता है कि जितने नगदी मूल्य की वस्तुओं
 पैदा होती हैं और मुद्रा का चक्कर जितने समय में पूरा होता है। पूर्वी
 वस्तुओं के दाम को मुद्रा के चक्करों में भाग देने से मासूम हो जायगा कि
 सभी वस्तुओं के संचार के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता है। उदाहरण
 के लिए अगर विश्वी देश में प्रति वर्ष १० करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं
 पैदा होती हैं और हर रुपये साल में दस चक्कर पूरे करता है तो उस देश
 की वस्तुओं के संचार के लिए १ करोड़ रुपयों (मुद्रा) की आवश्यकता होगी।
 कुल वस्तुओं के दाम को मुद्रा के चक्करों में भाग देकर आवश्यक मुद्रा की
 संख्या का पता लगाया जा सकता है। वाण्य की मुद्रा भी सोने की मुद्रा
 का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टि में वाण्य की मुद्राओं की संख्या भी
 बही होगी।

अगर किसी देश की सरकार उद्योग नियम का उल्लंघन करने आकर जाता है अधिक मात्रा में कारखानों को मुद्रा जारी कर दे तो इसके फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जायगी। उतनी ही वस्तुओं के लिए अधिक संख्या में मुद्रा देनी होगी। इसी तरह मुद्रा प्रसार में संकुचन आ जाना और निश्चित मुद्रा प्राय वाले लोगों (मजदूरों, नौकरों का लोगों आदि) को हमने हानि होती है।

उद्योग नियम को दृष्टिगत करते हुए कहा जा सकता है कि मुद्रा संस्कार की गति बढ़ने पर अथवा उसके चक्करों की तेजी के बढ़ने पर अपेक्षाकृत कम मुद्राओं के द्वारा वस्तुओं का गन्तार हो जाना है। इसके विपरीत मुद्रा के संस्कार की गति कम होने पर या उसका चक्कर (टर्नओवर) धीमा होने पर अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होती है। आवश्यक मुद्रा का परिणाम इस तरह होता है :—

$$\frac{\text{कुल वस्तुओं का दाम}}{\text{मुद्रा के चक्कर}} = \text{आवश्यक मुद्रा}$$

मूल्य का नियम

पहले बताया जा चुका है कि वस्तुओं का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम के आधार पर निश्चित होता है। एक ऐसे समाज में जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व स्थापित है, यह नियम एक खास ढंग से काम करता है।

व्यवहारिक जीवन में दिखाई देता है कि बाजार में जिस वस्तु की माँग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं और इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हुई और माँग कम हुई तो उसके दाम घट जाते हैं। ऊपरी तौर पर ऐसा मालूम होता कि वस्तुओं की माँग और पूर्ति के द्वारा ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है और मुद्रा के आधार पर सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम का नियम गलत है।

इसी तरह यह भी दिखाई देता है कि जब किसी वस्तु को बेचने के व्यापारियों में प्रतियोगिता होती है तो उस वस्तु के दाम गिर जाते । प्रतियोगिता के अभाव में वस्तुओं के दाम बढ़ भी जाते हैं । अतएव प्रतीत होता है कि वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग और पूर्ति के सम्बन्धों में प्रतियोगिता के द्वारा ही निर्धारित होता है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि माँग और पूर्ति की स्थिति तथा प्रतियोगिता का असर मूल्यों पर काफी पड़ता है । अगर बाजार में किसी वस्तु माँग बढ़ जाती है और उसके दाम बढ़ जाते हैं तो अधिक से अधिक लोग वस्तु का उत्पादन करने लगते हैं । नतीजा यह होता है कि उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और उसे बेचने के लिए व्यापारियों में प्रतियोगिता पैल लगती है जिससे दामों में गिरावट आ जाती है । दाम कम होते ही वह वस्तु के उत्पादन में कमी करने लगते हैं । इस प्रकार प्रतियोगिता द्वारा माँग और पूर्ति के बीच उचित सतुलन कायम हो जाता है और यही साथ ही दाम भी उचित स्तर पर आ जाते हैं ।

पूँजीवादी समाज में, जहाँ उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, मूल्य का नियम इसी तरह स्वतः स्फूर्त ढंग से प्रतियोगिता के रूप में काम में आता है । किन्तु पूँजीवादी समाज में दामों के उतार-चढ़ाव और प्रतियोगिता की उपलब्धता तथा अराजकता के बीच भी मूल्य के नियम का इतना कम नहीं होता है । प्रतियोगिता इस समाज का एक खास गुण है किन्तु प्रतियोगिता के बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि उत्पादक अपनी वस्तुओं की कीमतों में बौटने लगेंगे । वस्तुओं के दामों में एक समय तक के लिए उतार-चढ़ाव होती है किन्तु आम तौर से दामों की एक सामान्य सीमा रहती है । इस सीमा का क्या आधार होता है ? इस सीमा को मूल्य के इसी नियम के द्वारा समझा जा सकता है कि वस्तुओं में लगा हुआ सामाजिक रूप में आवश्यक श्रम ही उनके मूल्य को मौलिक रूप से निर्धारित करता है ।

मूल्य के नियम के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए कि यह नियम वस्तु

उत्पादन का एक आर्थिक नियम है और उसके अन्तर्गत वस्तुओं का बिना उनमें लगे हुए सामाजिक रूप में आवश्यक श्रम के अनुसार होता है। प्रयोगिता की अराजकता के बावजूद वस्तुओं के औसत दाम उनके मूल्य के इतने गिरे घूमते रहते हैं।

मूल्य के नियम का महत्व कई प्रकार में दृष्टिगोचर होता है। नियम वस्तुओं के उत्पादन को नियंत्रण में रखता है। इसी नियम के कारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन का भी मनुष्यन कायम होता है। यदि मूल्य नियम लागू न हो तो किन्हीं उद्योगों में पूँजी का अभाव हो जाय और विभिन्न अन्य उद्योगों में लोग आवश्यकता से अधिक पूँजी लगा दें।

इसके अलावा मूल्य के नियम का एक सबसे बड़ा असर यह पड़ता है कि उत्पादक मूल्य घटाने के लिए अर्थात् वस्तुओं में लगा हुआ सामाजिक रूप में आवश्यक श्रम कम करने के लिए, नवी नयंत्रों (मशीनों) में तथा उन्नत प्राविधिक (तकनीकी) प्रणाली से काम लेने के लिए, बाध्य होते हैं। इस प्रकार अच्छी मशीनों तथा काम के बेहतर तरीकों के जरिए प्रतियोगिता में प्रतिद्वन्दियों को पछाड़ने में मदद मिलती है। पूँजीवादी व्यवस्था में मूल्य का नियम इसी तरह स्वतःस्फूर्त ढंग से काम करता है।

वस्तु का चमत्कार या दैवी स्वरूप

पूँजीवादी समाज में उत्पादकों का परस्पर सम्बन्ध वस्तुओं के द्वारा ही कायम होता है। बाजार में वह एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं बल्कि उनकी वस्तुयें ही एक दूसरे के सामने आती हैं।

यह भी देखा जाता है वस्तुयें जब तैयार होकर उत्पादकों के हाथ से बाजार में आ जाती हैं तो उन पर उत्पादकों का नियंत्रण नहीं रह जाता है। आज अगर किसी वस्तु के बदले में उत्पादक को दस रुपये मिलते हैं तो सम्भव है कि कल उसे उसी वस्तु के लिए केवल पाँच रुपये मिलें। ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु के मूल्य से उत्पादक और उसके श्रम का कोई वास्ता

ही है और वस्तु का अपना पृथक् अस्तित्व है तथा उसका मूल्य अपने आप से निर्धारित होता है। वस्तु पर उत्पादक का नियंत्रण नहीं होना है बल्कि उत्पादक पर वस्तु का नियंत्रण होता है। मार्क्स ने इसी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस प्रकार वस्तु एक "दैवी-स्वरूप" धारण कर लेती है और यह वस्तु का चमत्कार (कमोडिटी फेडिगिज्म) है।

वस्तु के दैवी स्वरूप की भाँति मुद्रा का भी "दैवी स्वरूप" दिखाई देता है। वास्तव में मुद्रा केवल वस्तुओं के मूल्य को नापने का एक साधन है और उसके विनियम का माध्यम है। किन्तु ऊपरी तौर पर देखने से भ्रान्त होता है कि मुद्रा का स्वामी सभी वस्तुओं को खरीद सकता है, इसलिए वस्तुओं पर मुद्रा का अधिकार शायद ही और मुद्रा वस्तुओं के मूल्य की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि वस्तुओं ही मुद्रा के प्रभुत्व को व्यक्त करती हैं। यह मुद्रा का चमत्कार है।

मार्क्स ने वस्तुओं के इस "दैवी-स्वरूप" का पर्दाफाश किया और बताया कि यह पूँजीवादी व्यवस्था के कारण दिखाई देता है जिसमें उत्पादन पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। समाजवाद में सामुहिक स्वामित्व आने पर वस्तुओं का यह दैवी स्वरूप गायब हो जायगा।

तीथा अध्याय | पूंजी, आंतरिक मूल्य और मजदूरी

पहले की सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना में पूंजीवाद की एक विशेषता यह है कि उन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कुछ लोग अन्य लोगों का शोषण करके किस ढंग से सम्पत्तिशाती हो जाते हैं लेकिन पूंजीवाद में यह नहीं दिखाई देता है कि पूंजीपति की सम्पत्ति कैसे बढ़ती है। समाज के एक छोटे से हिस्से की समृद्धि के कारणों के बारे में तरह तरह की धारणाएँ प्रचलित हैं। कहीं इसे दैवी कृपा का सहाय लेकर समझाया जाता है तो कहीं उसे कुछ लोगों की मेहनत और सद्गुणों का परिणाम बताया जाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्री भी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूंजीपतियों का धन व्यापार के द्वारा अथवा वस्तुओं के विनिमय के द्वारा बढ़ता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत भी होता था। वह साधारण वस्तु उत्पादन था जिनके विनिमय के लिए बहुत कम वस्तुएँ तैयार की जाती थीं। उस समय लोग अपनी वस्तु को बेच कर अपनी आवश्यकता के लिए अन्य वस्तुएँ प्राप्त करते थे। संक्षेप में वस्तुओं का गन्धार इस प्रकार होता था :—

वस्तु—मुद्रा—वस्तु

अर्थात् वस्तु के लिए मुद्रा प्राप्त की और मुद्रा में पुनः वस्तु प्राप्त की। लेकिन पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः बिक्री के लिए होता

। यहाँ वस्तुओं का संचार एक नये ढंग से होता है। उत्पादन के स्वामी (A) के स्वामी होते हैं। वह मुद्रा देकर मशीन, कच्चा मान आदि खरीदते और मजदूरों में काम लेते हैं, फिर जो माल तैयार होता है उसे बाजार बेचकर और अधिक मुद्रा (पैसा) हासिल करते हैं। इस तरह पूँजीवादी मात्र में वस्तुओं के संचार की प्रक्रिया मुद्रा से आरम्भ होती है और उसका अन्त भी मुद्रा में होता है:—मुद्रा—वस्तु—मुद्रा।

अब प्रश्न यह है कि वस्तुओं के इस संचार की प्रक्रिया में पूँजीपतियों (A) पैसा किस तरह बँट जाता है? यह नहीं कहा जा सकता कि हर पूँजीपति अपनी वस्तु के अधिक दाम वसूल करता है इसीलिए उसकी सम्पत्ति बढ़ जाती है। यदि यह मान लिया जाय कि प्रत्येक पूँजीपति अपनी वस्तु के दाम १० प्रतिशत अधिक लेता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि हर पूँजीपति (A) विक्रेता की दृष्टियन में तो १० प्रतिशत दाम अधिक मिलते हैं लेकिन खरीदार के रूप में उसे १० प्रतिशत में अधिक देने पड़ने हैं। इस तरह ने-कर हिमाव बराबर हो जाता है। इस तरह पूँजीवाद का विकास नहीं हो सकता।

पूँजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं का संचार मुद्रा—वस्तु—मुद्रा के रूप में होता है। पूँजीपति मुद्रा का स्वामी होता है और मुद्रा के बल पर वह वस्तुओं का स्वामी बनता है तथा इन वस्तुओं को बेचकर वह पहले से अधिक मुद्रा प्राप्त कर लेता है। अतएव यह कहना अधिक सही होगा पूँजीवाद में संचार का नियम है मुद्रा—वस्तु—मुद्रा, अर्थात् अन्त में जब मुद्रा वापस आती है तो उसमें मौलिक मुद्रा का एक भाग जुड़ जाता है। यह भी हो सकता है जब कि पूँजीपति को बाजार में कोई ऐसी वस्तु खरीदने में मिल जाय जिसका मूल्य उसे कम देना पड़े तथा जो अपने मूल्य से अधिक मूल्य पैदा कर सके।

पूँजीपति को बाजार में इस तरह की एक वस्तु मिलती है जिसका प्रथम मूल्य कम होता है, किन्तु जिसके द्वारा अधिक मूल्य का उत्पादन होता है, अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी

भी जरूरी है कि वह किसी तरह अपनी गृहस्थी का पालन कर सके। इस लिए मजदूर का पारिश्रमिक या मजदूरी तय करने में देखा जाता है कि उसे सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए कितने साधनों की आवश्यकता है और उन साधनों का मूल्य क्या होता है। देश और काल के अनुसार जीवन के सामान्य स्तर में अन्तर होता है और इसके अनुसार मजदूरी की दरों में भी अन्तर होता है, परन्तु इस मौलिक सिद्धान्त की व्यवहारिकता बनी रहती है। मजदूरी और काम की शर्तें तय करते समय पूंजीपति देखता है कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति कितने समय तक काम करके अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और इसके बाद कितने समय तक काम करके अतिरिक्त मूल्य की वस्तुयें बनायेगा।

अन्य वस्तुओं की भाँति श्रम-शक्ति के भी दो गुण होते हैं—उसका उपयोगी मूल्य और विनिमय मूल्य। पूंजीपति के लिए यह श्रम-शक्ति अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में उपयोगी होती है और मजदूरी देते समय पूंजीपति देखता है कि इस वस्तु (श्रम-शक्ति) के उत्पादन में कितना श्रम लगता है अर्थात् कितने मूल्य की वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

इस तरह मजदूर का कार्य-दिवस दो भागों में बँट जाता है। एक भाग वह है जो उसकी मजदूरी के लिए आवश्यक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगता है और दूसरा भाग वह है जिसमें अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन होता है। मान लीजिए कि एक मजदूर को प्रतिदिन एक रुपया मजदूरी मिलती है और वह प्रतिदिन १२ घण्टे काम करता है। इन बारह घण्टों में ६ घण्टे के काम में वह जितनी वस्तुयें बनाता है उनसे मालिक को एक रुपया मिलता है जिसे वह मजदूर को दे देता है और उसके बाद के ६ घण्टों में जो एक रुपया का मूल्य बचता है उसे अपने पास रख लेता है। इस हालत में मजदूर के काम के दिन के ६ घण्टों के काम को आवश्यक श्रम (नेसिसरी-लेबर) कहा जायगा क्योंकि मजदूर के जीवन के लिए यह श्रम आवश्यक है। शेष ६ घण्टों का श्रम अतिरिक्त-श्रम (सरप्लस लेबर) हुआ। दूसरे शब्दों में,

उसके कुल थम के ६ घण्टे आवश्यक थम-काल (नेसिसरी-नेबर-टाइम) है और अन्य ६ घण्टे अतिरिक्त थम-काल (सरप्लस नेबर टाइम) है।

पूरे कार्य-काल में अतिरिक्त थम-काल और आवश्यक थम काल का अनुपात मान्य किया जा सकता है किन्तु इन दोनों को बिलकुल अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन से ६ घण्टे अतिरिक्त थम-काल के हैं और कौन से ६ घण्टे आवश्यक थम-काल के हैं। वास्तव में मजदूर के कार्य-काल का प्रत्येक क्षण आवश्यक थम-काल और अतिरिक्त थम काल में बँटा रहता है। मजदूर को पूरे वक्त काम करना पड़ता है और जब वह काम करता है तो अपनी जीविका के साथ साथ मासिक के लिए अतिरिक्त मूल्य भी पैदा करता है।

पूँजीपति का मुनाफा मजदूर के अतिरिक्त थम से पैदा होता है, वह मजदूर के थम से पैदा किया गया अतिरिक्त मूल्य है। पूँजीवादी व्यवस्था का मजदूर ऊपरी तौर से आज़ाद होता है। वह दासों तथा भू-दासों की भाँति प्रत्यक्ष बन्धनों से नहीं जकड़ा होता है। फिर भी मूल्य के अदृश्य बन्धनों ने यह मजदूर बंधा हुआ होना है और अपनी थम शक्ति बँच कर अपने लिए जीविका प्राप्त करता है तथा पूँजीपति को मुनाफा देता है।

पूँजी क्या है ?

जब पूँजीवाद के अन्त की बात की जाती है तो पूँजीपति जगं बडे जोरो से शोर मचाता है कि कम्युनिस्ट भोगों का धन छीनना चाहते हैं और उत्पादन के साधनों को जबरन करना चाहते हैं। इस प्रकार के कारण बहुत से लोग समझने लगते हैं कि पूँजी का तात्पर्य केवल मुद्रा से है अथवा उत्पादन के साधनों से है। इस तरह पूँजीवादी शोषण और पूँजी का वास्तविक स्वरूप दृष्टि से ओझल हो जाता है।

यह सच है कि मुद्रा पूँजी का प्रारम्भिक स्वरूप है और पूँजीवादी समाज में मजदूर का प्रारम्भ मुद्रा में होता है किन्तु मुद्रा अपने आप ही पूँजी का

पूँजी, अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी

का यों कायम रहता है। उममें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके किरीत परिवर्तनशील पूँजी के द्वारा मजदूर की श्रमशक्ति में काम लेकर जो अधिक मूल्य की वस्तुओं की तैयार की जाती हैं और अनिश्चित मूल्य प्राप्त किया जाता है।

पूँजी के इन दोनों स्वभावों को जोड़कर मानस ने पूँजीवादी शोषण को स्पष्ट कर दिया। मानस ने बताया कि मजदूरों के शोषण की स्तर या उसकी दर को जानने के लिए देखना चाहिए कि किसी उद्योग में कौन हुई परिवर्तनशील पूँजी कितनी है और उसके द्वारा कितना अनिश्चित मूल्य प्राप्त किया जाता है। अनिश्चित मूल्य को परिवर्तनशील पूँजी ने भाग देता और उसे १०० में गुणा करने में अनिश्चित मूल्य दर या शोषण की दर साम्य हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी उद्योग में मजदूरों को १० हजार रुपये वेतन देकर उनमें ५ हजार रुपये अनिश्चित मूल्य के रूप में मिलते हैं तो कहा जायगा कि इन उद्योग में अनिश्चित मूल्य की दर

$$\frac{५००० \times १००}{१००००} = ५० \text{ प्रतिशत है।}$$

१००००

अ० मू०

$$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times १०० = \text{अनिश्चित मूल्य की दर।}$$

५० पू०

किसी वस्तु के उत्पादन से कितना अनिश्चित मूल्य प्राप्त हुआ, यह जानने के लिए पहले उसके कुल दामों में से लगी हुई सतत और परिवर्तनशील पूँजी को घटाना होगा। जैसे कि किसी कारखाने में १ लाख रुपये की वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उसमें निम्नलिखित खर्च हुए :

हुई	—	४५ हजार रुपये
मशीन की घिसाई	—	३ हजार रुपये
मकान किराया	—	७ हजार रुपये
मजदूरी	—	३० हजार रुपये
कुल जोड़	—	८५ हजार रुपये

इस वाग्दाने का कुल अतिरिक्त मूल्य = १ माघ—८५ हजार रुपये = १५ हजार रुपये । सूक्ति परिवर्तनशील पूत्री ३० हजार रुपये है

१५०००

इसलिए अतिरिक्त माघ की दर = $\frac{15000}{100} \times 100 = 10$ प्रतिशत

३००००

पूत्रीवादी अर्थशास्त्री अतिरिक्त मूल्य की दर को छिटाने की बड़ी कोशिश करने हैं क्योंकि इसमें पूत्रीपतियों की वृद्ध का गवचा रूप प्रबल हो जाता है । इसलिए पूत्रीवादी अर्थशास्त्र में पूत्री के स्वस्वों का उल्लेख उनके काम के आधार पर नहीं किया जाता है ।

स्थिर पूत्री और चलनशील पूत्री

पूत्रीवादी अर्थशास्त्र में दो प्रकार की पूत्री का उल्लेख किया जाता है । यह विभाजन पूत्रीपतियों के बंती श्रावणों को ध्यान में रख कर किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि गवचा की दृष्टि में बौन ही पूत्री की बड़ा स्थिति है । पूत्री की इन दो श्रेणियों के नाम हैं—(१) स्थिर पूत्री और (२) चलनशील पूत्री ।

स्थिर पूत्री उम्र बढ़ते हैं जो मशीनों, कारखाने की जमीन और अन्य साधन-सामान में लगायी जाती है । यह पूत्री उन उत्पादन के साधनों में लगायी जाती है जिनका पूरा मूल्य किसी वस्तु के मूल्य में शामिल नहीं होता है । मशीनों के द्वारा पूत्रीपति दम-बीग मान तक काम लेता है । इस लिए इस अर्थ में उनमें जा वस्तुपे बनायी जाती है उसके मूल्य के द्वारा धीरे-धीरे पूत्रीपति मशीन के दाम वसूल करता है । पूरी मशीन या फैक्टरी की इमारत के दाम किसी एक वस्तु या एक ही वर्ष के उत्पादन में नहीं जोड़ लिए जाते हैं । यह दाम तमश ५ प्रतिशत या ८ प्रतिशत या कुछ कम-बेश इस वर्ष वसूल किये जाते हैं । इसी लिए पूत्रीपति इस पूत्री को स्थिर पूत्री कहता है ।

पूत्री, अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी

चलनशील पूँजी उम पूँजी को कहते हैं जो कच्चे मान और धन-शक्ति को मर्गदर्शन में समायोजित करती है। मजदूर की दृष्टि में उम पूँजी की वापसी प्रत्येक वर्ष की निजी के मान की मात्रा होती है। प्रत्येक मजदूर उत्पादन में लगे कुल कच्चे मान और धन-शक्ति की शक्तों को उस मजदूर के दाम में शामिल कर लिया जाता है।

पूँजी का उम प्रकार विभेद करने में जोषण का स्वरूप प्रिजात है। जीवित मजदूर का श्रम भी कच्चे मान की श्रेणी में आ जाता है और ऐसा मालूम होने लगता है कि पूँजीपति को जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है उसके उत्पादन में कच्चे मान का भी उतना ही हाथ है जितना कि मजदूर की श्रम-शक्ति का।

शोषण के विभिन्न स्वरूप

हम पहले देख चुके हैं कि मजदूर का कार्य-दिवस दो भागों में बाँटा जा सकता है—आवश्यक कार्य-काल तथा अतिरिक्त कार्य-काल। आवश्यक कार्य-काल में मजदूर अपनी जीविका पैदा करता है और अतिरिक्त कार्यकाल में वह पूँजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। मान लीजिए कि किसी मजदूर का कार्य-दिवस १२ घण्टे का है और उममें ६ घण्टे आवश्यक कार्य-काल के हैं तो शेष ६ घण्टे अतिरिक्त कार्य-काल के हुए। कार्य-दिवस का विभाजन इस प्रकार हुआ—

कार्य-दिवस १२ घण्टा

आवश्यक कार्य-काल ६ घण्टा | अतिरिक्त कार्य-काल ६ घण्टा
कार्य-काल को देखते हुए अतिरिक्त मूल्य की दर इस प्रकार तय होगी :—

$$\frac{\text{अतिरिक्त मूल्य}}{\text{परिवर्तनशील पूँजी}} = \frac{\text{अतिरिक्त कार्य-काल}}{\text{आवश्यक कार्य-काल}} \times १००$$

$$= \frac{६ \text{ घण्टा}}{६ \text{ घण्टा}} \times १०० = १०० \text{ प्रतिशत}$$

पूँजीपति अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक साधनों का इस्तेमाल

करते हैं। अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने का एक सबसे सीधा-सादा तरीका मजदूरों के काम के घण्टे (उनका कार्य-दिवस) बढ़ा देने का होता है। अगर मजदूर के काम के आवश्यक समय में कोई परिवर्तन न हो और उसका कार्य-दिवस अधिक लम्बा कर दिया जाय तो स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त कार्य-बाल बढ़ जाता है। इस तरह पूँजीपति को मिलने वाली अतिरिक्त मूल्य की रकम बढ़ जाती है। मिसाल के लिए यदि मजदूर का आवश्यक कार्य-काल ६ घण्टा ही बना रहे और कार्य-दिवस १२ घण्टे से बढ़ाकर १५ घण्टा कर दिया जाय तो अतिरिक्त कार्य-काल ९ घण्टे हो जायगा। इस तरह अतिरिक्त मूल्य की दर होगी —

$$\frac{\text{अतिरिक्त कार्य-काल ९ घण्टा}}{\text{आवश्यक कार्य-काल ६ घण्टा}} \times १०० = १५० \text{ प्रतिशत}$$

मजदूर का कार्य-दिवस बढ़ाकर जो अतिरिक्त मूल्य की बड़ी हुई रकम मिलती है उसे "पूर्ण अतिरिक्त मूल्य" (एक्सोल्पूट सरप्लस वैल्यू) कहते हैं।

पूँजीपतियों की ओर से इस पूर्ण अतिरिक्त मूल्य को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अगर उनका बस चले तो मजदूर से पूरे चौबीस घण्टे काम लेना शुरू कर दें। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि एक तो मजदूर की शारीरिक दृष्टि से यह अमभव हो जाता है, इसके अलावा नैतिक दृष्टि से भी अन्य कामों के लिए, अपने घर के काम, मनोरंजन आदि के लिए मजदूर को समय चाहिए। पूँजीवाद के प्रारम्भिक दौर में हर देश में काम के घण्टे बहुत ज्यादा थे किन्तु मजदूर वर्ग ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी। अन्त में यह काम के घण्टे कम हुए और आगे बढ़े हुए पूँजीवादी देशों में मजदूरों ने आठ घण्टे का कार्य-दिवस प्राप्त कर लिया।

अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने का एक अन्य तरीका भी होता है जिसमें कार्य-दिवस की लम्बाई वही बनी रहती है लेकिन आवश्यक-धम के समय में

कमी कर दी जाती है। यह तभी हो सकता है जब श्रम की उत्पादन-शक्ति (प्रोडक्टिविटी आफ लेबर) में वृद्धि हो जाय। श्रम की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी मशीनों का प्रयोग इनमें से एक तरीका है। उन्हीं मशीनों के रहते हुए भी उनकी रफ्तार बढ़ा कर या श्रमिक के काम की तेजी अथवा घनत्व बढ़ा कर (इन्टेन्सिटी आफ लेबर) उत्पादन-शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। श्रम की उत्पादन-शक्ति बढ़ने पर मजदूर उतने ही समय में अधिक मूल्य की वस्तुयें पैदा करने लगता है। इस प्रकार उसके आवश्यक श्रम-काल में कमी आ जाती है और अतिरिक्त श्रम-काल अपने-आप बढ़ जाता है। अतिरिक्त श्रम-काल बढ़ने से अतिरिक्त मूल्य भी बढ़ जाता है।

मजदूरों के कार्य-दिवस को बढ़ाये वगैर श्रम की उत्पादन-शक्ति की वृद्धि के द्वारा उनके आवश्यक कार्य-काल को घटाकर पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य की जो रकम प्राप्त करता है उसे "सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य" (रिलेटिव सरप्लस वैल्यू) कहते हैं।

मिसाल के लिए आज एक मजदूर १२ घण्टे प्रतिदिन काम करके २४ गज या मीटर कपड़ा तैयार करता है और उसके काम-में आवश्यक समय के ६ घण्टे हैं। वही मजदूर यदि इतने ही समय में ३६ गज या मीटर कपड़ा तैयार करने लगे तो उसके काम के आवश्यक समय में कमी हो जायगी क्योंकि पूंजीपति केवल १२ गज कपड़ा बेचकर उसकी मजदूरी अदा करेगा जिसे बनाने में अब पहले से कम समय लगेगा। आवश्यक कार्य-काल ६ घण्टे से घट कर ४ घण्टे हो जायगा और अतिरिक्त कार्य-काल ६ घण्टे से बढ़ कर ८ घण्टे हो जायगा। अब अतिरिक्त मूल्य की दर होगी :—

$$\frac{८ \text{ घण्टे}}{४ \text{ घण्टे}} \times १०० \text{ अर्थात् } २०० \text{ प्रतिशत।}$$

सापेक्ष अतिरिक्त-मूल्य में पूंजीवादी शोषण का रूप उतना अधिक प्रत्यक्ष नहीं होता है जितना कि पूर्ण अतिरिक्त मूल्य में।

मजदूरो को वेतन देने के दो तरीके होते हैं—(१) समय के अनुसार या (२) रोजगार मान के अनुसार या पीस रेट से। प्रामाणिक लोग समझते हैं कि काम के अनुसार या पीस रेट से मजदूर को जो वेतन मिलता है उसके रंग उमका सोपना नहीं होता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। रोजगार मान के अनुसार वेतन निश्चित करने समय पूँजीपति पहले से ही हिताववाला होता है कि एक श्रमिक मजदूर एक दिन में कितना मान रोजगार करता है और उस मान में कितना मूल्य प्राप्त होता है। इस तरह मजदूर जिस मूल्य का उत्पादन करता है वही मान की दर में वेतन तय करवा का आधार है। पूँजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य की व्यवस्था करने के बाद मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार के वेतन से मजदूर समझता है कि उसे उसके श्रम का पूरा मूल्य मिल रहा है और अधिक कामाने के लिए वह और भी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। पूँजीपति इन मजदूरों की ओर से अपेक्षाकृत अधिक निश्चित हो जाता है क्योंकि उसे मान्य है कि मजदूरों का सालाना मजदूर को और अधिक अतिरिक्त-मूल्य पैदा करने के लिए बाध्य करेगा।

अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के यह तरीके सभी पूँजीपतियों द्वारा काम में लाये जाते हैं। आम तौर पर किसी वस्तु की लागत के दाम सभी पूँजीपतियों के लिए एक ही समान पड़ते हैं और उनको प्राप्त होने वाले अतिरिक्त मूल्य की दर में भी अन्तर नहीं होता है। फिर भी पूँजीपति व्यक्तिगत रूप से अपने श्रम के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मुनाफा कामाने का कोई भी वादा हाथ में नहीं लाते देते हैं। इसके लिए वह अपनी वस्तुओं का उत्पादन में लगे हुए श्रम में खास तौर से काम करते हैं। वह ऐसी मशीनें लगाते हैं जो अन्य पूँजीपतियों की मशीनों की तुलना में तेजी हों और जिनके द्वारा कम दामों में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो सके। इस प्रकार व्यक्तिगत पूँजीपति जो अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हैं उसे "विशेष अतिरिक्त मूल्य" (एक्स्ट्रा मरचन्स वॉल्यू) कहते हैं।

विशेष अतिरिक्त मूल्य का पूँजीवादी समाज में महत्वपूर्ण स्थान है।

इससे पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में नवीन, मुघरे हुये तरीकों को ज़रूरी करने में मदद मिलती है। जब कोई पूंजीपति विशेष अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने लगता है तो अन्य पूंजीपति भी उसके तरीकों की नकल करते हैं और अच्छी मशीनें लगाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो पूंजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व का अनिवार्य परिणाम है। जिन पूंजीपतियों के पास नई मशीनें होती हैं वह चाहते हैं कि अन्य पूंजीपति नवीन आविष्कारों की सुविधा से वंचित रहें। इसके लिए वह इन आविष्कारों को अपने लिए सुरक्षित कर लेते हैं। इस तरह बड़े बड़े पूंजीपति अन्य छोटे छोटे पूंजीपतियों को बर्बाद करके अपने पास अधिकाधिक सम्पत्ति केन्द्रित कर लेते हैं। पूंजीवादी समाज में अन्ततोगत्वा विशेष अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने की लालसा उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधा हो जाती है।

पूंजीवाद का विकास

पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का जो विकसित रूप आज हमें दिखाई देता है वह एक ही दिन में नहीं पैदा हुआ। उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति क्रमशः हुई। सबसे पहले मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था बल्कि उत्पादन की वृद्धि मनुष्यों के साधारण सहयोग के द्वारा प्रारम्भ हुई। पूंजीपतियों ने एक ही स्थान पर बहुत से लोगों को एकत्रित करके उनसे किसी एक वस्तु का उत्पादन करवाना शुरू किया। व्यवहार में मालूम हुआ कि यदि एक ही वस्तु को बनाने वाले कई कारीगर एक स्थान पर काम करते हैं तो उनके उत्पादन की रफ्तार बढ़ जाती है। यह पूंजीवादी साधारण सहकारिता थी।

पूंजीवादी साधारण सहकारिता में प्रत्येक कारीगर अलग अलग अपनी वस्तु तैयार करता है किन्तु अनेक कारीगर एक ही स्थान पर काम करते हैं। इससे वस्तुओं की पैदावार बढ़ने के साथ साथ मकान किराया, रख-रखाव, सफाई, प्रकाश आदि का व्यय भी कम हो जाता है। क्रमशः उत्पादन प्रक्रिया में यह भी मालूम हो जाता है कि कौन सा मजदूर वस्तु के उत्पादन की

किस प्रक्रिया की अधिक जानकारी रखता है तथा उत्पादन-प्रक्रिया के किसी विशेष अंग को किस तरह अधिक सुगमता के साथ पूरा किया जाता है। इस तरह श्रम-विभाजन का जन्म होता है। श्रम-विभाजन के आधार पर कारखानों (मैन्यूफैक्चर्स) का विकास होता है।

यही कारखाने आगे चलकर पूंजीवादी फैक्टरी में विकसित हो जाते हैं। इन कारखानों में मशीनों से काम नहीं होता था बल्कि औजारों से काम लिया जाता था। औजार और यंत्र (मशीन) में अन्तर है। औजार का इस्तेमाल करने के लिए हाथ की जरूरत होती है, जैसे कि बडई की आगी या दर्जी की सुई एक औजार है। मशीन अथवा यंत्र में हाथ का काम भी एक पुर्जा करने लगता है। मिलाई मशीन में सुई को पकड़ने और चलाने के लिए, कपड़ा खिमकाने के लिए तथा डोरे को खींचने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ केवल कपड़े की सिलाई की दिशा नियंत्रित करता है। इसी तरह लकड़ी फाड़ने की आग मशीनें भी बडई की आगी से भिन्न हैं।

कारखानों में श्रम के विभाजन के कारण मशीनों को बनाने में आसानी हुई, वही ऐसे मजदूर मिले जो मशीनों को चला सकते थे। धीरे-धीरे मशीनों की बनावट में सुधार हुआ और उनका व्यवहार करना अधिक आसान हो गया। भाप के इंजनों और बिजली के प्रयोग में एक साथ कई मशीनों का चलाना सम्भव हो गया। आज के विशाल पूंजीवादी कारखाने या उद्योग-गृह जिनमें मशीनों का एक भिन्न-भिन्न उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, इसी तरह सामने आये।

पूंजीवादी फैक्टरी और मशीनों ने उत्पादन में लगे हुए मनुष्यों (मजदूरों) का रूप बदल दिया। अब उनकी व्यक्तिगत दक्षता का महत्व घट गया। इसी प्रकार शक्ति की भी उतनी आवश्यकता नहीं रह गयी। थोड़े ही दिनों में अब काम सीखकर एक मजदूर तैयार हो जाता और पुरुषों का काम स्त्रियाँ तथा बच्चे भी कर सकते थे। इस प्रकार मशीनों के आविष्कार में पुराने कारीगरों के पैरों के नीचे से जमीन खिमक गयी। फैक्टरी के भीतर भी अब मनुष्य अपनी दक्षता, शक्ति और अनुभव के आधार

पर औजारों को नहीं चलाता था बल्कि मनुष्य की कार्य-कुशलता इसमें ही कि वह किस हद तक मशीन के साथ कदम मिलाकर चल सकता है। पहले औजारों को मनुष्य चलाता था अब मनुष्य मशीन के अनुसार चलने लगा।

फैक्टरी (यांत्रिक कारखानों) के चलने से पूरे समाज की उत्पादन व्यवस्था पर असर पड़ा। मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, लोहे के लिए कोयला चाहिए, कोयला निकालने के लिए अन्य मशीनें चाहिए, कोयले को ढोने के लिए रेलें चाहिए—उस प्रकार तमाम उद्योग-धन्धे एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं। उत्पादन का स्वरूप सामाजिक हो गया—पूरे समाज की दृष्टि से भी और अलग-अलग फैक्टरियों के भीतर काम की दृष्टि से भी, किन्तु उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत रहा। यही पूंजीवादी समाज का सबसे बड़ा अन्तर्विरोध है। यह अन्तर्विरोध उत्पादन की शक्तियों की प्रगति में बाधक है। इसलिए कम्युनिस्ट मांग करते हैं कि इस अन्तर्विरोध को खतम किया जाय और सामाजिक उत्पादन पर समाज का स्वामित्व स्थापित किया जाय।

मजदूरी के विभिन्न स्वरूप

पूंजीवादी शोषण को अच्छी तरह समझने के लिए मजदूरी के स्वरूपों को कुछ विस्तार के साथ देखना होगा। अभी तक हम इतना कह चुके हैं कि पूंजीपतियों का यह दावा गलत है कि मजदूर को उसके श्रम के दाम दिये जाते हैं। जिस समय मजदूर को पूंजीपति नौकर रखता है उस समय उसके श्रम का कहीं पता नहीं रहता है। मजदूर के पास केवल उसकी श्रम-शक्ति रहती है। पूंजीपति इसी श्रम-शक्ति का सौदा तय करता है।

मजदूर को उसका वेतन तब मिलता है जब कि वह कुछ समय तक काम कर लेता है। श्रम-शक्ति का सौदा अन्य वस्तुओं की भाँति नहीं पूरा होता है जिनके दाम पहले दिये जाते हैं या वस्तु के विनिमय के साथ ही दिये जाते हैं। श्रम-शक्ति का मालिक मजदूर पहले अपनी वस्तु पूंजीपति को देता है फिर बाद में पूंजीपति से उसके दाम प्राप्त करता है। यह दाम

बर्फी समय के समय के अनुसार मिलने है और बर्फी मजदूर द्वारा बनाई गयी बस्तुओं के परिमाण के अनुसार । इन दोनों ही प्रकार की मजदूरी का सम्बंध बिना का सूत्र है ।

बनाई गयी बस्तुओं पर आयाजित धीम-रेट मजदूरी की प्रथा पहले नहीं थी । प्रारम्भ में निकट समय के अनुसार बेगन मिलता था । अब बनाई हुई बस्तुओं के आधार पर मजदूरी देने का प्रचलन अधिष्ठ है । इस प्रकार की मजदूरी में लेगा प्रतीत होगा है कि मजदूर को उसके धम के पूरे दाम मिल रहा है । वास्तव में मजदूर को बेचम उमकी धम-गवित का मूल्य मिलता है और धम-गवित के नगदी (मुदा-रुप में) मूल्य का नाम ही मजदूरी है । मजदूरी के रूप में मजदूर को उसकी धम-गवित के उत्पादन में लग हुआ मूल्य ही मिलता है ।

लेगा बस्तुओं के अनुसार मजदूरी देने समय भी पूजोपति पहात ग देव लेता है कि एक दिन में एक बस्तु का बिली माता में किमी बस्तु का निर्माण कर सकत है । उसी हिसाब में वह उम बस्तु के लिए मजदूरी की दर नियत करता है । पहले एक उदाहरण के द्वारा हम देख चुके है कि किस प्रकार आरम्भिक धम-राम के घटन में अनिश्चित मूल्य में वृद्धि हो जाती है । यह नियत जग भी लागू होगा है । उदाहरण के लिए यदि एक मजदूर को १२ घण्टे की मजदूरी के लिए २ रुपये प्रतिदिन मिलते है तो बस्तुओं के अनुसार मजदूरी तब करले समय मानिक यह देगेगा कि वह १२ घण्टे में कितने मज करदा बुनता था । यदि वह १२ घण्टे में २० मज करदा बुनता था और अपने आय समय (१ घण्टे में) अपनी जीविका के माधन हासिल कर लेता था तो पूजोपति के लिए हम मज करदे का मूल्य अतिरिक्त मूल्य के रूप में बच रहता था । अब भी पूजोपति का प्रयास यही होगा कि उमक पास १० मज करदे का मूल्य बचा रहे और मजदूर के आवश्यक धम-गाल में वृद्धि न हो । इसलिए वह इस मजदूरी की पूरी बस्तुओं के दामों में पैसा देगा और अर्थात् मजदूर को २० मज करदे के लिये २ रुपये मजदूरी देगा अर्थात् प्रति मज २/२० देगा या १० पैसे मजदूरी मिलगी ।

पूजी, अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी

पूँजीपति इस मजदूरी को घटाने की भी कोशिश करने हैं। मजदूरी तय करने के अन्य नये तरीके भी ईजाद कर लिए गये हैं। पूँजीपति किसी अच्छे मजदूर और कुशल मजदूर को काम में लगाकर देखते हैं कि वह एक दिन में कितनी वस्तुएँ बना सकता है। इसी आधार पर वह तय करते हैं कि एक दिन में इतनी मात्रा में किसी वस्तु के बनाने वाले को निम्नतम कितनी मजदूरी मिलेगी। पूँजीपति यह भी कहते हैं कि इसके ऊपर काम करने वाले को अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। परिणाम स्वरूप हर मजदूर अपने काम के उस अंश को पूरा करने के लिए जो तोड़ कोशिश करता है जो निम्नतम मजदूरी हासिल करने के लिए आवश्यक है। जो मजदूर इतना काम नहीं कर पाते हैं उनके लिये मजदूरी की दर अलग होती है और वह तुलनात्मक दृष्टि से और भी कम होती है।

मशीनों की रफ्तार तेज करके भी पूँजीपति मजदूर से अधिक काम लेता है। इस ढंग से वह काम के घंटे बढ़ाये वगैर ही अधिक मुनाफा कमा लेता है। लेकिन पूँजीपतियों ने एक श्रृंखला की नई तरकीब निकाल ली है। वे मजदूरों को अपने मुनाफे का "साझेदार" बनाते हैं। इस साझेदारी की योजना में मजदूर से कहा जाता है कि उसे अन्य कारखानों की अपेक्षा दैनिक वेतन तो कम मिलेगा लेकिन साल के आखिर में जो मुनाफा होगा उसका एक अंश मजदूरों में बाँट दिया जायगा। फलस्वरूप हर मजदूर अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे मुनाफे के अंश के प्राप्त होने का लालच रहता है। मजदूरों में भ्रम पैदा होता है कि वे वास्तव में उद्योगपतियों के साझेदार हैं और मालिक से उनके हितों का कोई संघर्ष नहीं है।

पूँजीवादी देशों में मजदूरों की आपसी प्रतियोगिता का इस्तेमाल उनके वेतन की दरें गिराने के लिए किया जाता है। वेकार मजदूरों की फौज हमेशा इस काम में शोषकों की सहायता करती है क्योंकि वह लोग कम मजदूरी पर काम में लगे हुए मजदूरों का स्थान लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस काम में वेकार मजदूरों के साथ साथ पूँजीपति वर्ग स्त्रियों

शोर बच्चों का भी इस्तेमाल करता है। मशीनों की उन्नति के साथ स.प स्त्रियों और बच्चों के लिए भी एक वयस्क पुद्ग के बराबर काम करना सम्भव हो जाता है। फिर भी स्त्रियो और बच्चो को उनके काम के लिए मजदूरी कम दी जाती है। बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी का सिद्धान्त पूंजीपति लागू नहीं करते हैं।

नाम की मजदूरी : वास्तविक मजदूरी

मजदूर को जो मजदूरी मिलती है उसे दो प्रकार से देखा जा सकता है। पूंजीवाद के प्रारम्भिक काल में मुद्रा के रूप में मजदूरी कम मिलती थी। सामान के रूप में मजदूरी देने का रिषाज अधिक था। लेकिन अब नगदी (मुद्रा के रूप में) मजदूरी का प्रचलन है। अतः पहले हमें यह देखना चाहिए कि किसी मजदूर को नगदी मजदूरी कितनी मिलती है। मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी को "नाम की मजदूरी" (नामिनल वेज) कहते हैं।

मजदूरी की हालत सही तौर से जानने के लिए केवल इतना जानना काफी नहीं है कि उसे नाम की मजदूरी कितनी मिलती है। अर्थात् उसे कितने रुपये प्रतिदिन या हर महीने मिलते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि इस नगदी मजदूरी से जीवन की आवश्यक वस्तुयें किस हद तक प्राप्त की जा सकती हैं। मजदूरी को अब जीवन की आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तित करके देखते हैं तो उसे "वास्तविक मजदूरी" (रियल वेज) कहते हैं।

नाम की मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के स्तरों में काफी अन्तर होता है। यदि नाम की मजदूरी में वृद्धि हो जाय तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि मजदूरी की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो गयी है। अवसर ऐसा होता है कि नाम की मजदूरी में जितनी वृद्धि होती है उससे कहीं अधिक वृद्धि वस्तुओं के दामों और सरकारी करों आदि में हो जाती है, जिससे मजदूर का जीवन स्तर ऊँचा नहीं उठ पाता है बल्कि कभी कभी नीचे गिर जाता है। हमारे देश का ही उदाहरण काफी है, जहाँ आज नगदी के रूप

में मजदूरों को पहले की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है लेकिन जहाँ वास्तविक मजदूरी १९३९ ई० की वास्तविक मजदूरी से आगे नहीं जा सकी है ।

पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जाते हैं । पूँजीवादी देशों में शिक्षा, चिकित्सा आदि का खर्च भी बढ़ता जाता है और टैक्सों में वृद्धि होती है । इसलिए नाम के वेतन में वृद्धि के बावजूद वास्तविक वेतन में वृद्धि नहीं होती है । वास्तविक मजदूरी का अन्दाजा लगाने के लिए देखना चाहिए कि नाम की मजदूरी कितनी मिलती है, खपत की आवश्यक वस्तुओं के दामों का स्तर क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह पर कितना खर्च होता है, मकान-किराया और टैक्स कितने देने पड़ते हैं तथा अन्य ऊपरी खर्चों का क्या हाल है ।

पूँजीपति वर्ग पूरी ताकत से कोशिश करता है कि मजदूरी में वृद्धि न होने पाये । वह उचित मजदूरी के लिए मजदूरों के आन्दोलनों को कुचलने की चेष्टा करता है और इसके लिए राजसत्ता के यंत्र—नीकरणाही और पुलिस का प्रयोग करता है तथा प्रचार के साधनों (समाचार पत्रों, रेडियो आदि) से भी इस काम में मदद लेता है । पूँजीपति वर्ग की इन कोशिशों के बावजूद मजदूर वर्ग का आन्दोलन आगे बढ़ता जाता है । मजदूर अपने संगठनों (ट्रेड-यूनियनों) की शक्ति के बल पर पूँजीपति वर्ग की संगठित शक्ति का जवाब देता है और अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है ।

कम्युनिस्ट इस संघर्ष को अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इन संघर्षों के दमियान मजदूर वर्ग को यह अनुभव होता है कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त करके ही पूँजीवादी शोषण से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ।



1 अध्याय | पूंजी का संचय तथा पूंजी का द्वैहिक अनुपात

पहले बहा जा चुका है पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में पूंजीपति उत्पादन साधनों को खरीदता है और उनके साथ साथ मनुष्यों की श्रम-शक्ति को खरीदता है। पूंजीपतियों को जो लाभ या मुनाफा प्राप्त होता है वह दूरो द्वारा उत्पादित अतिरिक्त मूल्य है। इसी अतिरिक्त मूल्य पर वेपति वर्ग की सम्पन्नता निर्भर करती है।

वरोत्पादन—साधारण तथा परिवर्द्धित

अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने की लालसा ही पूंजीपति वर्ग को उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई पूंजीपति अपनी मौलिक पूंजी को अतिरिक्त मूल्य द्वारा बढ़ाये और उसे अपने काम में लाना शुरू कर दे तो थोड़े ही दिनों में वह ताल हो जायगा। मूल पूंजी से यदि व्यय होता रहे तो किसी भी कारोबार चलना असम्भव है। अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन की प्रक्रिया को जारी राना न केवल पूंजीपति वर्ग के निजी व्यय के लिए आवश्यक है बल्कि शीवादी उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए भी जरूरी है।

उत्पादन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण लें। मान लिये कि किसी कारखाने में एक पूंजीपति ने १ लाख रुपये उत्पादन के साधनों में (मशीनों, कच्चे माल आदि में) सतत पूंजी के रूप में लगा रखे और वह हर साल २० हजार रुपये मजदूरी के रूप में देता है। यदि

उसकी इस परिवर्तनशील पूंजी पर १०० प्रतिशत का अतिरिक्त मूल्य मिले तो उस पूंजीपति को प्रतिवर्ष २० हजार रुपये अतिरिक्त मूल्य के रूप में मिलेंगे। यदि वह पूंजीपति इस २० हजार रुपये की आय की सीमा के भीतर ही अपने व्यक्तिगत खर्चों को रखता है तब तो उसका काम चलता अन्यथा वह दिवालिया हो जायगा।

इतना ही नहीं, अपने निजी व्यय के अलावा उस पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य की रकम में से एक हिस्सा हर साल बचाकर रखना भी पड़ेगा ताकि वह कारखाने की पैदावार को चालू रखने के लिए लगाया जा सके। सभी जानते हैं कि पूंजीपति ने अपनी एक लाख की सतत पूंजी से जो मशीनें खरीदी थीं वह हमेशा के लिए काम नहीं दे सकती हैं। आगे चलकर नवी मशीनों का आविष्कार होगा और यदि उक्त पूंजीपति इन अच्छी और अधिक कीमती मशीनों को नहीं खरीदेगा तो अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के सामने प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकेगा। इसका अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया को आगे जाने के लिए मूल पूंजी में वृद्धि होनी चाहिये।

उपर्युक्त उदाहरण से उत्पादन प्रक्रिया के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। पहला वह है जिसमें उत्पादन के साधनों तथा श्रम-शक्ति में लची हुई पूंजी बनी रहती है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतिरिक्त मूल्य की रकम मिलती है उसे पूंजीपति अपने निजी काम में लाता है। इस तरह पूंजी की लागत और वस्तुओं के उत्पादन के परिणाम को जैसे का तैसा रखते हुए जो उत्पादन होता है और जिसके अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति अपने निजी व्यय के काम में लाता है उसे साधारण पुनरोत्पादन (सिम्पल रिप्रोडक्शन) कहते हैं।

साधारण पुनरोत्पादन पूंजीवाद के विकास के आरम्भ में अधिक होता था जब कि पूंजीपति थोड़े से मजदूरों से काम करवाता था, बड़े बड़े कारखाने चालू नहीं हुये थे और बड़ी मशीनों का प्रचलन नहीं था। उस समय पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य भी कम मिलता था। इस अतिरिक्त मूल्य को

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के विकास को इस तरह माफ़ तोर में समझा जा सकता है। अतिरिक्त मूल्य के द्वारा ही पूँजी का संचय होता है। धाज जो बड़े-बड़े पूँजीपतियों के कल-कारगाने दिग्गर्ह होते हैं वह उस पूँजी के आधार पर नहीं बन सकते थे जो पूँजीपतियों ने जुल्बत में लगायी थी। पूँजीपतियों की सारी फिजूल गतिवियों और ऐज-आराम के बावजूद उनकी पूँजी का आकार बढ़ता गया। इसके मूल्य में अतिरिक्त मूल्य है—मजदूरों का अतिरिक्त श्रम है। यदि आज सरकार की ओर से इन कारखानों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाय तो पूँजीपतियों को अधिक जिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जिनकी मूल पूँजी लगायी थी उससे कहीं अधिक रुपया बीसों वरों में ग्या पी चुके हैं, वास्तव में राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार को मजदूरों के पैश किये हुये अतिरिक्त मूल्य की यह संवित रकम ही मिलेगी।

पूँजी का दैहिक अनुपात

माक्स द्वारा बताया गये पूँजी के दो स्वरूपों—सतत पूँजी और परिवर्तनशील पूँजी का उल्लेख किया जा चुका है। इसी के आधार पर माक्स ने पूँजी के दैहिक अनुपात (आर्गेनिक कम्पोजीशन) का वर्णन किया और बताया कि पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजी का दैहिक अनुपात लगातार अधिक ऊँचा या भारी होता जाता है और पूँजी के दैहिक अनुपात के ऊँचा होने से भी श्रमिक वर्ग के शोषण में वृद्धि होती है।

पूँजी के दैहिक अनुपात का अर्थ क्या होता है? पूँजी के दैहिक अनुपात से हमारा तात्पर्य है किसी उद्योग में लगी हुई सतत पूँजी और परिवर्तनशील पूँजी के बीच के अनुपात से। जिस पूँजी का सतत भाग जितना ही बड़ा होता है उसका दैहिक अनुपात उतना ही ऊँचा होता है। उच्चतर दैहिक अनुपात (हाइयर आर्गेनिक कम्पोजीशन) की पूँजी का अर्थ है सापेक्ष रूप से अधिक सतत अंश वाली पूँजी। इसके विपरीत यदि पूँजी

नहीं होगी है उन्हें पूंजीवादी अर्थशास्त्री "अतिरिक्त जनसंख्या" का नाम प्रदान करते हैं। उनका प्रयाग पूंजीवादी अर्थशास्त्र के विकास के नियम पर पर्दा डालकर यह दिखाने का होता है कि जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता है। इसके बाद जनसंख्या को कम करने के लिए जनसंख्या को कम करने का नारा दिया जाता है।

ऐसे ही एक अर्थशास्त्री मानवस्य मादन है। उनका कथन यह कि जन आवादी अधिक बढ़ जाती है तो उद्योग, ग्राम-शिक्षा आदि का उत्थान नहीं हो पाता है। फलस्वरूप लोगों में मला सारिदी और बीमारियाँ फैलती हैं या फिर युद्ध होने हैं। इन युद्धों और बीमारियों के कारण जनसंख्या कम हो जाती है, संतुलन फिर से कायम हो जाता है और लोगों की हालत सुधर जाती है। इस विचारधारा के धनुवार युद्धों और बीमारियों के संसार के लिए एक बख्शान समझना चाहिये क्योंकि उनमें प्राकृतिक तौर पर लोगों की दशा में सुधार हो जाना चाहिए। पूंजीवादी सरकारें किसी न किसी रूप में मानवस्य के सिद्धान्त को मानती हैं। उनके नेता अक्सर अतिरिक्त जन-संख्या को बान्त किया करते हैं और सलाह देने रहते हैं कि संतति-निग्रह या परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या को कम करना चाहिए। भारत सरकार भी इसका अनाद नहीं है। उसकी योजना में परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस समस्या के बारे में मार्क्स ने लिखा है :—

"जितना ही अधिक सामाजिक सम्पत्ति होती है, क्रियाशील पूंजी होनी है, उसकी वृद्धि की व्यापकता और शक्ति होती है और इसके फलस्वरूप सर्वहारा का पूर्ण आकार भी जितना ही अधिक बड़ा होता है तथा उसकी श्रम की उत्पादकता जितनी अधिक होती है उतनी ही ज्यादा औद्योगिक सुरक्षित सेना होती है। जिन कारणों से पूंजी की विस्तार-शक्ति का विकास होता है, उन्हीं कारणों से उमे प्राप्य श्रम-शक्ति का भी विकास

होता है। अतएव सम्पत्ति की निहित शक्ति (ऊर्जा) के साथ साथ औद्योगिक सुरक्षित सेना का आकार भी सापेक्ष रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन सक्रिय श्रमिकों की सेना के अनुपात में यह सुरक्षित सेना जितनी अधिक बड़ी होती है, उतना ही अधिक बड़ा उस एकत्रित अतिरिक्त जनसंख्या का आकार होता है जिसकी दरिद्रता उसके श्रम के कण्टों की तुलना में उल्टे अनुपात में घटती बढ़ती रहती है। अन्त में, गरीब-और तबाह मजदूरों का वर्ग जितना ही अधिक विस्तृत होता है और औद्योगिक सुरक्षित सेना जितनी ही अधिक बड़ी होती है उतनी ही अधिक सरकारी तौर पर गरीबी होती है। यह पूंजीवादी सचय का विद्युत् सामान्य नियम है।" ("कैपिटल" प्रथम भाग अंग्रेजी संस्करण, मास्को, पृ० ६४४)

इस बेकारों और दरिद्रों की सेना में कई प्रकार के लोग रहते हैं। बड़े में बड़े पूंजीवादी देश में लागों की संख्या में ऐसे मजदूर मिलेंगे जो पूरी तरह बेकार है। सन् १९६२ में विश्व के सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी देश मधुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से बेकार लोगों की संख्या ४० लाख थी। इसके अलावा ऐसे मजदूर या छोटे छोटे कारीगर होते हैं जिन्हें कभी काम मिलना है और कभी नहीं मिलना है। यह आशिक रूप से काम करते हुए किसी तरह गुजर बसर करते हैं। मानसं ने इनका नामकरण करते हुए कहा है कि यह "शक्तिहीन" (स्टेगनेन्ट) सुरक्षित सेना है। पूंजीवाद के विकास के साथ हर साल देश में ऐसे ही मजदूर और छोटे किमान पंदा होते रहते हैं जिनके पास जीविका के साधन नहीं होते हैं और जो शहरों में जाकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मानसं के शब्दों में यह "गुप्त" (लैटेन्ट) सुरक्षित सेना है। अन्त में हमें भिखमगों और आवारा लोगों की फौज को भी नहीं भूलना चाहिए। यह भी अतिरिक्त जनसंख्या के अन्तर्गत आते हैं।

पूंजीवादी सचय का पूरा इतिहास इसका साथी है। उसके फल-स्वरूप उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित होते जाते हैं।

पूंजी अतिरिक्त मूल्य और मजदूरी

पूंजीवाद का प्रारम्भ सामन्तवाद के युग के छोटे छोटे वस्तु उत्पादकों से हुआ था। कमजोर यह छोटे वस्तु उत्पादक भाग्यहीन होने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े कल-कारखानों ने ले ली। इन कारखानों में मान पूंजी का आकार बढ़ता गया। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व छोटे पूंजीमालकों के लिए सम्भव नहीं रहा। सामाजिक धर्म और सामाजिक उत्पादन के मूल-साध उत्पादन के निजी स्वामित्व का भंग बैठना सम्भव नहीं था। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और उत्पादन के निजी स्वामित्व के फलस्वरूप समाज का अधिकांश भाग वस्तुओं में बन्धित रहा। यह निजी स्वामित्व अब उत्पादन की वृद्धि में भी बाधक बन गया। पूंजीवादी व्यवस्था के अनिवार्य अंग सत्रहहारा ने अपनी दशा को सुधारने के लिए, संपूर्ण विश्व और अनुभव से इस नीति पर पहुँचा कि पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त करना आवश्यक है।

पूंजीवाद ने स्वयं अपने विनाश की परिस्थितियों तैयार की और उस शक्ति को जन्म दिया जो पूंजीवाद को समाप्त करेगी। अब तक संसार के एक तिहाई भाग में यह शक्ति अपना काम पूरा कर चुकी है और बाकी देशों में भी उसका अभियान जारी है।

छाठवां | अतिरिक्त मूल्य का वंटवारा

अभी तक हमने यह देखा है कि अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन किस प्रकार होता है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का वितरण किस प्रकार होता है।

पूँजीपतियों में कई तरह के लोग होते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे होते जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्ध रखते हैं और कारखाने चलाते हैं। हम उन्हें उद्योगपति या औद्योगिक पूँजीपति (इन्डस्ट्रियल कैपिटलिस्ट) कहते हैं। पूँजीपतियों का एक भाग केवल वस्तुओं के खरीदने बेचने का काम करता है। उन्हें व्यापारी कहते हैं। कुछ पूँजीपति जमीन के मालिक होते हैं और उनकी आमदनी का साधन जमीन का लगान होता है। इसी तरह कुछ सूदखोर या महाजन होते हैं जो दूसरों को रुपया उधार देते हैं और उस रुपये का ब्याज वसूल करते हैं। पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूँजीपति अपने धन को "जोखिम" में डालते हैं और इस तरह अपने पैसे के बल पर पैदा करते हैं। उनका कथन यह भी है कि पूँजीपति अपने धन का प्रयोग करने देते हैं और इसी से लाभ या मुनाफा पैदा होता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है।

पूँजी का आवर्तन

पहले हम पूँजी के संचार की प्रक्रिया को भी देख चुके हैं। पूँजी का यह संचार लगातार जारी रहता है। यदि पूँजी का संचार रुक जाय तो पूँजी का अस्तित्व ही मिट जायगा क्योंकि फिर अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति

भी एक जागती । पूँजी का संसार एक प्रकार के वस्तु (मौल्य वस्तु) से
 होता है । इसे हम पूँजी का वृत्ताकार आवर्तन कह सकते हैं ।

प्रारम्भिक दौर पर पूँजी मुद्रा के रूप में रहती है । उस मुद्रा के द्वारा
 पूँजीपति उत्पादन के साधनों और श्रम-बलिक को मर्यादित है और उत्पाद
 किया जाना करता है । वेसाओं के द्वारा हम उन प्रक्रिया को निम्न प्रा
 ने अधिकृत कर सकते हैं :-

[मुद्रा = मु, वस्तु = व, श्रम-बलिक = श्र. प्र. उत्पादन के साधन = उ. सा.
 उत्पादन = उ.]

$$\text{मु} \text{-----} \text{व} \left\{ \begin{array}{l} \text{उ. सा.} \\ \text{श्र. प्र.} \end{array} \right\} \dots\dots\dots \text{उ.}$$

उत्पादन क्रिया के फलस्वरूप पूँजीपति द्वारा मर्यादी मदी वस्तु का
 मूल्य पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है अतएव जो नवीन वस्तु पैदा होती है
 इसके लिए हम एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करेंगे । नवीन वस्तु या परि
 वृद्धित मूल्य की वस्तु = व +

इसलिए पूँजीवादी उत्पादन का चित्र हम प्रकार हुआ :-

$$\text{मु} \text{-----} \text{व} \left\{ \begin{array}{l} \text{उ. सा.} \\ \text{श्र. प्र.} \end{array} \right\} \dots\dots \text{उ.} \dots\dots \text{व} +$$

अब इस पैदा की हुई वस्तु को बेचकर पूँजीपति मुद्रा हासिल कर
 है । इस प्रकार जो मुद्रा प्राप्त होती है उसका मूल्य पहले लगाई गयी मु
 की तुलना में अधिक होता है । अतएव पूँजी के वृत्ताकार आवर्तन क
 रेखा चित्र इस प्रकार हुआ :-

$$\text{मु} \text{-----} \text{व} \left\{ \begin{array}{l} \text{उ. सा.} \\ \text{श्र. प्र.} \end{array} \right\} \dots\dots \text{उ.} \dots\dots \text{व} + \text{-----} \text{मु}$$

अब यदि बीच की प्रक्रियाओं को उड़ा दिया जाय तो ऐसा मा

होता है कि पूँजीपति ने मूल्य में जो मुद्रा पत्ती के रूप में जमाई (मु) उसी से उसे अतिरिक्त मुद्रा (मु +) प्राप्त हुई। बाजार में "मु" और "मु + " के बीच में उत्पादन की प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य की शक्ति की महापत्ता से उत्पादन के साधनों का किसरीन बनाकर मनुष्यों का उत्पादन होता है। अतिरिक्त मूल्य का जन्म उत्पादन की प्रक्रिया में होता है मजदूर की श्रमिता में नहीं। पूँजी के बूनाकार अवर्तन मजदूर की श्रमिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है और उत्पादन के साथ मजदूर का अभिन्न सम्बन्ध है। फिर भी उत्पादन की प्रक्रिया का निर्णायक महत्व है।

पूँजीपति वर्ग के विभिन्न हिस्सों का जिस अभी कुछ पहले किया जा चुका है। औद्योगिक पूँजीपति का वास्तव में तीव्र पर उत्पादन की प्रक्रिया से रहता है। इसलिए वह तीव्र तीव्र पर मजदूरों में अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है। लेकिन यह अतिरिक्त मूल्य कबल उगी के पास नहीं रह जाता है, इसके भागीदार अन्य प्रकार के पूँजीपति भी होते हैं। इस अतिरिक्त मूल्य का एक भाग उन महाजनो या बैंकों के पास जाता है जो उद्योगपतियों को काम चलाने के लिए रुपया उधार देते हैं। एक अन्य भाग व्यापारियों के पास जाता है जो पूँजीवादी मजदूर प्रक्रिया में भाग लेते हैं और बाजार में एक हिस्सा उन मून्धारियों को भी मिलता है जो उत्पादन के एक महत्वपूर्ण साधन जमीन के मानिक होते हैं।

अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा "लाभ" या "मुनाफा" के नाम से होता है। औद्योगिक पूँजीपति को जो रुपय मिलती है उसे "औद्योगिक लाभ" (इन्डस्ट्रियल प्रॉफिट) कहते हैं, व्यापारी को "व्यापारिक लाभ" (कमर्शियल प्रॉफिट) मिलता है, महाजन या बैंकर को "श्रेण का श्राज" मिलता है और जमीन के मानिक को "समान" या "किराया" मिलता है।

लाभ की दर और अतिरिक्त मूल्य की दर

लाभ की दर मातूम करने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि

अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा

किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत लगी है या उमदा "लागत मूल्य" (कार्ट प्राइस) तथा है। इस लागत मूल्य के ऊपर जो रकम वस्तु के मालिक को मिलती है उसे लाभ कहते हैं। यदि किसी वस्तु में ५० रुपये लागत के लगे हैं और वह १०० रुपये में बिकती है तो उस पर २० रुपये का लाभ पूंजीपति को हुआ। "लागत-मूल्य" में दोनों ही प्रकार की पूंजी-सतत पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी-शामिल रहती है।

लाभ की दर मान्य करने का तरीका अतिरिक्त मूल्य की दर मालूम करने के तरीके से भिन्न है। हम पहले देखा चुके हैं कि अतिरिक्त मूल्य की दर तय करने लिए केवल परिवर्तनशील पूंजी और अतिरिक्त मूल्य के बीच का अनुपात देखा जाता है।

$$\text{अतिरिक्त मूल्य की दर} = \frac{\text{अ० मू०}}{\text{स० मू०}} \times १००$$

चूंकि लाभ की दर लागत-मूल्य के आधार पर तय की जाती है और लागत-मूल्य में परिवर्तनशील पूंजी के साथ सतत पूंजी भी शामिल रहती है इसलिए लाभ की दर (रेट आफ प्राफिट)

$$= \frac{\text{अ० मू०}}{\text{स० मू०} + \text{प० मू०}} \times १००$$

अब हम इसे स्पष्ट करने के लिए मान लें कि किसी उद्योग में ५० हजार रुपये की सतत पूंजी और २० हजार रुपये की परिवर्तनशील पूंजी लगी है। उससे पैदा की गयी वस्तुओं का दाम १ लाख, २० हजार रुपये है। उस उद्योग का कुल लाभ हुआ १२००००—१ लाख अर्थात् २० हजार रुपये।

$$\begin{aligned} \text{यहाँ लाभ की दर} &= \frac{२०००० \text{ लाभ}}{५० \text{ हजार (स० मू०)} + २० \text{ हजार (प० मू०)}} \times १०० \\ &= \frac{२००००}{१.०००००} \times १०० = २० \text{ प्रतिशत} \end{aligned}$$

नाम की दर मानने का दर तभीका भिन्न होने हुए भी यह नहीं
 समझना चाहिए कि "नाम" और "अतिरिक्त मूल्य" में मौलिक दर में
 अंतर है। वास्तव में नाम और अतिरिक्त मूल्य एक ही रकम को कहते हैं,
 इन रकम को जो बिना अनु के नाम में उगकी लागत (गात्र पूत्री +
 परिचर्यागत पूत्री) को विचार कर रखी है। ऊपर के उदाहरण में कुल
 उत्पादन के नाम १ लाख २ हजार रुपये हैं और गात्र पूत्री तथा परिचर्या-
 गत पूत्री का योग १ लाख रुपये है। इसलिए नाम या अतिरिक्त मूल्य २०
 हजार रुपये है।

इसी लिए कारणों में कहा है कि "नाम" या मूल्य "अतिरिक्त मूल्य"
 का परिचर्यागत रकम है। जब हम अतिरिक्त मूल्य या "नाम-मूल्य" मधी
 गात्र पूत्री और परिचर्यागत पूत्री के नाम के मुकाबल रख कर उगकी
 तुलना करते हैं तो इसे "नाम की दर" कहा है। लेकिन जब हम अतिरिक्त
 मूल्य को केवल परिचर्यागत पूत्री के नाम में रख कर उगकी तुलना करते
 हैं तो "अतिरिक्त मूल्य की दर" कहते हैं।

पूत्रीवादी अर्थशास्त्री केवल नाम की दर में बाधा रखते हैं क्योंकि
 उनका समर्थन इसी में है। पूत्रीवाद की दृष्टि हमें नाम पर केन्द्रित
 रहने है। यह अर्थ जो कुल पूत्री के लिए नाम की दर मानने में हमें नाम
 बाध रहा है। इसके लिए पूत्रीवाद मधी दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।

"नाम की दर" का विचार पूत्रीवादी मोषण की उद्यम पर पक्ष
 मानने का काम करता है। अतिरिक्त मूल्य की दर में मोषण को साफ़ ठीर
 में मानने हो जाता है कि पूत्रीवादियों द्वारा मजदूरों का मोषण बिना रचना
 में हो रहा है—मजदूरों की पूत्रीवादि विपत्तियाँ पैठन देते हैं और उनमें कितना
 खून करते हैं। लेकिन नाम की दर में ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाम
 तथा अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन में मजदूरों का कोई हान नहीं है।
 पूत्रीवादियों की पूत्री मानने अर्थ ही बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इस बुद्धि
 का प्रतिफल अनुभव भी उद्यम अधिक बढ़ा नहीं मानने होता है जितना

कि अतिरिक्त मूल्य की दर में। लाभ की दर तय करने में मजदूरी के हक में दी जाने वाली पूंजी अलग से नजर नहीं आती है। परिवर्तनशील पूंजी को रातत पूंजी के साथ मिलाकर और उसके रिश्ते में अतिरिक्त मूल्य ले रखकर जब पूंजीपति अपना हिस्सा तैयार करते हैं तो चारों ओर पूंजी की ही महिमा दिखाई देती है। मुद्रा स्वतः विराट रूप धारण कर लेती है।

औरत लाभ और उत्पादन के दाम

पूंजीपति मजदूर की श्रम-शक्ति खरीदता है और उसी के बल पर अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है। वस्तुओं का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम के आधार पर निश्चित होता है। जो पूंजीपति वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम को कम कर देते हैं वे अपने वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हैं जिसे विशेष अतिरिक्त मूल्य का नाम दिया गया है।

विशेष अतिरिक्त मूल्य का ही दूसरा नाम है—विशेष लाभ या अतिरिक्त लाभ। जिन उद्योगपतियों के पास उत्पादन के साधन सापेक्ष रूप से अधिक अच्छे होते हैं, जिनकी स्थिति अधिक सुविधाजनक होती है वे अन्य पूंजीपतियों की अपेक्षा कम लागत में वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं और अतिरिक्त लाभ कमा लेते हैं। अतिरिक्त लाभ की सम्भावना एक ही उद्योग के विभिन्न मालिकों के बीच में ही नहीं बल्कि पृथक-पृथक उद्योगों के मालिकों के बीच में भी होती है।

पूंजी का प्रवाह स्वतः उन्हीं उद्योगों की ओर होता है जहां लाभ की दर ऊंची होती है। यदि आज किसी वस्तु के दाम अधिक ऊंचे हैं और उसकी माँग अधिक है तथा पूर्ति कम है तो पूंजीपति उसी की पैदावार की ओर अधिक ध्यान देने लगेंगे। फलतः उसकी पैदावार बढ़ जायगी। अधिक पैदावार होने पर उसके दाम गिर जायेंगे और उसके उत्पादक पूंजीपतियों को अतिरिक्त लाभ मिलना बन्द हो जायगा। इसी तरह किसी उद्योग का मालिक जब बेहतर मशीनों का प्रयोग करके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता

है तो अन्य उद्योगों की जल्दी यंत्रों का प्रयोग करने लगते हैं। इस तरह के विभिन्न पूर्वोक्तियों के साथ ही हमें के बीच अछिन्न अन्तर नहीं हो पाता। अतः वही यह हर एक ही भी रहती है।

बाजार में वस्तुओं के दाम यह देख कर नहीं लग जाते हैं कि उनका उत्पादन किस उद्योगों के कारण होने में हुआ है और वर्तमान में इन उद्योगों ने बिना लागत के दाम क्या दिए हैं। बाजार में वस्तुओं के दाम उनके बाजार-मूल्य (माकेट-वैल्यू) के अनुसार तय होते हैं। बाजार-मूल्य का अर्थ है कि किसी वस्तु के उत्पादन में सामाजिक तौर पर बिजली लागत की सीमा नहीं है। मूल्य का निर्धारण का अर्थहीनता करने समय पहले भी कहा जा चुका है कि वस्तु का मूल्य उगने लगे हुए "सामाजिक रूप में आवश्यक" धन के द्वारा निर्धारित होता है और इसी मूल्य के इन्हीं वस्तु का दाम (मकरी मूल्य) तय होता है।

इस तरह विभिन्न उद्योगों के बीच पूंजी का प्रवाह जारी रहने और उद्योगों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण पन्ध्रमा की लागत पर एक अलग मुनाफा निश्चित होगा है। अलग मुनाफा या लाभ की सीमा दर क्या है? जब एक ही आकार की पूंजी पर समान रूप से लाभ प्राप्त होता है तो उसे औसत लाभ कहते हैं।

किसी वस्तु के लागत-मूल्य औसत लाभ की रकम जोड़कर जो दाम निश्चित किये जाते हैं उन्हें "उत्पादन के दाम" (प्राइस आफ प्रोडक्शन) कहते हैं। इस प्रकार उत्पादन के दाम = सतत पूंजी + परि-वर्तनीय पूंजी + औसत लाभ। बाजार में वस्तुओं की बिक्री इसी औसत लाभ और उत्पादन के दाम के अनुसार होती है।

परि हम विभिन्न वस्तुओं या उद्योगों को अलग-अलग करके देखें तो मान्य होगा कि यह उत्पादन के दाम हमें वस्तुओं के मूल्य के अनुसार ही

नहीं होते हैं यद्यपि सामाजिक रूप से कुल मूल्य उत्पादन के दामों के पते के बराबर होते हैं। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित तालिका को देखिए:-

उद्योग	पूँजी का दैहिक अनुपात	अतिरिक्त मूल्य की दर %	अतिरिक्त मूल्य	लाभ की दर %
	स.पू. + परि-पू.			
चमड़ा	७० + ३०	१००	३०	३०
कपड़ा	८० + २०	१००	२०	२०
इंजीनियरिङ्ग	६० + १०	१००	१०	१०
कुल जोड़	२४० + ६०	१०० प्र.श.	६०	२० प्र.

उद्योग	वस्तु का मूल्य	औसत लाभ %	उत्पादन के दाम	मूल्य तथा उत्पादन के दाम में अंतर
चमड़ा	१३०	२०	१२०	-१०
कपड़ा	१२०	२०	१२०	—
इंजीनियरिङ्ग	११०	२०	१२०	+१०
कुल जोड़	३६०	२० प्र. श.	३६०	—

इस तालिका में तीन भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग दिये गये हैं। तीनों में पूँजी का दैहिक अनुपात अलग-अलग है। किन्तु मजदूरों के श्रम की रफ्तार में कोई अन्तर नहीं है। उनमें अतिरिक्त मूल्य की दर समान रूप से १०० प्रतिशत है। यदि हम इन तीनों वस्तुओं के दाम अलग-अलग मूल्य के अनुसार निश्चित करें तो चमड़ा उद्योग के मालिक को १०० प्रतिशत लाभ पर ३० प्रतिशत लाभ होता है, कपड़ा-उद्योग में २० प्रतिशत लाभ होगा और इंजीनियरिंग में केवल १० प्रतिशत। ऐसा होने पर सभी उद्योगों पर चमड़ा उद्योग की तरफ दौड़ पड़ेंगे। लेकिन औसत लाभ के अनुसार जो उत्पादन के दाम तय होंगे उनमें चमड़ा उद्योग के मालिक को १३० स्थान पर १२० मिलेंगे, कपड़ा उद्योग में स्थिति जैसी की तैसी रहेगी।

इन्जीनियरिंग में ११० के स्थान पर १२ मिलेंगे अर्थात् लाभ की दर १० प्रतिशत से बढ़कर औसत २० प्रतिशत हो जायगी ।

उपर्युक्त तालिका में मालूम होता है कि चमत्ता उद्योग के मालिक के लाभ की दर कम हो गयी और इन्जीनियरिंग के लाभ की दर उतनी ही बढ़ गयी । यह अवश्य हुआ लेकिन सामाजिक रूप से पूँजी के कुल लाभ में कोई अन्तर नहीं हुआ । सामाजिक रूप से कुल पूँजी ३०० है और उस पर अतिरिक्त मूल्य ६० है । औसत लाभ के द्वारा मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ उनका शोषण उसी गति से जारी रहा । अन्तर केवल एक हुआ और यह यह कि जब समान रूप से पूँजीपति वर्ग में लाभ का बँटवारा हुआ तो मजदूर-मजदूरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त मूल्य का एक अंश इन्जीनियरिंग उद्योग के मालिकों के पास चला गया ।

इस उदाहरण में हम यह भी देख सकते हैं कि यदि किसी उद्योग में अतिरिक्त मूल्य की दर कम कर दी जाय तो उसने औसत लाभ कम हो जायगा । इसके विपरीत अगर किसी उद्योग में अतिरिक्त मूल्य की दर बढ़ा दी जाय तो उसने औसत लाभ भी बढ़ जायगा । पूँजी के औसत लाभ को बँचा रखने के लिए मजदूरों का शोषण अधिकाधिक तीव्रगति से होते रहना चाहिये । यदि उद्योग के किसी क्षेत्र में मजदूर का शोषण कम हो जाना है तो उससे पूरे पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ को धनका लगता है । इसीलिए जब किसी उद्योग के मजदूर अपनी मांगों के लिए सघर्ष करते हैं तो उन्हें न हीबल अपने मालिकों का सामना करना पड़ता है बल्कि मालिकों का पूरा धैर्य उनकी मांगों का विरोध करता है ।

उत्पादन के दाम की समझने के लिए इतना ही जान लेना काफी है कि सामाजिक रूप से "उत्पादन के दाम" का योग वस्तुओं के "मूल्य" के योग के बराबर होता है और पूरे "अतिरिक्त मूल्य" का योग कुल "लाभ" के बराबर होता है । मूल्य का नियम इसी प्रकार "उत्पादन के दाम" के सामर्थ्य में अमन में आता है ।

अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा

लाभ की दर और लाभ का योग

जैसे जैसे पूंजीवादी उत्पादन आगे बढ़ता है उसी प्रकार पूंजी का दैहिक अनुपात उच्चतर होता जाता है। मशीनों, इमारतों, कच्चे माल आदि में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लगती है और मजदूरों की संख्या उसी गति से नहीं बढ़ती है। पूंजी के दैहिक अनुपात के उच्चतर हो जाने से लाभ की दर में गिरावट आना स्वाभाविक है। लेकिन लाभ की दर में होने वाली इस गिरावट से पूंजी के कुल लाभ में कमी नहीं आती है। इसके विपरीत पूंजी के लाभ का योग बढ़ता जाता है। नीचे की तालिका में हम उदाहरण के तौर पर पूंजी की दो रकमों का उदाहरण दे रहे हैं जो बीस साल में दुगुनी हो गयी हैं, जिनके दैहिक अनुपात में तथा लाभ की दर में अन्तर है।

	दैहिक अनु. कुल पूंजी	अतिरिक्त मू. स.पू.प.पू. की दर	लाभ या अ० मूल्य	लाभ की दर
१९४० ई० १० करोड़ रु.	६ + ४ करोड़	१००	४ करोड़	४० प्र.श.
१९६० ई० २० करोड़ रु.	१५ + ५ "	१००	५ करोड़	२५ प्र.श.

इस उदाहरण में १९४० ई० में कुल पूंजी १० करोड़ रुपये थी। उसमें सतत पूंजी ६ करोड़ (६० प्रतिशत) थी और परिवर्तनशील पूंजी ४ करोड़ (४० प्रतिशत) थी। अतिरिक्त मूल्य की दर १०० प्रतिशत थी। इस हिसाब से लाभ की दर ४० प्रतिशत थी और कुल लाभ ४ करोड़ रुपये हो गया। १९६० में इसी उद्योग की पूंजी बढ़कर २० करोड़ हो गयी। पूंजी का दैहिक अनुपात भी उच्चतर हो गया। सतत पूंजी का अनुपात ६० प्रतिशत से बढ़कर ७५ प्रतिशत हो गया २० करोड़ में से १५ करोड़ और परिवर्तनशील पूंजी केवल २५ प्रतिशत रह गयी जब कि पहले ४० प्रतिशत थी। दोनों में अतिरिक्त मूल्य की दर समान रही। अन्त में हम देखते हैं कि पूंजी के लाभ की दर में तो कमी हुई, वह ४० प्रतिशत से घटकर २५ प्रतिशत रह गयी लेकिन लाभ के योग में कमी के स्थान पर वृद्धि हुई।

कुल नाम '४ करोड़ के स्थान पर ५ करोड़ हुआ अर्थात् कुल लाभ में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई।

इसलिए लाभ की दर में होने वाली इन कमी को देखकर यह नहीं अनुमाना चाहिए कि पूँजीपति वर्ग अब गरीब होता जा रहा है और उसका अपने आप दिवाना मिट जायगा। पूँजीवादी पुनरोत्पादन इसी ढंग से चलता है। पूँजी का दैहिक अनुपात उच्चतर होता है, उनके लाभ की दर में गिरावट आती है, फिर भी उसका कुछ लाभ बचना जाता है और इसके स्वरूप दिन प्रति दिन पूँजी का आकार बढ़ता जाता है।

लाभ की दर में गिरावट को रोकने के लिए पूँजीपति मजदूरों का शोषण और भी तेज करते हैं। इसके लिए वे मजदूरों की सुविधाओं को देने से इनकार करते हैं और नये-नये हथकण्डों में काम लेते हैं। अपने लक्ष्य में पूँजीपति वर्ग काफी हद तक कामयाब भी होता है। यदि ऐसा न होना तो लाभ की दर की गिरावट एक प्रवृत्ति या रज्जान के रूप में न रहती बल्कि एक अनिवार्य नियम के रूप में अबाध गति में आगे बढ़ती और पूँजीपतियों के लिए यह भारी कठ-कारखानों का विकास लाभदायक न रह जाता।

पूँजीपति अपना बोझ मजदूरों के कंधों पर खिसका कर लाभ की दर की गिरावट को धीमा कर देने हैं किन्तु उसे बिलकुल रोक नहीं पाते हैं। इसके साथ ही पूँजीवाद का बुनियादी अन्तर्विरोध—मजदूरों और पूँजीपतियों का अन्तर्विरोध और उग्र हो जाता है।

व्यापारिक लाभ

औद्योगिक पूँजीपतियों का लाभ तो आसानी से समझ में आ जाता है लेकिन व्यापारिक पूँजी के लाभ का स्रोत क्या है, इसे जानने में अधिक कठिनाई होती है। लेकिन व्यापारिक पूँजी पर प्राप्त होने वाला लाभ कोई पूरक बन्तु नहीं है। वास्तव में लाभ या अतिरिक्त मूल्य की उत्पत्ति उत्पादन की प्रक्रिया में होती है। उत्पादन के साधनों का मासिक और औद्योगिक

अतिरिक्त मूल्य का चेंडूवारा

पूँजीपति होता है। इसलिये वही सबसे पहले उस नाम का भी अधिकारी होता है। औद्योगिक पूँजीपति लाभ की पूँजी रकम को अकेले नहीं हड़प जाता है वरन् उसका एक अंश व्यापारी को भी देता है।

औद्योगिक पूँजीपति लाभ का बँटवारा व्यापारियों के साथ करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापारियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पूँजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन विक्री के लिए होता है। औद्योगिक पूँजीपति अपनी मुद्रा को वस्तुओं का रूप देता है और व्यापारिक पूँजीपति जब इन वस्तुओं को ले जाकर बेच देता है तो इन वस्तुओं को फिर से मुद्रा का रूप प्राप्त हो जाता है। यह मुद्रा फिर पूँजी की हैसियत से उत्पादन-क्रिया में भाग लेती है। यदि संचार की प्रक्रिया में औद्योगिक पूँजीपतियों को व्यापारियों की सहायता नहीं प्राप्त हो तो उन्हें स्वयं दुकानें आदि खोलने के लिए और पूँजी लगानी होगी। व्यापारियों की इस सहायता के बदले में ही औद्योगिक पूँजीपति कुल लाभ का एक अंश उन्हें देते हैं।

लाभ की दर की दृष्टि से औद्योगिक पूँजी और व्यापारिक पूँजी में अन्तर नहीं होता है। यदि व्यापारिक पूँजी के लाभ की दर कम हो जाय तो लोग व्यापार में पूँजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। इससे पूँजी के आवर्तन में बाधा पड़ेगी। इसलिए व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों में पूँजी के लाभ की दर वही रहती है हालाँकि औद्योगिक पूँजीपतियों को कुल मिला कर अधिक लाभ होता है क्योंकि उनकी पूँजी का परिमाण भी अधिक होता है।

संचार की प्रक्रिया में काफी खर्च भी लगता है। यह व्यय दो प्रकार का होता है। पहला व्यय वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जैसे कि वस्तुओं को गोदानों में रखने का खर्च, रेल आदि से ढोकर ले जाने और उनकी पैकिंग आदि का व्यय। इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। यह व्यय उत्पादन के व्यय के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि

एनडुर का बपड़ा दिल्ली में भी उन्ही दामों पर बिकता है। दूसरा व्यय वह है जिसे हम पंचार का शुद्ध व्यय (नेट कास्ट आफ ससुंजेसन) कहते हैं। इनमें डूबान का किराया, सेल्समैन की सनखराह, बिज्ञापन आदि का खर्च शामिल है। पूंजीवादी प्रणाली में इस तरह के खर्च काफी अधिक होते हैं और उनके कारण मूल मिलाकर संचार का व्यय बढ़ जाता है और वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं।

व्यापार दो तरह का होता है—थोक और फुटकर। थोक व्यापार में औद्योगिक पूंजीपति अपना माल व्यापारिक पूंजीपतियों के हाथ बेचते हैं और फुटकर व्यापार में व्यापारिक पूंजीपति इन्हीं वस्तुओं को सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के हाथ बेचते हैं।

व्यापार केवल अपने देश की सीमाओं के भीतर नहीं होता है वरन् अन्य देशों के साथ भी होता है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार में जो लाभ होता है या अतिरिक्त रकम मिलती है उसे 'प्राप्तना' (वैलेंस आफ पेमेंट) कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत को व्यापार के फलस्वरूप जो रकम मिलने वाली थी उसे हम "पाउण्ड प्राप्तना" (स्टिलिंग वैलेंस) कहते थे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो शब्द आते हैं—आयात और निर्यात। आयात उच्च मूल्य वाले वस्तुओं को कहते हैं जो बाहर से मंगाया जाता है और निर्यात में वह वस्तुएँ शामिल रहती हैं जो किसी अन्य देश को भेजी जाती हैं। "प्राप्तना" की रकम इस पर निर्भर करती है कि किसी देश का निर्यात उसके व्यय की तुलना में जितना अधिक है। जिन देशों का आयात अधिक होता है वे अन्य देशों के कर्जदार हो जाते हैं। बड़े-बड़े पूंजीवादी देश हमेशा उत्पन्न विकसित देशों को कर्जदार बनाकर उन्हें अपने बश में रखने की कोशिश करते हैं।

उधार पूंजी और व्याज

औद्योगिक पूंजीपतियों को कभी कभी अपना काम चलाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है। उनका पूरा तैयार माल

अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा

एक साथ नहीं विक जाता है। उनके विकल्प में कुछ समय लगता है। इस बीच में उद्योगपति अपने कारखाने को बन्द नहीं करता है, उसे चालू रखता है। उनके लिए उसे मुद्रा चाहिए। इसी समय में अनेक उद्योगों में कच्चा मान फायल पर ही पूरे मान के लिए गरिष्ठ निर्यात जाता है। यह कच्चा मान कमजोर वस्तुओं में परिवर्तित होता है और फिर उन वस्तुओं के विकल्प पर ही उस कच्चे मान के साम पूंजीपति के हाथ में वापस आते हैं। उत्पादन के लिए हम अपने देश के सीसी उद्योग को लेते हैं। चीनी मिलों की पैदावार ६ महीने में तैयार हो जाती है परन्तु उनके विकल्प में पूरा साल लग जाता है। जब फायल का समय आता है और मिन चालू होते हैं तो उन्हें घास तीर में नये की जरूरत होती है। ऐसे मौकों पर काम करने के लिये मिल मालिक दुबरे ने कर्ज लेते हैं।

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि औद्योगिक पूंजीपति हमेशा कर्ज लेते ही रहते हैं। ऐसा भी समय आता है जब उनके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी आ जाती है, खास कर ऐसे समय जब उन ही वस्तुओं की विकल्प अधिक जोरों में होती है या अन्य वस्तु कम हो जाती हैं। उस समय उद्योगपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को अन्य पूंजीपतियों को उधार देते भी हैं। पूंजीपतिवर्ग में पूंजी का यह लेन-देन बराबर चलता रहता है। एक निश्चित समय के लिए निश्चित लाभ भी दृष्टि से जो पूंजी अन्य लोगों को देती है उसे "उधार पूंजी" कहते हैं। उधार पूंजी के देने वाले को इन रकम के बदले में जो अतिरिक्त रकम प्राप्त होती है उसी को "व्याज" कहते हैं।

व्याज भी अतिरिक्त मूल्य का एक हिस्सा है जो औद्योगिक पूंजीपति के द्वारा महाजन को या उधार-पूंजी देने वाले को अदा किया जाता है। व्याज की दर घटती बढ़ती रहती है। जब कभी उधार-पूंजी की मांग अधिक होती है तो व्याज की दर बढ़ जाती है, मांग कम होने पर व्याज की दर गिर जाती है। लेकिन व्याज की दर कभी भी औसत लाभ की दर से अधिक

नहीं हो सकती है क्योंकि बीसत लाभ की रकम से ही व्याज का भुगतान किया जाता है।

बैंकों का काम

पूर्वादादी समाज में बैंक भी एक प्रकार के पूँजीवादी प्रतिष्ठान होते हैं। बैंकों का काम उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच मध्यवर्ती का कार्य होता है। बैंकों में न केवल पूँजीपति बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोग संपत्ति जमा करते हैं। इस प्रकार बैंकों में जो धन जमा (डिपॉजिट) होता है उसके बदले में बैंक जमा करने वालों को व्याज अदा करता है। फिर बैंकों के स्वामी या बैंकर इस रुपये को दूसरों को (व्यापारियों या उद्योगपतियों को) काम के लिए उधार देते हैं और इस उधार पूँजी के लिए व्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार बैंकों का एक काम है समाज की संपूर्ण पूँजी को एकत्रित करना जो अस्थायी रूप में बेकार पड़ी होती है और दूसरा काम है इस पूँजी को जरूरत मन्द पूँजीपतियों के पास पहुँचाते देना।

बैंक उधार पूँजी के लिए व्याज की जो दर निश्चित करते हैं वह उस दर से अधिक होती है जिसके अनुसार जमा रकम या डिपॉजिट के लिए व्याज अदा करते हैं। बैंक जो कर्ज देते हैं उन्हें "बैंक-ऋण" कहा जाता है। बैंक ऋण के व्याज और बैंक-जमा (डिपॉजिट) के व्याज के बीच का फरक ही बैंकरो की आय का स्रोत होता है।

बैंक केवल पूँजी जमा करने और उधार देने का ही काम नहीं करते हैं। वह संपत्ति भी कारखानों में पूँजी लगाते हैं और लाभ कमाते हैं।

बैंकों के कारण पूँजीपति वर्ग को अनेक प्रकार से फायदा होता है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी पूँजीपति की पूँजी बेकार नहीं रहती है। वह उसे बैंक में जमा करके व्याज हासिल कर लेता है। इसके अलावा बैंकों के कारण पूँजीपतियों को कर्ज आसानी से मिल जाता है। बिना किसी खास

दोड़-धूप के पूँजीपतियों को न सिर्फ अपने वर्ग की जमा की हुई रकम मिल जाती है बल्कि अन्य वर्गों के लोगों की जमा-रकम भी उसके हाथ लग जाती है। जन-साधारण को पता भी नहीं चलता कि उनके धन का उपयोग किस प्रकार पूँजीपति वर्ग के लाभ के लिए हो रहा है। इसके विपरीत लोग यही समझते हैं कि बैंक उन्हें जमा धन के बदले में व्याज देकर कृतार्थ कर रहे हैं।

बैंक पूँजीपति वर्ग को ही नहीं पूँजीवादी सरकारों को भी कर्ज देते हैं और उनकी सेवा करते हैं।

ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी

जैसे जैसे पूँजीवाद का विकास होता गया उसी रफ्तार से बड़े-बड़े उद्योगों की वृद्धि होती गयी। ऐसे उद्योगों का जन्म हुआ जिनके चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में रेलों, बन्दरगाहों आदि के लिए संयुक्त रूप से पूँजी इकट्ठा करने की आवश्यकता हुई और इसके लिए ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियाँ खोजी गयी। आज तो अधिकांश पूँजीवादी प्रतिष्ठान ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में चलते हैं।

किसी ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी में लगी हुई पूँजी उसके हिस्सों या शेयरों में बँटी होती है। प्रत्येक शेयर के निश्चित दाम होते हैं और कोई भी व्यक्ति जितने शेयर चाहे खरीद सकता है। कम्पनी का पूरा लाभ उसके हिस्सेदारों या शेयर होल्डरों में उनके शेयर के मूल्य के अनुपात से बाँट दिया जाता है। किसी हिस्सेदार को उसके शेयर से जो लाभ होता है उसे बाभांश या डिवीडेंड कहते हैं।

हिस्सेदारों के पास उनके शेयर एक प्रकार के "अधिकार-पत्रों" (सेक्योरिटी) के रूप में रहते हैं। इस अधिकार-पत्र के द्वारा उन्हें कम्पनी के लाभ में अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से बाजार में इन अधिकार-पत्रों की भी खरीद और बिक्री होने लगती है। हम अक्सर यह देखते हैं कि शेयरों के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं। यह कैसे होता है ?

यहाँ शेयरों की खरीद-बिक्री होती है उसे शेयर-बाजार या स्टॉक-एक्सचेंज कहते हैं। शेयर-बाजार में उन्हीं कम्पनियों के शेयर अधिक दामों पर बिकते हैं जिनका नाम अधिक होता है और जो अपने हिस्सेदारों को अधिक लाभान देती हैं। शेयरों के दाम इस आधार पर निश्चित होने हैं कि कौन सी कम्पनी के आभास की दर ब्याज है और बैंकों से जमा-धन पर जो ब्याज मिलता है उसकी दर क्या है। यदि लाभान की दर ब्याज की दर से अधिक है तो शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। मान लीजिये कि कोई कम्पनी १०० रुपये के शेयर पर १० रुपये लाभान अदा करता है और बैंक में १०० रुपये जमा करने पर केवल ५ रुपये मिलते हैं तो लोग उक्त कम्पनी के १०० रुपये के शेयर के लिए दो सौ रुपये तक देने के लिये तैयार हो जायेंगे।

कम्पनियों में हिस्सेदारों या शेयर होल्डर्स की संख्या हजारों की होती है। लेकिन इससे यह मोच बैठना गलत होगा कि अब ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के स्थापित होने से पूँजीवाद का स्वरूप बदल गया है और वह "जनशाही" हो गया है। वास्तव में कम्पनियों के साधारण हिस्सेदारों को कोई पूछने वाला नहीं है। कम्पनियों के प्रबन्ध में उन्हीं हिस्सेदारों की मनमानी चलती है जिनके पास अधिक संख्या में या अधिक कीमत के शेयर होते हैं। किसी कम्पनी में स्वेच्छ पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए जितने शेयर आवश्यक होने हैं उन्हें "नियंत्रणकारी हित" (कन्ट्रोलिंग इन्टरेस्ट) कहते हैं। अनुभव बताता है कि ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी में यदि किसी पूँजीपति के पास ४० प्रतिशत तक शेयर हुए तो भी वह शेयर ६० प्रतिशत शेयरों के हजारों मालिकों की पूँजी पर नियंत्रण हासिल कर लेता है।

ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों की व्यवस्थाओं भी पूँजीपतियों को समाज के अन्य सदस्यों की सम्पत्ति का उपयोग अपने हितों में करने की स्वतंत्रता देती है। इससे पूँजी का अधिकार-क्षेत्र और कार्य-क्षेत्र बढ़ता है। बड़े-बड़े पूँजीपति अब अनेक कम्पनियों के शेयर खरीदकर उनमें अपना नियंत्रणकारी हित स्थापित करते हैं और उनके वास्तविक मालिक बन जाते हैं। अन्य

समय भी लगान अदा करते हैं जब कि सामन्तवाद का स्थान पूँजीवाद ले लेता है। लेकिन पूँजीवादी लगान सामन्तवादी लगान से भिन्न होता है।

सामन्तवाद के अन्तर्गत लगान की अदायगी के तरीके हमेशा एक ही ही रहे हैं। उनमें भी परिवर्तन होता रहा है। इनमें से एक तरीका था कि जिनके रूप में लगान अदा करने का जिम्मेदार किसान को अपने मालिक के यहाँ एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता था। हमारे देश में भी मनुस्मृति जैसे ग्रन्थ में इस तरह के अनिवार्य धर्म का जिक्र आया और इसी प्रथा के अवशेष के रूप में हरी और बेगार की प्रथा थी, जो अब तक देखने में आ जाती है।

लगान की अदायगी का दूसरा तरीका था उत्पादन की वस्तु के रूप में माल देने का। इसे जिनसी लगान कहते हैं। खेत की पैदावार का एक भाग सामन्त को लगान के रूप में मिलता था। हमारे देश में भी यह प्रथा थी यद्यपि समय-समय पर यह भाग बदलता रहता था, कभी राजा को छठा भाग (षष्ठ्यांश) मिलता था तो कभी एक-तिहाई मिलता रहा। वस्तु के रूप में लगान अदा करने वाला किसान उससे अधिक स्वतन्त्रता अनुभव करता था किन्तु धर्म के रूप में लगान देना पड़ता था। अब भी बंटवाई पर खेत में जाने वाले किसान उत्पादन की वस्तु के रूप में लगान अदा करते हैं और इनके मून्डानियों को पैदावार का आधा भाग तक मिल जाता है।

लगान की अदायगी का तीसरा तरीका था नकदी लगान या मुद्रा के रूप में लगान देने का। मुद्रा के रूप में लगान का प्रचलन काफी बाद में हुआ है फिर भी यह नहीं समझना चाहिये कि पूँजीवादी युग में ही नगदी लगान की प्रथा खाली हुई। सामन्तवाद के ही युग में लोग मुद्रा के रूप में लगान अदा करने लगे थे। भारत में नगदी लगान सम्राट अकबर के युग में ही खाली था यद्यपि ब्रिटिश शासन में ही उसकी प्रधानता पूरे देश के पैमाने पर स्थापित हुई। पूँजीवाद जब ऋषि की व्यवस्था में लागू होता है तो अन्य

प्रकार के लगान (यस के रूप में, वस्तु के रूप में) लगान की जाती है और
 मगरी लगान सर्वत्र विद्यमान हो जाता है।

पूँजीवादी लगान और साम्यवादी लगान के बीच का अन्तर इन
 दोनों प्रकारों की अन्तर्गत अन्तर्गत है अन्तर्गत के अन्तर्गत है। साम्यवाद
 में विमान मीठे और एक भूस्वामीयता का अन्तर्गत है। साम्यवादी भूस्वामी
 विमान द्वारा जीवित उत्पादन का अन्तर्गत है और अन्तर्गत है और
 अन्तर्गत अन्तर्गत भी अन्तर्गत है। पूँजीवादी भूस्वामी जमीन के
 पूँजीवादी विमानों (फार्मर्स) के अन्तर्गत है और पूँजीवादी फार्मर्स के
 जमीन पर अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तर्गत
 अन्तर्गत और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत पूँजीवादी अन्तर्गत
 विमानों (कॉन्ट्रिब्यूटर्स अन्तर्गत फार्मर्स) और भूस्वामीयता के बीच में अन्तर्गत
 है। भूस्वामी अन्तर्गत जमीन की अन्तर्गत लगान पर ही अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत
 कभी वह मीठे और एक अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत पूँजीवादी अन्तर्गत अन्तर्गत ही अन्तर्गत हो जाता है। पूँजीवाद में अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत होता है अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत के द्वारा होता है।

विशिष्ट लगान (डिफरेंशियल रेंट)

लगान (ग्राउन्ड रेंट) अन्तर्गत अन्तर्गत का एक भाग है जो भूस्वामी
 को जमीन का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 जाता है। लेकिन लगान निर्धारित अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 जमीन की "किसमों" के अनुसार अन्तर्गत अन्तर्गत है। जिस भूमि की अन्तर्गत
 अधिक होती है उसका लगान अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अधिक देना पड़ता है। जो जमीन किसी नदी, नहर या द्यूबवेत के अन्तर्गत
 होती है अन्तर्गत अन्तर्गत के लिहाज से अच्छी होती है या जो जमीन किसी
 शहर और बाजार के नजदीक होती है उसका लगान अधिक होता है।
 समय के साथ भी किसी जमीन के लगान की दर में अन्तर पड़ सकता है।

यदि कल किसी गाँव के पास कुछ कारखाने खुल जायें और वहाँ एक अच्छी जनसंख्या निवास करने लगे तो उसके लिए साग-सब्जी आदि की आवश्यकता बढ़ जायगी। इस दृष्टि से आस पास की जमीनों को लोग अधिक रगत पर लेने के लिये तैयार हो जायेंगे। इस तरह से जमीन का मूल्य बढ़ जाता है और जमीन के मालिक या भूस्वामी लगान के रूप में अपनी जमीन का मूल्य बसूल करते हैं।

अपेक्षाकृत अधिक उर्वर तथा अधिक सुविधापूर्ण भूमि के उपयोग से सामान्य भूमि की तुलना में अतिरिक्त लाभ होता है उसी को विशिष्ट लगान रहते हैं। भूस्वामी वर्ग दावा करता है कि यह विशेष लाभ भूमि के विशेष गुणों के कारण हुआ है और चूँकि वह भूमि का स्वामी है इसी लिये इस लाभ का भी अधिकारी है। जब कोई भूस्वामी अपनी जमीन का पट्टा लेखता है या उसे निश्चित समय के लिए लगान पर उठाता है तो पहले से अनुमान करता है कि भूमाली जमीन के मुकाबिले उस जमीन से कितना अधिक लाभ होगा। वह इस अतिरिक्त लाभ को अपने लगान में शामिल कर लेता है। समान रूप से पूँजी और श्रम लगाने पर सुविधाजनक भूमि से अधिक उत्पादन होता है, उससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है इसी लिये किसान विशिष्ट लगान को देना स्वीकार कर लेता है।

भूस्वामी से एक बार निश्चित काल के लिये लगान पर जमीन लेने के बाद भी किसान जमीन में सुधार करते रहते हैं। इससे उन्हें और भी आय प्राप्त होती है किन्तु इस आय पर भूस्वामी का अधिकार नहीं होता है क्योंकि उसका लगान पहले से ही निश्चित होता है। हाँ, जब निश्चित समय के बाद दुबारा पट्टा बदलने का समय आता है तो भूस्वामी फिर से लगान को बढ़ाने की कोशिश करता है और किसान द्वारा किये गये सुधारों का धपरा स्वयं उठाता है। संक्षेप में विशिष्ट लगान वह विशिष्ट आय है जिसके निम्नलिखित तीन स्रोत हैं—

(१) भूमि की उर्वरता (२) भूमि की स्थिति और (३) धनीभूत

अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा

रीती के तरीके। उनमें से पहले दो-तीनों श्रेणियों में (भूमि की उर्वरता और भूमि की विविधता से प्राप्त विभिन्न लगान की प्रथम श्रेणी का विभिन्न लगान करने के बाद पानीभूमि श्रेणी में प्राप्त विभिन्न लगान को द्वितीय श्रेणी का विभिन्न लगान करते हैं।

खेतों में मूल्य का नियम

विभिन्न लगान को समझने के लिये यह भी जान लेना चाहिये कि कृषि के उत्पादन पर मूल्य का नियम किन तरह लागू होता है। कृषि-उत्पादन पर मूल्य का नियम एक विशेष ढंग से लागू होना है। औद्योगिक उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन मूल्य पर उन उद्योगों का अधिक प्रभाव पड़ता है जो यांत्रिक और प्राधिधिद्य उत्पत्ति के कारण कम लागत से अधिक मूल्य के वस्तुओं तैयार करते हैं। इसके कारण वस्तुओं के बाजार दाम गिरते हैं और अन्य उद्योगपति अपने उत्पादन के माधनों को उन्नत बनाने के लिये बाध्य होते हैं। किन्तु खेती में उसका उल्टा होता है। कृषि उत्पादन के दाम उन फार्मों की लागत से प्रभावित होते हैं जिनके उत्पादन के माधन अधिक पिछड़े होते हैं और जिनके उत्पादन में लागत-मूल्य अधिक होता है। यह फार्म कृषि की उपज की कीमतों (दामों) को ऊँचा बनाये रखने में सहायक होते हैं जिसमें उन्नत साधनों वाले फार्मों की आय बढ़ जाती है और वे अधिक-अधिक बड़े पैमाने पर उन्नत साधनों का प्रयोग करते हैं।

नीचे की तालिका से हम इसे और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इस तालिका में तीन प्रकार की भूमि ली गयी है। प्रथम श्रेणी की भूमि वह है जिसे निष्कृष्ट भूमि कह सकते हैं, जिस पर पैदावार सबसे कम होती है; द्वितीय श्रेणी की भूमि मध्यम या औसत प्रकार की भूमि है और तृतीय श्रेणी में उत्तम प्रकार की भूमि है।

भूमि की श्रेणी	सादागन पूंजी	औसत लाभ की दर	उत्पादन विशिष्टता	उत्पादन के दाम पृष्ठ उपज का
प्रथम	१००	२०	१०	१२०
द्वितीय	१००	२०	१५	१२०
तृतीय	१००	२०	२०	१२०

भूमि की श्रेणी	क्षम-प्रसंग उत्पादन के दाम सामाजिक रूप में प्रति विशिष्टता	उत्पादन के दाम सामाजिक रूप में प्रति विशिष्टता	गुण उत्पादन का	विशिष्ट लगान
प्रथम	१२ रु.	१२ रु.	१५०	—
द्वितीय	८ रु.	१२ रु.	१५०	+ ६०
तृतीय	६ रु.	१२ रु.	२६०	+ १२०

यहाँ तीनों प्रकार की भूमि पर समान रूप से पूंजी लगाई गयी है लेकिन उनकी पंजावार में अन्तर है। यदि पूंजी पर औसत लाभ २० प्रतिशत मान लिया जाय तो प्रथम श्रेणी की भूमि के उत्पादन के दाम १२ रुपये प्रति विशिष्टता होंगे और दूसरी श्रेणी की भूमि की उपज का मूल्य ८ रुपये प्रति विशिष्टता होना चाहिये तथा तीसरी श्रेणी की भूमि के किसान को केवल ६ रु. प्रति विशिष्टता मिलने चाहिये। लेकिन सामाजिक रूप से ऐसा नहीं होता है। सामाजिक रूप से कृषि वस्तुओं के उत्पादन के दाम सबसे पचास श्रेणियों के उत्पादन के दाम के द्वारा निर्धारित होते हैं अतएव सभी उत्पादकों को १२ रुपये प्रति विशिष्टता के दाम मिलेंगे। इसके फलस्वरूप द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। द्वितीय श्रेणी के किसान को ६० रुपये अधिक मिलेंगे और तृतीय श्रेणी के किसान को १२० रुपये अधिक मिलेंगे। भूस्वामी इन किसानों से इस अतिरिक्त लाभ को विशिष्ट लगान के रूप में लेता है। निरूप्य भूमि पर (प्रथम श्रेणी की) कोई विशिष्ट लगान नहीं देना पड़ेगा।

विशुद्ध लगान

अधिक उपजाऊ और सुविधापूर्ण भूमि के लिये भूस्वामी विशिष्ट अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा

लगान का दावा पेश करते हैं लेकिन निशुद्ध भूमि को भी वह मुफ्त में खेती के लिये नहीं बाँट देते हैं। मगधे खराब भूमि को भी जब कोई भूस्वामी खेती के लिये देता है तो उसका लगान माँगता है। इन जमीनों पर भी जो लगान देना पड़ता है वह "विशुद्ध लगान" है।

विशुद्ध लगान किस प्रकार निर्धारित होता है? विशुद्ध लगान भूस्वामी को भूमि पर उसके अधिकार के फलस्वरूप दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति भी खेत-मजदूर की श्रम-शक्ति से होती है। किन्तु विशुद्ध लगान को निश्चित करने का तरीका भिन्न है।

विशुद्ध लगान के सिलसिले में हम देख चुके हैं कि वह अच्छी भूमि के उपयोग के लिये दिया जाता है। इससे इन जमीनों के उपयोग में एकाधिकार प्राप्त होता है। लेकिन विशुद्ध लगान केवल भूस्वामियों के एकाधिकार का फल है। भूमि पर कुछ लोगों का एकाधिकार होने की वजह से कृषि में पूँजीपतियों का प्रवेश स्वच्छन्दता के साथ नहीं हो पाता है। फलतः खेती में लगी पूँजी का दैहिक अनुपात निम्न रहता है जिससे खेती में अतिरिक्त मूल्य अधिक बड़े परिमाण में प्राप्त होता है। इस तरह कृषि में लगी पूँजी तथा अन्य पूँजी के अतिरिक्त मूल्य में जो अन्तर होता है उसी को भूस्वामी किसान से विशुद्ध लगान (एक्सोल्यूट रेंट) की शकल में वसूल कर लेता है।

औद्योगिक पूँजी तथा कृषि में लगी पूँजी के इस अन्तर को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है।

	दैहिक अनुपात	अ० मूल्य की दर	उत्पादन का मूल्य	दोनों का अन्तर या विशुद्ध लगान
स.पू. + प.पू.				
औद्योगिक पूँजी	८० + २०	१००%	८० + २० + २०	= १२०
खेती में लगी	६० + ४०	१००%	६० + ४० + ४०	१४० - १२० = २०

देखा जायगा कि कितने रुपये बैंक में जमा करने पर १०० रुपये प्रतिवर्ष मिल सकेंगे। इस हिसाब से उस खेत के दाम २००० रुपये होंगे :

कृषि में पूंजीवाद का प्रसार

पूंजीवादी लगान पर विचार करते समय मार्क्स के सामने ब्रिटेन की पूंजीवादी कृषि व्यवस्था का चित्र था। मार्क्स ने बताया कि भूस्वामियों को लगान के रूप में अतिरिक्त मूल्य का जो भाग मिलता है उसका उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है। यह धन एक शोपक वर्ग के पालन-पोषण में व्यय होता है। भूस्वामी वर्ग भूमि के उपयोग में उसी तरह बाधक होता है जिस तरह किसी खजाने पर कुंडली मार कर बैठा हुआ नाग। भूस्वामियों के कारण कृषि व्यवस्था में पूंजी के प्रवेश में बाधा पड़ती है उन्नत यंत्रों तथा साधनों का उपयोग नहीं हो पाता है।

कृषि व्यवस्था में पूंजीवाद का प्रवेश कई ढंग से होता है। अब तक योरोप के देशों में दो प्रकार से पूंजीवादी कृषि व्यवस्था ने जन्म लिया है। एक तो वे देश हैं जहां पूंजीवादी क्रान्ति के फलस्वरूप सामन्तवादी भूस्वामियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और जमीन किसानों के हाथ बेच दी गयी। फ्रांस में ऐसा हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी प्रकार तेजी के साथ पूंजीवादी कृषि व्यवस्था का विकास हुआ। सामन्तवादी वर्ग के हाथ से जमीन लेकर उसे किसानों को देने के इस तरीके को मार्क्सवादी साहित्य में पूंजीवादी कृषि के विकास का अमरीकी तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका जर्मन तरीका कहलाता है। इसमें पूंजीवादी सरकार सामन्तों के हाथ से भूमि नहीं छीनती और भूमि को किसानों के हाथ में नहीं दिया जाता बल्कि सामन्तवादी भूस्वामियों को ही पूंजीवादी किसानों के रूप में विकसित होने दिया जाता है। जर्मनी में इसी ढंग से खेती में पूंजीवाद का विकास हुआ। जर्मनी में जिन सामन्तवादी भूस्वामियों ने पूंजीवादी फार्मरों का रूप धारण किया उन्हें "जुंकर फार्मर" कहते थे।

फिर गाँव में ही बड़े धानियों के मैदानों पर काम करने हैं। मिला मजदूरों की दशा भारत के मजदूर की तुलना में खराब रहती है। उनका जीवन और भी अधिक भदें लगीके में ही है।

जिन देशों में साम्यवादी भूमिस्वामियों को धान चरके पूँजीवादी में ही जानू भी जानी है यही भी का मान में बड़े बड़े भूमिस्वामियों का विनाश हो जाता है। यह पूँजीवादी भूमिस्वामी जानते हैं जो मजदूर पर कमीन किसानों को देखते हैं यदि यह मजदूरों में काम में बड़ा कृषि-समाधान कर सकें।

भूमि पर भूमिस्वामियों का अधिकार सैदा में बड़े बड़े देशों तथा प्राथमिक प्रजाती के प्रचार में बरकरार होना है। कृषि में पूँजी लगाने के विषये भूमिस्वामियों की अनुमति आवश्यक होती है और पूँजी लगाने के बाद भी यह किसान पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें लगान के रूप में अतिरिक्त मूल्य का बँटवारा करना पड़ता है। विशुद्ध लगान का सम्बन्ध भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व में है और व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त करके ही विशुद्ध लगान को यत्न किया जा सकता है।

छोटे छोटे कृषकों का उन्मूलन कई कारणों में होता है। उनके मैदानों में अच्छी मशीनों और याद आदि का उपयोग नहीं हो पाता है जिससे उनकी पैदावार कम होती है। पूँजीवादी सरकारें कृषकों को सहायता के रूप में जो धन-राशि देती है उसका इन्वैमान बड़े बड़े फार्मर ही कर पाते हैं। बाजार में भावों का उतार-चढ़ाव भी छोटे किसानों को चीपट करता रहता है। छोटे उत्पादकों की दुर्दशा और उनका उन्मूलन पूँजीवादी विकास का एक नियम है और कृषि व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है।

पूँजीवादी कृषि व्यवस्था की एक विशेषता और भी है। यद्यपि क्षेत्रों में उत्पादन के आधुनिक तरीकों का प्रसार होता है और उत्पादकों में वृद्धि होती है फिर भी कृषि-जन्य वस्तुओं के दाम क्रमशः ऊँचे होते जाते हैं। जनसाधारण को सस्ते दामों पर अनाज नहीं मिल पाता है। कृषि में व्यक्तिगत स्वामित्व का यह एक परिणाम है।

पूँजीवादी कृषि व्यवस्था में एक ओर तो गाँव के भीतर सेन मजदूरों और किसानों के बीच अन्तर्विरोध रहता है, उनके हित आपस में टकराते हैं, दूसरी ओर गाँव और शहर के बीच अन्तर्विरोध रहता है। गाँवों का पिछड़ापन बामम रहता है और वे शहरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, जहाँ पूँजी का पड़ होता है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत होने वाली किसानों की कगाली, सेन-मजदूरों की बेकारी, गाँवों का पिछड़ापन और पूँजीपतियों द्वारा किसानों का शोषण—इन्हीं सब बातों की वजह से पूँजीवादी किसान भी इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि समाज की उन्नति के लिए पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

सातवां अध्याय | पूंजीवादी पुनरोत्पादन और शारीरिक संकट

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से पूंजीपति अपने उद्योगों या प्रतिष्ठानों के स्वामी होते हैं। वे अपने निजी लाभ की दृष्टि से उत्पादन करते हैं और इसके फलस्वरूप पूंजीवादी उत्पादन में अराजकता स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहती है। फिर भी यह सब निजी उद्योग-धन्धे और प्रतिष्ठान एक दूसरे से विलकुल असम्बन्धित तथा स्वतंत्र नहीं होते हैं। वह सामाजिक रूप में एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए पूंजी के निजी तथा सामाजिक स्वरूपों को एक साथ मिलाकर समझना होगा। समाज के विभिन्न निजी उद्योगों में जो निजी पूंजी लगी रहती है उसी के योग को सामाजिक पूंजी कहते हैं। इसी तरह से किसी निश्चित समय में समाज के विभिन्न उद्योगों में या कृषि में जो अलग-अलग पैदावार होती है उसे "कुल सामाजिक उत्पादन" (ग्रॉस सोशल प्रोडक्शन) की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह समय आम तौर से एक वर्ष का रखा जाता है और जब किसी देश के कुल सामाजिक उत्पादन के आँकड़े पेश किये जाते हैं तो उनमें एक वर्ष के कुल उत्पादन का मूल्य दिया जाता है।

सामाजिक उत्पादन में दो प्रकार की वस्तुयें शामिल हैं—(१) उत्पादन के साधन, (२) उपभोक्ता वस्तुयें। उत्पादन के साधनों के अन्तर्गत वह

मूल्य पूंजीपति को उपलब्ध होता रहे। वस्तुओं के मूल्य की उपलब्धि का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना पुनरोत्पादन चल नहीं सकता है।

वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में पूंजीपति को मिलता है और इस मुद्रा को वह पुनः पूंजी के रूप में लगा देता है, इससे उत्पादन के साधन और श्रम-शक्ति खरीदता है तथा नये सिरे से वस्तु का उत्पादन करता है। इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य तथा स्वरूप की उपलब्धि वारम्बार होती रहती है। इसे वस्तुओं की उपलब्धि (रियलाइजेशन थाफ कमोडिटीज़) कहते हैं।

समय समय पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भूकम्प आते रहते। उनका सम्बन्ध वस्तुओं की उपलब्धि से ही होता है। उत्पादन के किस क्षेत्र में वस्तुओं की मूल्य उपलब्धि न होने से उस क्षेत्र में गड़बड़ पैदा हो जाती है और उसका कुप्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। पूंजीवाद सामाजिक उत्पादन का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

साधारण पुनरोत्पादन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पुनरोत्पादन दो प्रकार का होता है—साधारण पुनरोत्पादन तथा परिवर्द्धित या विस्तारित पुनरोत्पादन। साधारण पुनरोत्पादन में एक ही पैमाने पर उत्पादन जारी रहता है। उत्पादन में लगी हुई पूंजी में अन्तर नहीं होता है और अतिरिक्त मूल्य की रकम को पूंजीपति अपने निजी खर्च के लिये इस्तेमाल करता है, उसे उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं लगाता है। अब हम देखेंगे कि साधारण पुनरोत्पादन में वस्तुओं की किस प्रकार उपलब्धि होती है तथा उत्पादन की प्रक्रिया कैसे चलती है।

सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि किसी समाज में कुल सामाजिक उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से होता है :—

(करोड़ रुपये में)

विवरण	मतत पूंजी	परिवर्तनीय पूंजी	अतिरिक्त मूल्य	कुल उत्पादन
प्रथम विभाग - ८०००		२०००	२०००	१२०००
द्वितीय विभाग - ४०००		०००	१०००	६०००

यहाँ प्रथम विभाग में ८०० करोड़ मतत पूंजी लगी है और परिवर्तनीय पूंजी २००० करोड़ रुपये है जिसमें २०० करोड़ रुपये का अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। कुल उत्पादन का मूल्य १२००० करोड़ रुपये है। जब यह मूल्य प्रथम विभाग के पूंजीपतियों को उपलब्ध होता है तो वह उनसे ८००० करोड़ रुपये की मतत पूंजी को फिर से पूरा करते हैं और २००० करोड़ रुपये मजदूरी में लगाते हैं तथा शेष २००० करोड़ रुपये अपने पास में लगाते हैं। इस प्रकार प्रथम विभाग में कुल मिला कर ४००० करोड़ रुपये द्वितीय विभाग में चले आते हैं जहाँ में मजदूर और पूंजीपति उपभोक्ता वस्तुओं खरीदते हैं तथा ८००० करोड़ रुपये उसी विभाग के पूंजीपतियों के पास उत्पादन के साधनों को नये मिररे से खरीदने के लिये रह जाते हैं।

द्वितीय विभाग में मतत पूंजी ४००० करोड़ रुपये और परिवर्तनीय पूंजी १००० करोड़ रुपये हैं। अतिरिक्त मूल्य १००० करोड़ रुपये है। कुल उत्पादन ६००० करोड़ रुपये का है। इस विभाग के मालिक उत्पादन का मूल्य उपलब्ध करके उससे १००० करोड़ रुपये के उत्पादन के साधन प्रथम विभाग में खरीदते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम विभाग से १००० करोड़ रुपये उन्हें प्राप्त हुये थे वह प्रथम विभाग के पास वापस चले गये। शेष २००० करोड़ रुपये के उत्पादन में से १००० करोड़ मजदूरी में वितरित है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं चाहिये। यह रुपया इसी विभाग के पास रह जाता है। उसी प्रकार शेष १००० करोड़ रुपये पूंजीपतियों के पास खर्च में उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में आते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण से दोनों विभागों के बीच का आदान-प्रदान स्पष्ट

हो जाता है। यदि किसी विभाग को वस्तुओं की उपलब्धि न हो सके तो उससे दूसरे विभाग को मिलने वाली रकम भी कम हो जायगी। परिणाम स्वरूप पूंजीपति या तो अपने निजी सानं में कमी करेंगे या फिर मजदूरों के वेतन में कमी करके इस रकम को पूरा करेंगे। इससे उत्पादन के साधनों पर व्यय होने वाली पूंजी भी कम हो जायगी और अन्ततः पूरा सामाजिक उत्पादन कम हो जायगा।

साधारण पुनरोत्पादन की विशेष जतन है कि उसमें प्रथम विभाग की परिवर्तनशील पूंजी और अतिरिक्त मूल्य के योग के बराबर ही द्वितीय विभाग की सतत पूंजी होती है। संक्षेप में साधारण पुनरोत्पादन में द्वितीय विभाग की सतत पूंजी = प्रथम विभाग की परिवर्तनशील पूंजी + अतिरिक्त मूल्य। परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में स्थिति इससे भिन्न होती है।

परिवर्द्धित पुनरोत्पादन

पूजीवादी अर्थव्यवस्था साधारण पुनरोत्पादन के आधार पर नहीं चल सकती है। उसका आधार परिवर्द्धित (विस्तारित) पुनरोत्पादन है।

परिवर्द्धित पुनरोत्पादन की विशेषता यह है कि इसमें अतिरिक्त मूल्य की पूरी रकम को पूंजीपति अपने व्यक्तिगत खर्च में नहीं लाते हैं बल्कि उसके एक भाग को उत्पादन-वृद्धि के लिये सतत पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के रूप में लगा देते हैं। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मशीनों और कारखानों का आकार बढ़ता जाता है। दिन प्रतिदिन अधिक बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होती है।

नीचे हम परिवर्द्धित पुनरोत्पादन और उसके अन्तर्गत वस्तुओं की उपलब्धि का एक उदाहरण दे रहे हैं। इस उदाहरण में प्रथम विभाग के पूंजीपति प्रतिवर्ष अपने अतिरिक्त मूल्य का आधा भाग उद्योग में लगा देते हैं। मान लीजिये कि चालू वर्ष में दोनों विभागों की स्थिति इस प्रकार है:—

यहाँ से उत्पादन की प्रक्रिया नाए गिरे में चानू होंगी। अब दोनों विभागों के पूँजीपति अतिरिक्त मूल्य की रकम का एक भाग उत्पादन में पूँजी के तीर पर लगा देंगे। परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में इसी तरह पूँजी का आधार बढता जाता है।

साधारण पुनरोत्पादन का विश्लेषण करते समय हम देख चुके हैं कि द्वितीय विभाग की सतत पूँजी को प्रथम विभाग की परिवर्तनशील पूँजी तथा अतिरिक्त मूल्य के योग के बराबर होना चाहिए तभी दोनों विभागों में वस्तुओं की उपनब्धि ठीक तरह से हो सकती है। परिवर्द्धित पुनरोत्पादन के अन्तर्गत वस्तुओं की उपनब्धि के लिए आवश्यक है कि द्वितीय विभाग की सतत पूँजी उस मूल्य के बराबर हो जो प्रथम विभाग के पूँजीपति परिवर्तनशील पूँजी के रूप में लगाते हैं तथा अतिरिक्त मूल्य की जो रकम प्रथम विभाग के पूँजीपतियों के पास अपने निजी उपयोग के लिये जेप रहती है यहाँ प्रथम विभाग के अतिरिक्त मूल्य का एक अंश ही द्वितीय विभाग के उत्पादन के साधनों (सतत पूँजी) में शामिल होता है। उसका दूसरा अंश प्रथम विभाग में ही पूँजी के रूप में लगा दिया जाता है।

परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में उत्पादन के साधनों में लगातार वृद्धि होती जाती है। प्रथम विभाग, जहाँ लोहा, कोयला, पेट्रोल, विजली आदि के पैदावार होती है, द्वितीय विभाग की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति में प्रगति करता है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्द्धित पुनरोत्पादन की यह प्रक्रिया सुचारुरूप से नहीं चल पाती है और बीच-बीच में उसमें उथल-पुथल हुई करती है। पूँजीवाद में उत्पादन के साधनों पर पूँजीपतियों का निरज स्वामित्व होता है। प्रत्येक पूँजीपति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये मनमाने ढंग से उत्पादन करता है जिससे वस्तुओं की पूर्ति का सही अनुपात कायम नहीं रहता। पूँजीपतियों में आपसी प्रतियोगिता भी चलती है। मजदूरों का शोषण करके वह लोग उनकी क्रय-शक्ति को कर्म कर देते

राष्ट्रीय आय का वंटवारा सबसे पहले मजदूरों और औद्योगिक पूंजीपतियों या उद्योगपतियों के बीच होता है। इसके बाद उद्योगपतियों के हिस्से की राष्ट्रीय आय का वंटवारा ब्याज, लगान आदि के रूप में अन्य पूंजीपतियों के साथ होता है। इसी आय का एक भाग उद्योगपति फिर से उत्पादन में पूंजी की भाँति लगाता है ताकि परिवर्द्धित पुनरोत्पादन हो सके।

राष्ट्रीय आय को वही लोग पैदा करते हैं जो सीधे तौर पर भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में काम करते हैं। मजदूरों, किसानों, कारीगरों तथा उत्पादन में काम करने वाले बुद्धिजीवियों के श्रम से राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है लेकिन उसका एक बड़ा अंश पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। पूंजीपतियों की आय का इस्तेमाल पूरी तरह उत्पादन वृद्धि के लिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि काफी बड़ी रकम वे अपने ऐश-आराम में ही खर्च करते हैं।

वास्तविक उत्पादकों मजदूरों, किसानों आदि के हिस्से में जो राष्ट्रीय आय पड़ती है उसका भी एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्सों के रूप में सरकार वसूल कर लेती है। सरकार पूंजीपतियों से भी टैक्स लेती है लेकिन पूंजीवादी सरकार से पूंजीपति वर्ग को लाभ होता है जबकि मेहनतकश जनता के लिये सरकार मुख्यतः दमन के अस्त्र के रूप में काम करती है। एक और

कारण यह है कि पूंजीवाद में सरकारों का खर्च लगातार बढ़ता जाता

पूँज और नौकरशाही पर जो व्यय होता है उसे

क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में

सर्वा और उनकी सरकारों के

संख्या के बहुमत की) क्रय-

लये वस्तुओं को खरीद नहीं

वस्तुओं का ढेर लग जाता है

और उत्पादन प्रक्रिया का आगे

है एक मूल कारण है।

माक्सवादी अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय आय का बँटवारा सबसे पहले मजदूरों और औद्योगिक पूंजीपतियों या उद्योगपतियों के बीच होता है। इसके बाद उद्योगपतियों के हिस्से की राष्ट्रीय आय का बँटवारा व्याज, लगान आदि के रूप में अन्य पूंजीपतियों के साथ होता है। इसी आय का एक भाग उद्योगपति फिर से उत्पादन में पूंजी की भाँति लगाता है ताकि परिवर्द्धित पुनरोत्पादन हो सके।

राष्ट्रीय आय को वही लोग पैदा करते हैं जो सीधे तौर पर भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में काम करते हैं। मजदूरों, किसानों, कारीगरों तथा उत्पादन में काम करने वाले बुद्धिजीवियों के श्रम से राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है लेकिन उसका एक बड़ा अंश पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। पूंजीपतियों की आय का इस्तेमाल पूरी तरह उत्पादन वृद्धि के लिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि काफी बड़ी रकम वे अपने ऐश-आराम में ही खर्च करते हैं।

वास्तविक उत्पादकों मजदूरों, किसानों आदि के हिस्से में जो राष्ट्रीय आय पड़ती है उसका भी एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्सों के रूप में सरकार वसूल कर लेती है। सरकार पूंजीपतियों से भी टैक्स लेती है लेकिन पूंजीवादी सरकार से पूंजीपति वर्ग को लाभ होता है जबकि मेहनतकश जनता के लिये सरकार मुख्यतः दमन के अस्त्र के रूप में काम करती है। एक और खास बात यह है कि पूंजीवाद में सरकारों का खर्च लगातार बढ़ता जाता है। उनकी पुलिस, फौज और नौकरशाही पर जो व्यय होता है उसे "अनुत्पादक व्यय" कहना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं मिलती है। पूंजीपति वर्ग और उनकी सरकारों के शोषण की वजह से श्रमिकों की (अर्थात् जनसंख्या के बहुमत की) क्रय शक्ति घटती है। वे अपनी आवश्यकता के लिये वस्तुओं को खरीद नहीं सकते। इससे बाजार में विना बिक्री हुई वस्तुओं का ढेर लग जाता है। वस्तुओं की उपलब्धि में बाधा पड़ती है और उत्पादन प्रक्रिया का आगे बढ़ना रुक जाता है। पूंजीवादी संकट का यह एक मूल कारण है।

कोरिया के युद्ध के बाद भी आर्थिक संकट आया। उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा था।

आर्थिक संकट के दौर में पूंजीवाद के अन्तर्विरोध साफ तौर से उभर कर सामने आ जाते हैं। जब पूंजीपति उत्पादन के साधनों को नष्ट करते हैं, वस्तुओं को बर्बाद करते हैं और उद्योगों को बन्द करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवाद में उत्पादन की जिन विशाल शक्तियों का विकास हुआ था वह पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के ढाँचे को पार कर गई है अब इस ढाँचे के अन्तर्गत उत्पादन की शक्तियों का विकास नहीं हो सकता है। संकट का बोझ मजदूर वर्ग को सबसे बढ़कर उठाना पड़ता है। वेका बढ़ती है और मजदूरों की दुर्दशा का लाभ उठाकर पूंजीपति उनकी उ सुविधाओं को भी वापस लेने का प्रयास करते हैं जिन्हें श्रमिक वर्ग ने व के संवर्ष के फलस्वरूप प्राप्त किया था।

कृषि का क्षेत्र भी आर्थिक संकटों की मार से अछूता नहीं बचता है औद्योगिक क्षेत्र की भाँति यहाँ भी “अत्योत्पादन” का संकट आता रहता है। इसके फलस्वरूप छोटे उत्पादकों और खेत मजदूरों की हालत बदत हो जाती है।

आर्थिक संकटों में केवल श्रमिक वर्ग बर्बादी का शिकार नहीं होता। वरन् अनेक पूंजीपति भी अपना सब कुछ खो बैठते हैं। संकटों के फलस्वरूप पूंजीपतियों का केवल एक भाग फायदा उठाता है जिसके हाथ में उत्पादन के साधन केन्द्रित होते जाते हैं। यह एकाधिकारी पूंजीपतियों (इजारेदारों) का वर्ग है।

आगे चलकर हम एकाधिकारी पूंजीवाद पर विचार करेंगे।

एकाधिकारी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद

पूँजीवादी अर्थशास्त्रज्ञों ने यह दावा किया है कि पूँजीपतियों तथा मजदूरों का बीच-बचाव करना गृहयुद्ध है। अतः पूँजीपतियों में आतंक भी उत्पन्न होता रहा है। पूँजीपतियों का यह जापसी मध्य प्रतिपत्तिता के अभाव में है किन्तु अत्यन्त पूँजीपति अर्थ में अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कर्मियों की बर्बाद करने के लिए यह बाजार में प्रवेश कर अन्य पूँजीपतियों की अगुआई में उपाय चला सकें। प्रतिपत्तिता के अभाव में बड़ी पूँजीपति टिक सकें हैं किन्तु आम अधिक पूँजीवादी अर्थ अधिक उत्पादन के माध्यम से। उनकी कृति अन्य पूँजीपतियों को बाजार में भगाना असाम्य होता है।

अतिपतितता और मध्यों की इन प्रवृत्तियों में पूँजी का केंद्रीयकरण उत्पन्न होता है। अनेक पूँजीपतियों की निम्नी पूँजी एक साथ मिलकर जब उत्पन्न में उगती है तो पूँजी का केंद्रीयकरण होता है। केंद्रीयकरण के लिए कुछ पूँजीपति तो स्वच्छतापूर्वक एक साथ मिल जाते हैं और कुछ बला-बलित्व बचाने के लिए बाध्य होकर अन्य पूँजीपतियों के साथ मिलते हैं। लाइफ्ट स्ट्राक कम्पनियों की स्थापना ने पूँजी का केंद्रीयकरण और संकुचन हो गया है।

पूँजी का केंद्रीयकरण आगे चलकर बढ़ने बढ़ने पराधिकारी पूँजीवाद उत्पन्न करता है। एकाधिकारी पूँजी अथवा इजारेवारी पूँजी तब उत्पन्न होती है जब कुछ पूँजीपति आपस में मिल कर या कोई संगठन

वनाकर किन्हीं उद्योगों पर हावी हो जाते हैं या उन उद्योगों के अधिकांश उत्पादन पर अधिकार कर लेते हैं। एकाधिकारी पूंजी के बहुत से रूप होते हैं। आज सभी उन्नत पूंजीवादी देशों में एकाधिकारी पूंजीपति मौजूद हैं और कुल मिलाकर पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था पर उन्हीं का आधिपत्य है।

एकाधिकारी पूंजी के संगठन

एकाधिकारी पूंजी के संगठन कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक संगठन कार्टेल के रूप में होता है। कार्टेल के सदस्य अपना उत्पादन अलग अलग करते हैं लेकिन आपस में समझौते से तय कर लेते हैं कि वह वस्तुओं को किन दामों पर और कौन-कौन से बाजारों में बेचेंगे। कार्टेल के भीतर बाजार का बँटवारा हो जाता है।

कार्टेल से आगे बढ़ा हुआ संगठन का स्वरूप सिण्डिकेट कहलाता है। सिण्डिकेट के सदस्य केवल अपनी वस्तुओं के भाव और बाजार ही नहीं तय करते हैं बल्कि एक ही दाम पर कच्चा माल खरीदते हैं और उनके उत्पादन की वस्तुओं की बिक्री भी सिण्डिकेट के द्वारा होती है। हमारे देश में भी पहले चीनी मिल मालिकों का सिण्डिकेट था जो बाद में टूट गया। अब उसका स्वरूप तथा नाम दूसरा है।

सिण्डिकेट से भी अधिक आगे बढ़ा हुआ और मजबूत संगठन ट्रस्ट कहलाता है। ट्रस्ट में किसी उद्योग के पूंजीपति अपनी पूंजी को एक में मिला देते हैं। उसके कारोबार का स्वामित्व ट्रस्ट के हाथ में चला जाता है और वह स्वयं उसके हिस्सेदार हो जाते हैं। एकाधिकारी पूंजी के संगठन का यह स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन में खास तौर से अधिक विकसित है।

ट्रस्ट से भी आगे बढ़ा हुआ संगठन कन्सर्न कहलाता है जिसमें एक ही उद्योग के नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों और बैंकों, बीमा कम्पनियों

लाभ प्राप्त करना । अपने मुनाफे की रकमों को बढ़ाने के लिए एकाधिकारी पूंजीपति किसानों को भी लूटते हैं । वह किसानों के हाथ अधिक दामों में औद्योगिक वस्तुयें बेचते हैं और उनसे सस्ते दामों पर कृषि जन्य वस्तुयें खरीदते हैं । जब किसानों की गरीबी बढ़ती है और वह अपनी जमीनें बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एकाधिकारी पूंजीपति इन जमीनों को हथियार लेते हैं ।

लेनिन ने बतलाया कि पूंजीवाद जब एकाधिकारी पूंजीवाद की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह साम्राज्यवाद का रूप ग्रहण कर लेता है । लेनिन ने साम्राज्यवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है :—

१—उत्पादन और पूंजी का केन्द्रीकरण विकसित होकर ऐसी ऊँच मंजिल पर पहुंच गया कि उसने एकाधिकारी पूंजीपतियों (इजारेदारियों) को जन्म दिया जो आर्थिक जीवन में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं

२—औद्योगिक पूंजी के साथ बैंक पूंजी का विलयन और इस “महाजनी पूंजी” (फाइनेन्स कैपिटल) के आधार पर एक महाजनों के गुरु की प्रधानता या महाजनी (फाइनेन्सियल ओलिगर्की) का जन्म ।

३—पूंजी का निर्यात, जो कि वस्तुओं के निर्यात से भिन्न होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है ।

४—पूंजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी संगठनों का निर्माण, जो आपस में विश्व का बँटवारा कर लेते हैं ।

५—सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्तियों के बीच सम्पूर्ण विश्व का क्षेत्रीय विभाजन पूर्ण रूप से हो जाता है ।

“साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास की वह अवस्था है जिसमें एकाधिकारियों (इजारेदारियों) और महाजनी पूंजी की प्रधानता स्थापित हो जाती है; जिसमें पूंजी का निर्यात स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है; जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों के बीच विश्व का बँटवारा आरम्भ हो जाता है;”

नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, फिर इन छोटे उद्योगों के जरिए वह अन्य उद्योगों के भी शेयर खरीदते हैं जो उनसे भी छोटे होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की एक पूरी शृंखला बन जाती है जिस पर बड़े उद्योगपतियों का अधिकार होता है।

बैंकों के साथ औद्योगिक पूंजी का सम्मिश्रण और विलयन आज वे पूंजीवादी संसार में एक मामूली सी बात हो गयी है। अमेरिका जैसे वे पूंजीवादी देश में महाजनी पूंजी ने इतना अधिक विकास कर लिया है कि महाजनी पूंजी के कुल ८ समूहों से पूरी अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है इन आठ बड़े महाजनी पूंजी के समूहों में हैं—मार्गन, राक फेलर, ड्पाण्ट, मेलन, बैंक आफ अमेरिका, शिकागो बैंक, क्लीवलैण्ड बैंक और दि फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक। इसी तरह ब्रिटेन में भी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में राष्ट्र की आर्थिक वागडोर है। ब्रिटेन के ऐसे एकाधिकारी फर्मों में इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज का नाम आता है। महाजनी पूंजी का विकास भारत में काफी हो चुका है। हमारे देश के मुख्य पूंजीपतियों में टाटा, विडला, डालमिया, सिहानिया आदि के नाम हैं। इन लोगों का औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ बैंकों पर भी नियंत्रण है।

महाजनी पूंजी का राज्य केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं सीमित रहता है। महाजनशाही पूंजीवादी राजनीतियों और सरकारों को भी अपने इशारे पर नचाती है। पूंजीवादी सरकारें महाजनी पूंजी के हित में कानून बनाती हैं, महाजनी पूंजी के विस्तार में मदद देती हैं और देश के भीतर तथा देश के बाहर महाजनी पूंजी के आधिपत्य को फैलाने में सहायक होती हैं।

पूंजी का निर्यात

एकाधिकारी पूंजी के विकास का तीसरा कदम होता है—पूंजी का निर्यात अब आगे बढ़े हुए पूंजीवादी देशों के एकाधिकारी पूंजीपति अपने देश से केवल वस्तुओं का निर्यात नहीं करते हैं बल्कि अपनी पूंजी अन्य देशों में लगाते हैं।

संसार के सभी देशों में पूजावाद का विकास साथ ही साथ और तेज गति में नहीं होता है। कुछ देश पूजावादी विकास में आगे निकल चुके हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन पूजा का निर्यात सिर्फ पिछड़े देशों को नहीं होता है। अधिक बड़े पूजावादी देशों में अपेक्षाकृत उन्नत पूजावादी देशों में भी पूजा निर्यात की जाती है। आज समुक्त राज्य अमेरिका पूजा का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है और वहाँ के पूजापति अन्य देशों में भी अपनी पूजा भेजते हैं। जापान भारत की अपेक्षा अधिक उन्नत पूजावादी देश है लेकिन वहाँ भी अमरीकी एकाधिकारी पूजा का निर्यात होता है।

पूजा का निर्यात दो तरह में होता है। इनमें से एक तरीका है "ऋण" निर्यात में पूजा भेजने का। अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों के पूजावादी महाजन अक्सर यह कहने सुने जाते हैं कि वे पिछड़े देशों को ऋण दे रहे हैं या "सहायता" दे रहे हैं। यह ऋण व्यक्तिगत रूप से पूजापतियों को दिया जाता है और सरकारों को भी दिया जाता है। आने वाले पूजापति और सरकारें इस ऋण के बढ़ने में विदेशी पूजा पेश करने वाले पूजापति और सरकारें इस ऋण के बढ़ने में निश्चित हो चुके हैं कि इन ऋण में जो उद्योग उस देश में खुलेंगे और उनमें जो लाभ होगा, उसका एक निश्चित भाग ऋण देने वाले पूजापतियों को मिला होगा। स्पष्ट है कि पूजा के निर्यात का उद्देश्य ऋण देने वालों की महायत्ना को पूरा नहीं करना बल्कि मुनाफा कमाना होता है।

पूजा का निर्यात "उत्पादक पूजा" के रूप में भी किया जाता है। उन्नत पूजावादी देशों के धनी-शाह अपने देश में कम्पनियाँ बनाते हैं जिनका उद्देश्य अन्य देशों में उद्योगों को खोलना होता है। प्रायः हम देखते हैं कि अमरीका के ब्रिटेन की कम्पनियाँ अन्य देशों में काम कर रही हैं। अमरीका की एन.बी.के. वंडुप्रम आयल कम्पनी इसकी एक मिसाल है। हमारे देश में भी अनेक कम्पनियाँ हैं जिनका लाभ उन देशों को जाता है। महाजनी पूजा

का निर्यात उत्पादक पूंजी के रूप में लाभ कमाने की दृष्टि से ही किया जाता है। पिछड़े हुये देशों में इन इजारेदारों को सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और कच्चा माल भी सस्ते दामों पर मिल जाता है। इसीलिए एकाधिकारी पूंजीपति अन्य देशों में अपने कारखाने खोलते हैं।

एकाधिकारी पूंजीपतियों के लिये पूंजी का निर्यात करना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। उनके पास इतनी अधिक पूंजी एकत्रित हो जाती है कि अपने देश की सीमाओं के भीतर उसे लाभप्रद तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। पूंजीपति अपनी रकम को बिना लाभ की आशा के जनता के जीवन को सुधारने के लिए किसी उद्योग में नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में पूंजी भेजकर वह अपने देश के मजदूरों के साथ भी अधिक सुविधापूर्वक सौदा कर सकते हैं। पूंजी के निर्यात से स्वयं उस देश के मजदूरों को लाभ नहीं होता, इससे उनको काम मिलने की सम्भावना भी कम हो जाती है।

विश्व का आर्थिक और क्षेत्रीय विभाजन

पूंजीवाद जब साम्राज्यवाद की मजिल में पहुंचता है तो पूंजीपतियों के एकधिकारी समूह विश्व के सभी देशों का बँटवारा आपस में आर्थिक रूप से कर लेते हैं। प्रायः कई देशों के पूंजीपति मिलकर निश्चय करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में अपने एकाधिकार को किस प्रकार कायम किया जाय। एकाधिकारी पूंजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी स्थापित होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। प्रथम महायुद्ध के पूर्व १९०७ ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी और जर्मनी की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने मिलकर विजली के सामान के बाजार का बँटवारा आपस में कर लिया था। इसी तरह पेट्रोल का व्यापार अमरीकी स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी और रायल डचशेल के बीच बँट गया था। रायल डचशेल में ब्रिटिश पूंजीपति साक्षीदार थे। द्वितीय महायुद्ध के

यह योरोपीय साक्षा बाजार की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य है। योरोप के पूजीवादी देशों में लोहे और कीयने के व्यापार पर योरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की इजारेदारी कायम है। यह भी एकाधिकारी पूंजीतियों का अन्तर्राष्ट्रीय मगठन है।

विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एकाधिकारी पूजीपति अनेक हथकण्डों से काम लेते हैं। वह अन्य देशों के पूजीपतियों को बाजार से भगाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े एकाधिकारी नव देशों में सस्ते दामों पर अपनी वस्तुओं का ढेर लगा देते हैं। इन्हें अंग्रेजी में डम्पिंग कहते हैं। सस्ता माल भेजने का यही तरीका जापान के पूजीपतियों ने अख्यार किया था जब १९३० ई० के बाद उन्होंने सस्ते घड़े, साइकिलों आदि का ढेर हमारे देश में लगा दिया था। उस समय एक बगानी साइकिल २० रुपये में मिलती थी और धोती का जोड़ा डेढ़ रुपये में।

सस्ता माल बेचकर एकाधिकारी पूजीपति अन्य देशों के बाजार से अपने प्रतिद्वन्दियों को भगाते हैं लेकिन इस कार्य का बोझ वह अपने देश के श्रमिक वर्ग पर डालते हैं। सस्ता माल तैयार करने के लिये मजदूरों का शोषण और भी तेज कर दिया जाता है।

विश्व के आर्थिक विभाजन में एकाधिकारी पूजीपतियों की सहायता पूंजीवादी सरकारें करती हैं। अपने देश का अन्दरूनी बाजार देशी पूजीपतियों के लिये सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकारें अन्य देशों में आने वाले वस्तुओं पर चुगी की दरें बढ़ा देती हैं। इसे सरक्षणत्मक चुगी कहते हैं। जब ही साथ सरकार की ओर से निर्यात पर चुगी दर कम कर दी जाती है ताकि देशी पूजीपति बाहर के बाजार में सस्ते दाम पर अपनी वस्तुओं बेच सकें। सरक्षणत्मक चुगी (प्रोटेक्टिव टैरिफ) की नीति पर आज-कल सभी पूंजीवादी देशों की सरकारें अमल करती हैं।

एकाधिकारी पूजीपतियों के बीच विश्व का आर्थिक बंटवारा पूरी

समूह करने के लिए विश्व का क्षेत्रीय विभाजन भी आवश्यक हो जाता है। किसी बड़े पूंजीवादी देश के इजारेदार अन्य किसी देश में स्याडे तोर से तभी अपने पौन जमा सकते हैं जब कि उन देश की सीमाओं को दूसरे देशों के एकाधिकारियों के लिए पूरी तरह बन्द कर दें। इसके लिए सम्बन्धित देश पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना जरूरी हो जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक बड़े बड़े साम्राज्यवादी देशों में पूरे विश्व का क्षेत्रीय बंटवारा कर लिया था। अन्य देशों पर कब्जा करने की दौड़ में ब्रिटेन सबसे आगे था। पश्चिमी योरोप के अन्य देशों का सम्बन्ध ब्रिटेन के बाद आता था। जर्मनी में पूंजीवाद का विकास अपेक्षाकृत बाद में हुआ था। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के पहले जर्मन एकाधिकारों की का विकास हो चुका था और उन बाजारों की बेहद आवश्यकता थी। बाजार हासिल करने के लिये उन एकाधिकारियों को अपना अन्तर्गत या जिन्होंने बाजार पर अधिकार जमा रखा था। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात हुआ।

लेनिन ने एकाधिकारी पूंजी और साम्राज्यवाद के इन चरित्र को पहलने से ही देख लिया था। लेनिन के मामलें पहलने का भी अनुभव था जो बतलाता था कि किस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुंजाल आदि के पूंजीपतियों ने बाजारों की छीना-जपटी के लिए बारम्बार युद्धों की मुहतात की है। इसलिये उन्होंने विश्व के मजदूर वर्ग को पहलने से ही साम्राज्यवादी महायुद्ध के आसन्न सकट के विरुद्ध चेतावनी दी और कहा कि सर्वहारा को साम्राज्यवादी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिये तथा साम्राज्यवादियों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाकर अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिये।

लेनिन ने कहा था कि जब तक साम्राज्यवाद कायम है तब तक युद्ध का खतरा बना रहेगा। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी और उसके सहायक देशों की पराजय हुई और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरीका तथा जापान आदि की (जो

व देन कहलाते थे) विजय हुई। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जर्मन एकाधिकारी पूंजीपतियों की इच्छा के अनुसार विश्व का पुनर्विभाजन नहीं होगा, इसके विपरीत उनके पास जो क्षेत्र (या बाजार) पहल से मौजूद हैं, वह भी उनके हाथ से निकल गये।

प्रथम महायुद्ध के अन्त के साथ ही द्वितीय महायुद्ध की नींव पड़ चुकी थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमरीका के एकाधिकारी पूंजीपति अग्रगण्य तरह से हावी हो गये थे। उन्होंने युद्ध की मूट में अपने साथी जापान को भी हिस्सा नहीं दिया था। यह निश्चित था कि आगे चलकर जब कभी जर्मनी के एकाधिकारी पूंजीपति शक्ति सग्रह कर लेंगे तो वह उक्त देशों के मूल्य को प्रवण्य चुनौती देंगे। हुआ भी ऐसा ही। जर्मनी ने एक बार ब्रिटेन की मांग गुरू कर दी। बाजारों की मांग की हिटलर ने "निवास स्थान" की मांग का नाम दिया। जर्मनी के साथ इटली और जापान जैसे देशों के एकाधिकारी पूंजीपतियों को सस्ते कच्चे माल और बाजार की दृष्टि थी। एक नया अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सतुलन स्थापित हुआ और द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ। प्रथम महायुद्ध की भाँति द्वितीय महायुद्ध भी विश्व के पुनर्विभाजन के लिये लड़ा गया था।

एकाधिकारी पूंजी के विकास के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता होती है और उपनिवेशों के लिये युद्ध अनिवार्य हो जाता है। युद्ध और एकाधिकारी पूंजी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। युद्ध की तैयारी में इजारेदारों का फायदा होता है। युद्ध काल में उन्हें मजदूरों को छुल कर लूटने का मौका मिलता है। सरकारें मजदूर आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगा देती हैं और "राष्ट्रवाद" के नाम पर एकाधिकारी पूंजी को खुली छूट दे दी जाती है।

पूंजीवाद के पतन का समय

लेनिन ने यह भी कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के पतन का घातक है। एकाधिकारी पूंजी के विकास के साथ पूंजीवाद अपने विकास की चरम अवस्था पर पहुंच गया। लेकिन पूंजी का एकाधिकारी स्वरूप

उसके पतन का प्रमाण देता है क्योंकि पूंजीवाद अपने साधनों का इस्तेमाल उत्पादन को बढ़ाने के लिये नहीं करता, वह जनता के जीवन में सुधार नहीं करता है।

साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद ने एक विश्वव्यापी व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। यह विश्वव्यापी व्यवस्था पूंजीपतियों की औपनिवेशिक नीति के आधार पर कायम हुई। इसलिये इस दौर में पूंजीवाद की शक्ति नहीं सुदृढ़ हुई वरन् उसके अन्तर्विरोध और भी अधिक तीव्र हो गये।

साम्राज्यवाद के युग में एक ओर तो साम्राज्यवादी देश के पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के बीच अन्तर्विरोध कायम रहता है दूसरी ओर उपनिवेशों की जनता और साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों के बीच एक जबर्दस्त अन्तर्विरोध चलता रहता है। इन दोनों अन्तर्विरोधों के साथ-साथ साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी पूंजीपतियों के बीच मंघर्ष चला करता है। एकाधिकारी पूंजीवाद के सभी अन्तर्विरोधों को दृष्टि में रखकर लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद को स्थायी नहीं मानना चाहिए, वह एक क्षणिक दौर है जिसके बाद सर्वहाग की क्रान्तियों का युग आने वाला है।

लेनिन की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सच निकली। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना हुई। पूंजीवाद के वह प्रचारक गलत साबित हुये जो एकाधिकारी पूंजीवाद के उत्थान में पूंजीवाद की अगजकता और अव्यवस्था का अन्त शक्ते थे और उसके मन्दिर विकास के सपने देखते थे। द्वितीय महायुद्ध आया और उसके बाद चीन तथा पूर्वी यूरोप के देशों को मिलाकर संसार की एक-तिहाई जनता ने समाजवादी सरकारें स्थापित कर लीं। भारत आजाद हुआ और एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों ने साम्राज्यवाद के जुयों को उतार फेंका। नव स्वतंत्र देशों ने साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक शोषण को भी दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब साम्राज्यवाद का अन्त निकट आ गया है।

नव-उपनिवेशवाद

सोवियत-वैदिक देशों की जनता के आन्दोलन ने साम्राज्यवाद की जड़ें हलकी हैं और साम्राज्यवादी जानते हैं कि अब उनके वह पुराने दिन लौटने की आसक्ति है। लेकिन हमने यह नतीजा नहीं निकालना जा सकता कि अब साम्राज्यवाद का धरिष बदल गया है। इस युग में साम्राज्यवादी अपना जमाना पहनकर सामने आते हैं। अब वह पहने की तरह अन्य देशों पर भी तौर पर अधिकार करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सैन्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।

बहुत से देशों को साम्राज्यवादियों ने प्रत्यक्ष रूप से "आजाद" कर चुके हैं लेकिन उन देशों में उन्होंने अपने पिच्छुओं की सरकारें बना रखी हैं। साम्राज्यवादी देशों की एकाधिकारी पूंजी के स्वार्थों की रक्षा करती हैं। दक्षिण कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका में ऐसी ही सरकारें हैं। मध्य-पूर्व के अनेक देशों में इसी तरह की सरकारें हैं।

साम्राज्यवादियों की यह नीति नई नहीं है। किन्तु इस नीति का जमाना बड़े पैमाने पर हो रहा है। लिनन ने अपनी पुस्तक "साम्राज्यवाद" में पूर्वमान को मिलाते हुए बताया था कि कुछ देश अन्य देशों को सत्तन करते हैं लेकिन वास्तव में स्वयं अन्य देशों के गुलाम होते हैं।

नव-उपनिवेशवाद की नीति के शिकार केवल वही देश नहीं होते हैं। पिछड़े हुए हैं या जिन्होंने हानि में ही आजादी हासिल की है। इस नीति के शिकार अनेक बड़े हुए पूंजीवादी देश भी हो रहे हैं। आज अमरीकी साम्राज्यवादी इस नीति के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपनी एकाधिकारी पूंजी के लिये जापान, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में जगह बनायी है। अमरीकी साम्राज्यवादी इन देशों की सार्वभौम सत्ता में भी हस्तक्षेप करते हैं।

राजकीय एकाधिकारी पूंजी और राजकीय पूंजीवाद

नाम प्राप्त करना हमेशा पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य रहा है।

एकाधिकारी पूंजी के युग में लाभ प्राप्त करने के तरीकों और साधनों में भी महान परिवर्तन हो जाता है। एकाधिकारी पूंजीपतियों को अपने प्रतिद्वन्द्वियों की प्रतियोगिता का उतना अधिक डर नहीं रहता है जितना पहले स्वतंत्र प्रतियोगिता के जमाने में पूंजीपतियों को रहा करता था। इसलिए एकाधिकारी पूंजीपति और भी बड़े पैमाने पर मुनाफे की रकमें बटोरते हैं।

पूंजीपति वर्ग हमेशा सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व की दुहाई देता है जब कभी वह कम्युनिज्म का हौवा खड़ा करता है तो यही कहता है कि कम्युनिस्ट लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति छीन लेंगे। इसीलिए बहुत से लोग उस समय आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब वह देखते हैं कि पूंजीवादी सरकारें भी राष्ट्रीयकरण की नीति का पालन कर रही है। पूंजीवाद के इस राजकीय रूप को देखकर यह खयाल पैदा होता है कि अब पूंजीवाद का चरित्र बदल गया है। भ्रम में पड़कर बहुत से समाजवादी विचारों के लोग भी कहने लगते हैं कि अब पूंजीवाद का "जनतंत्रीकरण" हो गया है या पूंजीवादी सरकारें स्वयं ही समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही हैं।

पूंजीवाद का राजकीय स्वरूप साम्राज्यवादी देशों में भी दिखाई देता है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि की सरकारें उत्पादन, व्यापार, पूंजी के निर्यात आदि को नियंत्रित करने के लिये अनेक कानून बनाती हैं। सरकार की ओर से नये कारोबार खोले जाते हैं और कभी कभी निजी क्षेत्र के किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाता है। लेकिन पूंजीवादी सरकारों के इन कदमों को समाजवाद का नाम नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में यह राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद (स्टेट मानोपॉली कॅपिटलिज्म) है।

राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद में एकाधिकारी पूंजी को प्रथम नतीजा दिया जाता है बल्कि एकाधिकारी पूंजी के साथ राजकीय उद्योगों को मिलाना दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद में सरकारें जनता से वसूल की गयी ढ़ैकों की रकम को एकाधिकारी

शक्तियों के हित में खर्च करती हैं। राजकीय धर्म में बड़ी बड़ी औद्योगिक
 उद्यम चलाई जाती हैं लेकिन उनका ठेका निजी क्षेत्र के एकाधिकारी
 शक्तियों को दे दिया जाता है। ठेकागरी को रकमों में एकाधिकारी क्षेत्र
 पूंजीपति माना जाता है। बाद में जब राजकीय क्षेत्र के यह उद्योग
 लाभकारी रूप से चलने लगते हैं तो सरकार उन्हें इजारेदारों के हाथ
 "स्वायत्त मूल्य में" (सस्ते दामों में) बेच देती है। राष्ट्रीयकरण भी
 धीरे धीरे होता है। सरकार उन्हीं उद्योगों को पूंजीपतियों से लेती
 जो अब लाभकारी नहीं रह गये हैं। इस तरह पूंजीपति घाटे में बच जाते
 हैं। कभी कभी यह भी होता है कि सरकार जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
 नहीं है उन्हें फिर पूंजीपतियों को वापस कर देती है। ब्रिटेन में द्वितीय
 महायुद्ध के बाद लेबर पार्टी की सरकार ने इसी तरह कोयले की खानों का
 राष्ट्रीयकरण किया था और बाद में इस राष्ट्रीयकरण को समाप्त
 कर दिया।

राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसके
 अन्तर्गत राजस्व या सरकार पूरी तरह में एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाथ
 में जाती है और उन्हीं के 'स्वार्थों' की देख रेख करती है। सरकार की ओर
 से पूंजीपतियों को "ऋण" और "सहायता" आदि मिलने में आसानी हो
 गयी है। इसके नियम जो कानून बनते हैं वह एकाधिकारी पूंजीपतियों के
 स्वार्थों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। सरकार भ्रष्टाचार आन्दोलन को
 दबाने के लिए अधिकाधिक हस्तक्षेप करती है। भ्रष्टाचार आन्दोलनों को
 'राष्ट्रीय हित' के विरुद्ध बताया जाता है। सरकार की मशीन में सीधे
 और पर एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रवेश होता है।
 कलाती नौकरशाही तो धाम तौर से पूंजीपति वर्ग के पिट्टुओं में भरी रहती
 है लेकिन मंत्रियों में भी बड़े-बड़े इजारेदारों के प्रतिनिधि पहुँच जाते हैं।
 ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के नेताओं में प्रायः ऐसे
 लोग मिलेंगे जो बड़े-बड़े एकाधिकारी पूंजीवादी फर्मों से सम्बन्धित हैं।
 बनरीली राष्ट्रपति केनेडी स्वयं बड़े पूंजीपति थे और उनके पास अरबों

होता है। समाजवाद के निर्माण के लिए सबसे पहले मजदूर वर्ग की सरकार की आवश्यकता होती है। जब तक मजदूर वर्ग के हाथ में राजसत्ता नहीं आती है तब तक समाजवाद की स्थापना असम्भव है।

राजकीय पूंजीवाद के सम्बन्ध में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह समाजवाद के निर्माण के लिए भौतिक परिस्थितियाँ तैयार करता है। जब श्रमिक वर्ग की सरकार कायम होगी तो उसके लिए राजकीय क्षेत्र में निर्मित उद्योगों का आधार प्राप्त हो जायगा और इन उद्योगों को जनता की सम्पत्ति बनाने के लिए उसे सवर्ष नहीं करना पड़ेगा।

लेकिन राजकीय पूंजीवाद अपने-आप ही समाजवाद में नहीं बदल जाता राजकीय पूंजीवाद में जहाँ मजदूर वर्ग की वृद्धि होती है वहीं पूंजीपतियों की भी शक्ति बढ़ती है। सरकार की ओर से उन्हें अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने तथा जनता पर बोझ लादने का रुझान दिखाई देना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी हालत में यदि मजदूर वर्ग ने पूंजीवादी सरकार के इस रुझान को न रोका तो राजकीय पूंजीवाद में प्रतिक्रियावादी तत्वों का विकास होने लगेगा और वह राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद का रूप ग्रहण कर लेगा।

ऐसे अल्प विकसित देशों में, जहाँ की सरकारों ने आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए राजकीय पूंजीवाद का रास्ता अख्तियार किया है, पूंजीवादी सरकारें देश के सामन्ती तत्वों से समझौता करने की कोशिश करती हैं और विदेशी एकाधिकारी पूंजी के साथ स्वयं साँठ-गाँठ करती हैं या देश के पूंजीपतियों को उनके साथ मिलकर "संयुक्त उद्योग" चलाने की अनुमति देती हैं। यह प्रवृत्ति खतरनाक होती है और राजकीय पूंजीवाद के प्रगतिशील पहलू को खतम कर देती है। इसी की पूरक नीति जन संगठनों और जन आन्दोलनों पर तथा विशेषतः कम्युनिस्टों पर प्रहार करने की नीति है। यदि इस नीति को अविराम गति से चलने दिया जाय तो यहाँ का राजकीय पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद में परिणत हो जायगा।

पंचम अध्याय / पूंजीवाद का शासन संकट

१९१७ ई० में रूस की क्रान्ति ने प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की, जिसे हम भाव घोषित समाजवादी नथ कहते हैं। इसके साथ ही विश्व को पूंजीवादी व्यवस्था में एक दरार पड़ गयी और पूंजीवाद के अगम गति का आरम्भ हुआ। पूंजीवाद का यह आम मकड़ लगातार गहरा होता चला है। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी योरोप में पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, हंगरी बल्गेरिया, अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी में समाजवादी सरकारें कायम हो गयीं। एशिया में चीन तथा उत्तरी कोरिया में भी क्रान्ति ने समाजवाद का मार्ग ग्रहण किया और बाद में उत्तरी वियतनाम में समाजवादी गिरि में स्थापित हो गया। इस प्रकार अब विश्व में दो तरह की सामाजिक व्यवस्थाएँ चल रही हैं। एक तरफ पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था है जिसके दिन कम पड़ते गये हैं। दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था है जिसने लगातार प्रगति की है। विश्व समाजवादी व्यवस्था का यह पूंजीवाद के वर्तमान आम संकट का सबसे मौलिक चिन्ह है।

विश्व समाजवादी व्यवस्था के जन्म से सप्तर में दो समानान्तर गति भी कायम हो गयीं। समाजवादी देशों की जनसंख्या पूरे सप्तर की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई के बराबर है। इन देशों में वह देश शामिल नहीं रहने साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी पूंजीपतियों को मुनाफा देने की पूरी आजादी मिली हुई थी। अब समाजवादी देशों के बाजार में एकाधिकारी पूंजीपतियों को अनियंत्रित रूप से प्रवेश करने की सुविधा

रूपों की जायदाद थी। अमरीकी सुरक्षा मंत्री श्री मैकनामारा फोर्ड मोटो कम्पनी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रिटेन के मंत्रियों के बारे में सभी जानते हैं कि वह जब मंत्रिमण्डल से बाहर होते हैं तो किसी न किसी बड़ी कम्पनी या बैंक के संचालक हो जाते हैं।

राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद में उत्पादन और भी अधिक बढ़े पैमाने पर केन्द्रीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ता है और सामाजिक उत्पादन बन जाता है। उत्पादन का यह समाजीकरण, यद्यपि एकाधिकारियों द्वारा अपने फायदे के लिए किया जाता है, लेकिन उनका यह कदम भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर देता है। लोगों के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि यदि पूंजीपतियों के हित में कोई सरकार उत्पादन का समाजीकरण कर सकती है तो मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के हित में भी समाजीकरण किया जा सकता है।

राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिक्रियावादी स्वरूप है। इसके अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम पूंजीपति भी एकाधिकारियों की लूट से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि एकाधिकारियों के पास विशाल पूंजी और सरकार दोनों की ही शक्ति रहती है। मध्यम और निम्न पूंजीपति क्रमशः अधिक गरीब होते जाते हैं और अन्ततः एकाधिकारी पूंजी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उनके साथ मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की सम्भावनाएँ पैदा होती हैं।

राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद तथा राजकीय पूंजीवाद (स्टेट कैपिटलिज्म) में अन्तर है। राजकीय पूंजीवाद का विकास एशिया और अफ्रीका के उन देशों में हो रहा है जिन्होंने हाल के वर्षों में स्वाधीनता प्राप्त की है। भारत, इण्डोनेशिया, श्री लंका और मिस्र इन्हीं देशों में है। राजकीय पूंजीवाद पिछड़े हुए देशों की अर्थ-व्यवस्था को साम्राज्यवादि-अथवा राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद के देशों के चंगुल से मुक्त कर

हो जाता है। अतएव राजकीय पूँजीवाद का लक्ष्य एक अर्थ में
संश्लेषण तत्त्व है।

पिछड़े हुए देशों में राजकीय पूँजीवाद का विकास इन देशों के पूँजी-
वादी तत्त्वों के स्वरूप में सम्बन्धित है। इन देशों में जब राजकीय
बड़े उद्योगों का निर्माण होता है तो मजदूर वर्ग उनका स्वागत
नहीं करता क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन उद्योगों का विकास विदेशी
पूँजीवादी पूँजी की सहायता से ही संभव है।

वह सत्य है कि जब पिछड़े देशों की पूँजीवादी सरकारें राजकीय उद्योगों
का निर्माण करती हैं तो उनके सामने पूँजीपति वर्ग का हित
होता है। इन देशों की सरकारों को पता है कि वर्तमान युग के भारी
उद्योगों का निर्माण इन पिछड़े देशों के पूँजीपतियों के उत्पन्न साधनों के बल
से ही संभव किया जा सकता है। पूँजीपतियों के निजी क्षेत्र की सहायता के
बिना राजकीय क्षेत्र की आवश्यकता है। लेकिन मजदूर वर्ग जब राज-
कीय पूँजीवाद का स्वागत करता है तो वह समाजवाद के मूल सिद्धान्त का
स्वागत करता है जिसके अनुसार उत्पादन के साधनों पर राज्य का अवकाश
समाज का अधिकार होना चाहिए। इन देशों में मजदूर वर्ग भाग लेता है
कि सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मजदूर वर्ग चाहता
है कि इस प्रकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उद्योगों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप
करने के अधिकार को मान्यता प्राप्त हो।

लेकिन मुधारवादी और संशोधनवादी राजकीय पूँजीवाद के वर्ग-चरित्र
को तथा उनकी सीमाओं को भ्रम देते हैं। वह राजकीय पूँजीवाद में
समाजवाद के निर्माण का स्वप्न देखने लगते हैं। समाजवाद के प्रति जनता
की बढ़ती हुई प्रार्थना और प्रेम को देखकर पूँजीवादी सरकारें भी अपने
राजकीय पूँजीवाद को समाजवाद का नाम प्रदान कर देती हैं।

राजकीय पूँजीवाद को समाजवाद की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती
है। समाजवादी व्यवस्था का जन्म पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं

ता है। समाजवाद के निर्माण के लिए सबसे पहले मजदूर वर्ग की सरकार की आवश्यकता होती है। जब तक मजदूर वर्ग के हाथ में राजसत्ता नहीं आती है तब तक समाजवाद की स्थापना असम्भव है।

राजकीय पूंजीवाद के सम्बन्ध में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह समाजवाद के निर्माण के लिए भौतिक परिस्थितियाँ तैयार करता है। जब श्रमिक वर्ग की सरकार कायम होगी तो उसके लिए राजकीय क्षेत्र में निर्मित उद्योगों का आधार प्राप्त हो जायगा और इन उद्योगों को जनता की सम्पत्ति बनाने के लिए उसे सवर्ष नहीं करना पड़ेगा।

लेकिन राजकीय पूंजीवाद अपने-आप ही समाजवाद में नहीं बद जाता राजकीय पूंजीवाद में जहाँ मजदूर वर्ग की वृद्धि होती है वहीं पूंजीपतियों की भी शक्ति बढ़ती है। सरकार की ओर से उन्हें अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने तथा जनता पर बोझ लादने का रुझान दिखाई देना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी हालत में यदि मजदूर वर्ग ने पूंजीवादी सरकार के इस रुझान को न रोका तो राजकीय पूंजीवाद में प्रतिक्रियावादी तत्वों का विकास होने लगेगा और वह राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद का रूप ग्रहण कर लेगा।

ऐसे अल्प विकसित देशों में, जहाँ की सरकारों ने आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए राजकीय पूंजीवाद का रास्ता अख्तियार किया है, पूंजीवादी सरकारें देश के सामन्ती तत्वों से समझौता करने की कोशिश करती हैं और विदेशी एकाधिकारी पूंजी के साथ स्वयं साँठ-गाँठ करती हैं या देश के पूंजीपतियों को उनके साथ मिलकर "संयुक्त उद्योग" चलाने की अनुमति देती हैं। यह प्रवृत्ति खतरनाक होती है और राजकीय पूंजीवाद के प्रगतिशील पहलू को खतम कर देती है। इसी की पूरक नीति जन संगठनों और जन आन्दोलनों पर तथा विशेषतः कम्युनिस्टों पर प्रहार करने की नीति है। यदि इस नीति को अविरोध गति से चलने दिया जाय तो यहाँ का राजकीय पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी राजकीय एकाधिकारी पूंजीवाद में परिणत हो जायगा।

लेखक शब्दावली | पूंजीवाद का श्राव्य संकट

१९७६ में हंगरी की जनता ने प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की, जिससे अन्य देशों में भी समाजवादी संस्थाएँ बनीं। इसके साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था में एक दरार पैदा हुई और पूंजीवाद के अन्त का आरम्भ हुआ। पूंजीवाद का यह क्रम गलत लगावार गहरा होता चला गया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरेशिया में पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमिनी, बुल्गारिया, अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी में समाजवादी सरकारें बनीं। एशिया में चीन तथा उत्तरी कोरिया में भी जनता ने समाजवाद का मार्ग ग्रहण किया और बाद में उत्तरी वियतनाम में समाजवादी निर्देश में शामिल हो गया। इस प्रकार अब विश्व में दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएँ चल रही हैं। एक तरफ पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें दिन कम पढ़ने गये हैं। दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था है जिसमें लगातार प्रगति की है। विश्व समाजवादी व्यवस्था का अन्त पूंजीवाद के अंतिम क्रम गलत का सबसे मौलिक चिह्न है।

विश्व समाजवादी व्यवस्था के जन्म में संसार में दो समानान्तर संस्थाएँ भी बनीं। समाजवादी देशों की जनसंख्या पूरे संसार की जनसंख्या के लगभग एक तिहाई के बराबर है। इन देशों में वह देश शामिल हैं जहाँ पहले साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी पूंजीपतियों को मुनाफा करने की पूरी आजादी मिली हुई थी। अब समाजवादी देशों के बाजार में उन एकाधिकारी पूंजीपतियों को अनियंत्रित रूप से प्रवेश करने की सुविधा

लगा है और जागामी कुछ वर्षों में सोवियत संघ का प्रतिव्यक्ति उत्पादन (सोविया से आगे निकल जायगा। इसी भाँति चीन का जनवादी गणतंत्र स्टेन की बराबरी करने जा रहा है।

बड़े-बड़े पूँजीवादी देश आज अपनी उत्पादन-श्रमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सामने बाजारों की समस्या है। १९६० ई० में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी लोहे की उत्पादन क्षमता के केवल ५४ प्रतिशत का उपयोग किया। अन्य पूँजीवादी देशों का भी यही हाल है। संयुक्त राज्य एक ओर तो उत्पादन को निम्नस्तर पर रखते हैं दूसरी ओर उनके देश दिन प्रतिदिन बेकारी बढ़ती जाती है। १९५९ ई० में संयुक्त राज्य अमरीका की जनसंख्या में ६१ प्रतिशत लोग पूरी तरह बेकार थे।

पूँजीवादी विचारकों का कथन था कि अब पूँजीवादी व्यवस्था को संकटों से मुक्ति मिल जायगी। प्रसिद्ध जर्जशास्त्री कीन्स तथा उसके अनुयायियों ने राजकीय एकाधिकारी पूँजीवाद को लेकर इस तरह की सुन्दर भविष्यवाणियाँ की थीं। लेकिन अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि इस दौर में पूँजीवादी संकटों का अन्त नहीं हुआ बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और पूँजीवादी "व्यापार चक्र" अर्थात् एक संकट तथा दूसरे संकट के बीच का समय और भी कम पड़ गया है। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के पूर्व पूँजीवादी संकटों के बीच का समय आम तौर से ८ से १२ वर्ष तक होता था। प्रथम महायुद्ध के बाद १९१९ ई० और १९३९ ई० के बीच में तीन बार आर्थिक संकट आया, जिसमें १९२९ ई० का आर्थिक संकट सबसे बुरा था। १९३९ ई० से १९४५ ई० तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा। उसके बाद १९४८ ई० में ही संयुक्त राज्य अमरीका को प्रथम संकट का सामना करना पड़ा। दूसरा संकट १९५३ ई० में कोरिया के युद्ध के बाद आया और तीसरा संकट १९५८ ई० में आ गया। तीनों बार अमरीका के उत्पादन में लगभग १० प्रतिशत कमी हो गयी।

पूँजीवादी व्यवस्था में संकटों का आना अनिवार्य है क्योंकि उसमें

। दोरी को काम भी मिल जाता है । नैतिक व्यव को बसाकर भी संकट
 मन्त्र नहीं किया जा सकता है । इमंग वस्तुओं को कृत्रिम मांग तो पैदा
 होती है परन्तु लोगों की स्वतन्त्रता गिर जाती है और वास्तविक मांग
 नहीं होती है । नैतिक व्यव के निचे टैक्सों का भार बसाया जाता है
 वे मुदा प्रसार किया जाता है । इन दोनों का परिणाम यह होता है कि
 गन्तव्य बनना जो वास्तविक आय गिर जाती है । आर्थिक संकट को
 दूर करने का यह तरीका अन्त में एक ओर भी बढ़े और भीषण आर्थिक
 संकट को नीचे डाल देता है ।

पूजोवाद के आम आर्थिक संकट के दौर में श्रमिक और पूजीपति वर्ग
 के बीच का अन्तर्विरोध और भी तीव्र हो जाता है । किसानों के भी जीवन-
 ण में निराशा आती है और यह पूजोवाद के अन्त में अपनी मुक्ति देखने
 लगे हैं । जनक बुद्धिजीवियों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर हो जाती है
 और वह मजदूर वर्ग के साथ आ जाते हैं । मध्यम और निम्न पूजीपतियों
 के भी राजकीय एकाधिकारी पूजोवाद के प्रति पूर्ण उत्पन्न होती है ।

इस दौर में साम्राज्यवादी देशों ने समाजवादी देशों के विरुद्ध अपनी
 एका न्यायित करने के लिये भरलक कोशिश की है । समाजवादी विचार
 देश पूजोवादी देशों के बीच का अन्तर्विरोध कायम है । फिर भी इस
 अन्तर्विरोध के कारण साम्राज्यवादी देशों के बीच का अन्तर्विरोध समाप्त
 नहीं हुआ है । इसके विपरीत, राजकीय एकाधिकारी पूजी के देशों के बीच
 अन्तर्विरोध में वृद्धि होती जा रही है ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मनुक्त राज्य अमरीका विश्व का सबसे प्रबल
 पूजोवादी देश बन गया था और उसी के नेतृत्व में सभी साम्राज्यवादी
 बनते थे । साम्राज्यवादी देशों में दो प्रकार के देश थे—वह देश जो एक
 क्षय भिन्न कर हिटलर जर्मनी के विरुद्ध लड़े थे और दूसरी ओर जर्मनी
 देश उनके मित्र देश जापान और इटली । द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की
 पराभव के फलस्वरूप जर्मनी और जापान के एकाधिकारी पूजीपति संयुक्त

दश अध्याय / समाजवाद और साम्यवाद

मार्क्स के जीवन काल में पूँजीवाद प्रगति कर रहा था। एकाधिकारी युग का जन्म हो रहा था और पूँजीवाद ने अभी तक अपनी अन्तिम मजिल नहीं प्रवेश नहीं किया था। मार्क्स ने पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों को देखा और कहा कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त अनिवार्य है। मार्क्स ने यह भी कहा पूँजीवाद के खारमे के बाद एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी और कम्युनिज्म स्थापित होगा, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मार्क्स ने यह भी बताया कि साम्यवाद की स्थापना के पूर्व समाजवाद की स्थापना होगी। समाजवाद की मजिल को पार करके ही पूँजीवाद से साम्यवाद तक पहुँचा जा सकता है। समाजवाद के अन्तर्गत प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे उसके काम के अनुसार मिलेगा।

साम्यवाद के सम्बन्ध में मार्क्स के विचार किसी कल्पना पर आधारित नहीं थे। मार्क्स ने स्पष्ट कर दिया था कि साम्यवाद की स्थापना उन सर्वोत्तम उत्पादन के साधनों की प्रगति को प्रयोग में लाकर की जायगी जिनके मादुर्भाव का ध्येय पूँजीवाद को है। मार्क्स उन लोगों से भिन्न विचार रखते थे जो पूँजीवाद की गुराइशों में तग आकर पूँजीवादी युग की वैज्ञानिक तथा शक्तिप्रिय प्रगति को तिलाजलि देकर छोटे-छोटे उत्पादकों के तथाकथित स्वर्ण-युग की बातें करते थे और इस तरह इतिहास को पीछे की दिशा में मोड़ना चाहते थे।

अधिष्य में आने वाले साम्यवादी समाज को उस आदिम साम्यवाद से भी भिन्न मानना चाहिए जिसके बीच से मानव समाज अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में गुजर चुका है। आदिम साम्यवाद उत्पादन के साधनों के पिछड़ेपन पर आधारित था जब कि साम्यवाद की स्थापना उत्पादन के साधनों की उन्नति के आधार पर होगी, जिसके बल पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

मानव के जीवन काल में समाजवाद केवल एक आदर्श के रूप में था, उसने व्यवहारिक रूप नहीं धारण किया था। अतएव उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवाद के नियमों का पूरी तरह उल्लेख नहीं किया जा सकता था। फिर भी मार्क्स ने समाजवाद और साम्यवाद के मौलिक नियमों पर प्रकाश डाला। प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन के नेतृत्व में हुई। समाजवाद के निर्माण के सम्बन्ध में लेनिन की शिक्षायें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब तो समाजवादी व्यवस्था केवल एक देश की सीमाओं के भीतर नहीं है वरन् कई देशों में उसको ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए समाजवाद के आर्थिक नियमों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा सकता है। सोवियत संघ में अब समाजवाद का निर्माण पूरा हो गया है और वहाँ साम्यवाद की रचना होने जा रही है। अतएव साम्यवाद के आर्थिक नियमों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है।

समाजवाद के सामान्य आर्थिक नियम

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था का विकास सभी देशों में एक साथ ही और समान गति से नहीं हुआ था। पूँजीवाद के विकास की असमानता से विभिन्न देशों में समाजवाद के विकास में भी विभिन्नता पैदा होती है। समाजवादी व्यवस्था का जन्म सभी देशों में एक साथ नहीं हुआ। जब पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया तो समाजवादी क्रान्ति

हे दिनों में भी परिवर्तन हुआ। मानव के समय में ऐसा अनुमान किया गया था कि पहले पहले उन्हीं देशों में समाजवाद स्थापित होगा जहाँ पूँजीवाद अधिक विकसित हो चुका था। लेकिन बाद में मार्क्स के अनुयायियों को यह विचार बदलना पड़ा। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी क्रान्ति की सबसे अधिक सम्भावना उन देशों में है जहाँ पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों ने उसे सबसे अधिक कमजोर कर दिया है। रूस ऐसे ही देशों में था। यहाँ पूँजीवाद का विकास ब्रिटेन और जर्मनी की अपेक्षा कम हुआ था लेकिन पूँजीवाद के अन्तर्विरोध अधिक तीव्र थे।

रूस की समाजवादी क्रान्ति की भाँति अन्य देशों की समाजवादी क्रान्ति भी ऐसे ही देशों में हुई जहाँ पूँजीवाद का विकास बहुत कम हुआ था। चीन तथा पूर्वी योरोप के समाजवादी देशों में पूँजीवाद ने बहुत कम शक्ति की थी।

लेनिन ने यह भी बताया था कि प्रत्येक देश की समाजवादी क्रान्ति में अपनी विशेषता होगी। क्रान्ति का लक्ष्य मौलिक रूप से समाजवाद की स्थापना होने पर भी प्रत्येक देश की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं तथा परम्पराओं को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि समाजवाद की स्थापना के लिए सभी देशों में एक साथ ही क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। किसी एक देश में भी समाजवाद का निर्माण संघर्षपूर्वक किया जा सकता है। समाजवादी क्रान्तियों के इस अनुभव ने लेनिन के कथन की उत्पत्ति सिद्ध कर दी है।

विभिन्न देशों की समाजवादी क्रान्ति की अपनी राष्ट्रीय विशेषता होती है और कम्युनिस्ट इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं लेकिन सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के कुछ मौलिक नियम हैं जो समान रूप में लागू होते हैं। इन नियमों की अपेक्षा करके समाजवाद नहीं स्थापित किया जा सकता है।

मजदूर वर्ग का अधिनायकतंत्र

पूँजीवादी व्यवस्था स्वतः समाजवाद को जन्म नहीं देती है। पूँजीवाद से समाजवाद तक पहुँचने में समय भी लगता है। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता है। समाजवाद की स्थापना की सबसे पहली शर्त यह है कि इस काम को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग का अधिनायकतंत्र स्थापित होना चाहिये। मजदूर वर्ग के अधिनायकतंत्र में ही समाजवाद का निर्माण सम्भव है। मार्क्सवादियों अथवा कम्युनिस्टों की विशेषता यही है कि वह अन्य समाजवादियों अथवा सामाजिक जनवादियों की भाँति यह नहीं मानते हैं कि किसी पूँजीवादी सरकार के निर्देशन में समाजवाद की स्थापना हो सकती है।

मजदूर वर्ग के अधिनायकतंत्र के स्वरूपों में विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुसार अन्तर हो सकता है लेकिन किसी न किसी रूप में उसे कायम करना हर देश के लिए जरूरी है। रूस में मजदूर वर्ग के अधिनायकतंत्र का स्वरूप सोवियत सरकार के तौर पर सामने आया। पूर्वी योरोप के देशों में जनता की लोकशाही कायम हुई। चीन में भी जनता की लोकशाही स्थापित हुई। वहाँ सरकार में कई दल शामिल हुये। लेकिन मौलिक रूप से जनता की लोकशाही की सरकार भी मजदूर वर्ग का अधिनायक-तंत्र है।

मजदूर वर्ग के अधिनायकतंत्र की स्थापना और उसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होता है। कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की पार्टी है। समाजवाद के लिए उसी का नेतृत्व चाहिए। पूँजीपति वर्ग की पार्टियाँ समाजवाद का नाम भले ही लें किन्तु वास्तव में वह समाजवाद से दूर रहती हैं। विभिन्न प्रकार के सुधारवादी तथा संशोधनवादी समाजवाद का नारा देते हैं किन्तु मजदूर वर्ग के अधिनायकतंत्र और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के बारे में मार्क्सवाद की शिक्षा को नहीं मानते हैं।

समाजवादी क्षेत्र का निर्माण

मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था की रचना प्रारम्भ होती है। पूँजीवाद से समाजवाद तक पहुँचने में समय लगता है। इस समयमहात्त में आर्थिक व्यवस्था के समाजवादी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है।

सर्वे व्यवस्था के समाजवादी क्षेत्र के साथ समाजवादी राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है। मजदूर वर्ग की सरकारें उत्पादन के उन माध्यमों पर अधिकार कर लेती हैं जो पहले पूँजीपति वर्ग की सम्पत्ति थे। राष्ट्रीयकरण के द्वारा समाजवादी सरकारें सबसे पहले बड़े-बड़े उद्योगों, बैंकों, बीमा कम्पनियों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने हाथ में लेती हैं। राष्ट्रीयकरण का कार्य विभिन्न देशों में पृथक् उग से हो सकता है किन्तु राष्ट्रीयकरण के बगैर समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता है।

उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व का अन्त करने और उनका समाजिककरण करने की दिशा में राष्ट्रीयकरण पहला कदम है। सोवियत पर में सरकार ने सभी उद्योगों का एक साथ ही बिना किसी प्रतिकार (मुआबिजे) के राष्ट्रीयकरण कर दिया था। चीन में केवल उन बड़े पूँजीपतियों को सम्पत्ति का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया गया जो साम्राज्यवाद के सहायक थे। अन्य पूँजीपतियों को अपना कारोबार चलाने की अनुमति दे दी गयी और बाद में उन्होंने स्वयं अपने अधिकारों को मजदूरों के मुहूर्त कर दिया क्योंकि निजी उद्योग अधिक लाभकर नहीं रह गये थे। पूर्वोत्तरोप के जनवादी देशों में बड़ा पूँजीपति वर्ग नाज़ी जर्मनी के साथ मिल गया था अतः उसकी सम्पत्ति का एकवारगी राष्ट्रीयकरण किया गया।

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप मजदूर वर्ग की सरकार के हाथ में जो उत्पादन के माध्यम प्राप्त होते हैं वह समाजवादी क्षेत्र के आधार का कार्य करते हैं। पूँजीपतियों के प्रमुख उद्योगों और बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण करने के साथ राजकीय क्षेत्र में अन्य उद्योगों का भी विकास किया जाता

है। सबसे अधिक जोर उन उद्योगों पर दिया जाता है, जिन्हें बुनियादी उद्योग कहते हैं अर्थात् वह उद्योग जिनके ऊपर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे कि—विजली के कारखाने, लोहा और इस्पात के कारखाने, यंत्र बनाने के कारखाने। बुनियादी उद्योगों की स्थापना समाजवादी क्षेत्र में होने से अन्य उद्योगों को समाजवादी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने में आसानी होती है। निजी क्षेत्र का लगातार संकुचित होना और समाजवादी क्षेत्र का विस्तार—यह दोनों ही समाजवाद के विकास के लिये आवश्यक है।

लेनिन ने बताया है कि पूंजीवाद से समाजवाद के संक्रमणकाल में पतनोन्मुख पूंजीवाद और विकासोन्मुख समाज के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। मजदूर-वर्ग-क्रान्ति के साथ पूंजीवाद की पराजय तो हो जाती है लेकिन उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं होता है। इस संक्रमणकाल में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति का निर्माण होता है, पूंजीवाद का उन्मूलन आवश्यक है।

प्रमुख-उद्योगों के समाजीकरण के बाद भी पूंजीवादी तत्वों के पनपने की सम्भावना उस समय तक रहती है जब तक कि छोटे कारीगरों अथवा दस्तकारों द्वारा निजी स्वामित्व में उत्पादन जारी रहता है। इसलिये छोटे-छोटे उद्योगों को भी समाजवादी क्षेत्र में लाना जरूरी होता है। यह काम समाजवादी सरकारें उन उद्योगों में सहकारिता को जारी करके और उन्हें सहायता देकर पूरा करती हैं। लघु उद्योगों के बारे में अपनाई गयी नीति उससे भिन्न होती है जो बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में ग्रहण की जाती है, फिर भी उसका उद्देश्य वही होता है।

देहात में कृषि के क्षेत्र में धनी किसान या बड़े फार्मर पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्यम किसानों और छोटे किसानों की स्थिति धनी किसानों से भिन्न होती है। मध्यम किसान किसी तरह अपना गुजर बसर कर पाते हैं, उन्हें अगर कभी कुछ लाभ हो गया तो कभी उतना ही घाटा भी झो जाता है। मध्यम और छोटे किसान लघु-उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं।

इस्वी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता है। समाजवादी देशों के इतिहास में भी वही बातें पाये हैं। जब इस प्रतिरोध को दबाने के लिये मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व को मरना बंदन उठाने पड़े हैं। रूस में मृत्युद के दौर में वही विचारों ने जब अपना अनाज और पशुओं को नष्ट करना शुरू किया तो बनना के लिए अनाज हासिल करने के उद्देश्य से सोवियत सरकार को "दूध कापीन साम्यवाद" या "वार कम्युनिज्म" की नीति अन्वयार करनी पड़ी। मत्तार के पूत्रीवादी समाचार पत्रों ने कहना शुरू कर दिया कि कम्युनिस्ट विचारों का अनाज छीन रहे हैं। इसके बाद जब परिस्थिति में सुधार हुआ और लेनिन ने उक्त नीति को छोड़कर 'नयीन अर्थ-नीति' ग्रहण की तब विचारों के साथ व्यापार और रियासतों का मार्ग ग्रहण किया तो वही समाचार पत्रों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कम्युनिस्टों ने अपना विचार छोड़ दिया है।

मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की सरकार यदि वही मरती करने के लिए बाध्य होती है तो उसका दोष उसी नीति पर नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए मजदूर वर्गों का प्रतिरोध ही उत्तरदायी होता है।

समाजवादी औद्योगीकरण

समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक भौतिक आधार की आवश्यकता है। यह भौतिक आधार तभी प्राप्त हो सकता है जबकि बड़े पैमाने के शक्ति उद्योगों का विकास किया जाय। समाजवादी व्यवस्था में शक्ति का यंत्रीकरण भी जरूरी है और कृषि का यंत्रीकरण तभी हो सकता है जबकि बड़े उद्योगों का काफी ऊँचा विकास किया जाय।

समाजवादी औद्योगीकरण में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। सबसे अधिक जोर उन उद्योगों पर दिया जाता है जहाँ उत्पादन के साधनों का निर्माण होता है। भारी उद्योगों के आधार पर ही पूरी अर्थ-व्यवस्था में अच्छी मशीनों और प्राविधिक प्रणाली का प्रयोग किया जा

व्यवस्था के अन्तर्गत, विद्यार्थी, नीचे का अन्तर्गत, गुरुकुल के परम्परा आदि में
 सहकारी परिवारियों की सम्मानना करने में अत्यन्त ही प्रयत्न में सहकारिता की
 भावना अत्यन्त प्रामाण्य हो जाता है। यह धारणा अत्यन्त आदिमिक समाजवादी
 समाज के विद्यार्थी को अत्यन्त आदिमिक रूप में सहकारिता के नामों से अत्यन्त
 प्रयत्न में सहकारिता की भावना अत्यन्त ही प्रयत्न में है। यदि तभी रूप में
 अत्यन्त ही सहकारिता के अन्तर्गत का अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न
 किया गया है।

समाजवादी रूप के अन्तर्गत में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में समाज-
 वादी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अन्तर्गत में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में

सहकारी रूप के अन्तर्गत में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में
 अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में अत्यन्त ही प्रयत्न में

परिस्थितियों का प्रभाव

मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व आम तौर पर उसी नीति को मानकर
 चलता है कि आर्थिक व्यवस्था में पूँजीवादी तत्वों को प्रतियोगिता के द्वारा
 उखाड़ फेंका जाय। केवल देहात के किसान ही नहीं, शहरों के लघु-उत्पादक
 भी अपने अनुभव से देख लेते हैं कि उत्पादन की समाजवादी प्रणाली छोटे
 पैमाने पर चलने वाले उत्पादन से अधिक श्रेष्ठ और लाभदायक है। वह
 स्वयं ही समाजवादी प्रणाली को स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाते हैं।

लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिये कि पूँजीवादी तत्वों की ओर

इन्हीं के अग्रभ्य को रोकेगा नया उत्पादन की भीत्र वृद्धि में सहायक होगा। इन्ही परिस्थितियों में समाजवादी औद्योगीकरण के उपर्युक्त विज्ञान लागू होंगे।

सम्पत्ति के स्वरूप

किसी समाज में उत्पादन के साधनों और उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए मनुष्यों के बीच के सम्बन्धों के आधार पर उस समाज की व्यवस्था निर्धारित होती है। पूँजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है जब कि उत्पादन करने वाले श्रमिक वर्ग का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज की सम्पत्ति होते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रमिक वर्ग स्वयं अपने उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है और उत्पादन करने में लगे हुए लोग स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं।

उत्पादन के साधनों का समाजोत्तरण होने पर जनता इन साधनों का नियंत्रण तथा उत्पादन का नियोजन अपनी सरकार (समाजवादी सरकार), सभी पार्टों और अन्य समूहों के द्वारा करती है। इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था में विभिन्न वर्गों—श्रमिक, किसान, बुद्धिजीवी आदि के स्वरूप में परिदूर्जन हो जाता है। शोषक वर्गों—पूँजीपतियों और भूमिस्वामियों—का अन्त हो जाता है।

पूँजीवाद से समाजवाद के संक्रमण काल में उत्पादन के स्वरूप कई प्रकार के होते हैं और उनमें तीव्रता से परिवर्तन होता रहता है। इस काल में एक ओर समाजवादी धर्म होता है, दूसरी ओर पूँजीवादी, तीसरी ओर छोटे उत्पादकों का धर्म। किन्तु अन्त में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित होता है और सम्पत्ति के स्वरूपों की विभिन्नता नहीं रह जाती है। सम्पत्ति का समाजवादी रूप सामने आता है।

आज सोवियत संघ में दो प्रकार की समाजवादी सम्पत्ति है—राजकीय अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सामुहिक अथवा सहकारी सम्पत्ति।

हो जाता है। अतएव पूँजीवादी व्यवस्था का यह मौलिक नियम बदल जाता है। अब उत्पादन का लक्ष्य होता है जनता की आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति करना।

समाजवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं होता है। उसकी प्राकृतिक उन्नति होती है और जीवन का स्तर उच्चतर होता जाता है। इसीसे लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की प्राविधिक प्रणाली में सुधार करके उत्पादन की वृद्धि की जाती है ताकि जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति की जा सके और लोगों के जीवन को सभी प्रकार से सुन्दर बनाया जा सके। यह समाजवादी व्यवस्था का मौलिक आर्थिक नियम है।

नियोजन अर्थव्यवस्था

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अराजकता और संकट का उल्लेख पहलें किया जा चुका है। पूँजीवाद में प्रतियोगिता के द्वारा विभिन्न उद्योगों के उत्पादन तथा वस्तुओं के मूल्य में सामंजस्य स्थापित होता है। इस प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का भयंकर विनाश होता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं चलती है। नियोजन उसका एक मौलिक नियम है। नियोजन के द्वारा विभिन्न उद्योगों के बीच का उचित अनुपात स्थिर किया जाता है। यह अनुपात उत्पादन की प्रगति के साथ बदलता रहना है परन्तु नियोजन में इसका ध्यान रखने पर पूरी अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ पैदा हो सकती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक केन्द्रीयकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। केन्द्रीयकरण न होने पर विभिन्न उद्योगों में स्थानीयता की भावना पैदा होने का भय है और पूरे समाज के हित पीछे छूट जायेंगे। किन्तु केन्द्रीयकरण का अर्थ यह कदापि नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों की सुविधा का ध्यान न रखा जाय अथवा उनकी विशेष क्षमता का उपयोग न किया जाय। अतएव केन्द्रीयकरण के साथ जनवादी तरीके से भी काम लेना

राजकीय अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति समाजवादी सम्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है किन्तु सामुहिक अथवा सहकारी सम्पत्ति के साथ उनका कोई विरोध नहीं है। मौलिक रूप से दोनों की गणना समाजवादी सम्पत्ति के अन्तर्गत होती है। सहकारी समितियों का निर्माण पूंजीवादी देशों में भी होता है किन्तु वहाँ यह समितियाँ समाजवादी सम्पत्ति को जन्म नहीं देती है बल्कि पूंजीवादी सम्पत्ति के विक्रम में सहायक होती है। समाजवादी देशों में राजमत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में रहती है और उत्पादन प्रमुख रूप से समाजवादी क्षेत्र में होता है अतएव सहकारी समितियाँ समाजवाद के विक्रम में सहायक होती हैं।

यहाँ यह देखा भी जरूरी है कि राष्ट्रीयकरण उत्पादन के बुनियादी साधनों का होता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति समाजवाद के दौर में भी कायम रहती है। इस व्यक्तिगत सम्पत्ति (परमर्नल प्रापर्टी) की उत्पत्ति समाजवाद के उस नियम के कारण होती है जिनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है और उसे उतने काम के अनुसार प्राप्त होता है। लोग अपने प्राप्त वेतन को बचन के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं। सामुहिक खेती करने वाले किसानों के अपने मकान होते हैं; वह अपनी थोड़ी सी जमीन पर व्यक्तिगत रूप से खेती कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए लोग वस्तुएँ खरीद सकते हैं, जैसे रेडियो वगैरह, और यह वस्तुएँ उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाती हैं। किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति की सीमा होती है और उसका इस्तेमाल दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

समाजवाद का मौलिक नियम

पूँजीवादी समाज में उत्पादन का लक्ष्य होता है पूँजीपतियों के लिए अधिक से अधिक मुनाफे का प्रवन्ध करना। इस लिए हम कहते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था का मौलिक नियम है—लाभ कमाना।

समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व

ले जाता है। अतएव पूंजीवादी व्यवस्था का यह मौलिक नियम बदल जाता है। अब उत्पादन का लक्ष्य होता है जनता की आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति करना।

समाजवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं होता है। उसकी मनुष्यवृद्धि उपरान्त होती है और श्रम का स्तर उच्चतर होता जाता है। जिन्हें लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की प्रतिअधिक प्रणाली में गुणानुसार उत्पादन की वृद्धि की जाती है ताकि जनता को बढ़ती हुई आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ति की जा सके और लोगों के जीवन को मजबूत प्रकार में सुन्दर बनाया जा सके। यह समाजवादी व्यवस्था का मौलिक आर्थिक नियम है।

नियोजन अर्थव्यवस्था

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असावधान और गड़बड़ का उल्लेख पहले किया जा चुका है। पूंजीवाद में प्रतियोगिता के द्वारा विभिन्न उद्योगों के उत्पादन तथा वस्तुओं के मूल्य में सामंजस्य स्थापित होता है। इस प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का भयंकर विनाश होता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं चलती है। नियोजन अपना एक मौलिक नियम है। नियोजन के द्वारा विभिन्न उद्योगों के बीच का उचित अनुपात स्थिर किया जाता है। यह अनुपात उत्पादन की प्रगति के साथ बदलता रहना है परन्तु नियोजन में इसका ध्यान रखने पर पूरी तरह व्यवस्था में गड़बड़ पैदा हो सकती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक केन्द्रीयकरण अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है। केन्द्रीयकरण न होने पर विभिन्न उद्योगों में स्थानीयता ही भावना पैदा होने का भय है और पूरे समाज के हित पीछे छूट जायेंगे। केन्द्रीयकरण का अर्थ यह यदापि नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों की सुविधा में ध्यान न रखा जाय अथवा उनकी विशेष क्षमता का उपयोग न किया जाय। अतएव केन्द्रीयकरण के साथ जनवादी तरीके से भी काम लेना

आवश्यक होता है। समाजवादी नियोजन जनवादी केंद्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर होता है।

केवल नियोजन के सिद्धान्त ही स्वीकार कर लेना काफी नहीं होता है। यदि नियोजन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम न लिया जाय और अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समी-सही डिमांड फिताव न रखा जाय और नियंत्रण न रखा जाय तो नियोजन सफल नहीं हो सकता। नियोजन की सफलता के लिये यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि उत्पादन की शक्तियों के एक भाग के रूप में मनुष्य की श्रम-शक्ति का किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग किया जाय। समाजवादी सरकार नियोजन के तरीकों में लगातार सुधार करती रहनी है।

वस्तु-उत्पादन—मूल्य वा नियम—व्यापार

समाजवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व समाप्त हो जाता है। पूंजीपति वर्ग नहीं रहता है और छोटे छोटे उत्पादक भी नहीं रहते हैं। किन्तु वस्तु-उत्पादन की प्रणाली कायम रहती है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वस्तु उत्पादन का अर्थ है बाजार में बेचने के लिए उत्पादन। वस्तु में दो गुण होते हैं—उपयोगिता और विनिमय मूल्य। पूंजीपति को मुख्यतः वस्तुओं के विनिमय मूल्य से सम्बन्ध रहता है क्योंकि उसका उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं के दोना प्रकार के मूल्य की ओर बराबर ध्यान दिया जाता है—उनके उपयोगिता मूल्य और विनिमय-मूल्य दोनों की ओर।

वस्तुओं के विनिमय का माध्यम मुद्रा है। मुद्रा और वस्तु का सम्बन्ध समाजवाद में चला करता है। सामाजिक उत्पादन में काम करने वालों को काम के बदले में मुद्रा प्राप्त होती है और वह मुद्रा देकर वस्तुयें प्राप्त करते हैं। उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के बीच भी वस्तुओं का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। यदि किसी सामुहिक फार्म से अनाज लिया

मार्क्सवादी अर्थशास्त्र

गता है तो उसके बदले में फार्म को मुद्रा प्राप्त होती है और उस मुद्रा के द्वारा सामुहिक फार्म अपनी आवश्यकता की वस्तुयें प्राप्त करता है।

मुद्रा और वस्तु के सम्बन्ध से लोगों को थम करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह राज्य के हाथ में समाजवादी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन होता है।

वस्तु-उत्पादन के साथ मूल्य के नियम का सम्बन्ध है। समाजवाद में मूल्य का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक रूप से आवश्यक थम के द्वारा निर्धारित होता है किन्तु मूल्य के नियम की वह भूमिका नहीं रह जाती जो पूंजीवाद के युग में रहती है। पूंजीवादी व्यवस्था में मूल्य का नियम स्वतःस्फूर्त ढंग में निश्चित कर देता है कि किन उद्योगों में कितनी पूंजी खेरी, किन्तु समाजवाद के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में पूंजी का बँटवारा विशेषज्ञ के द्वारा होता है जिसमें उद्योगों के बीच के अनुपात पर ध्यान रखा जाता है।

समाजवाद में वस्तुओं के दाम उनके मूल्य के अनुसार तय होते हैं, किन्तु यह दाम पहले से एक योजना के मातहत निश्चित किये जाते हैं। बाजार में जाकर वस्तुओं का मूल्य निश्चिन नहीं होता है वरन् उत्पादन के ढंग में ही निश्चित होता है।

मूल्य के नियम का प्रभाव यह होना है कि उत्पादन को नती माध्यामों के लागत व्यय कम करने की कोशिश की जाती है। लागत व्यय को कम करने का तरीका है यांत्रिक और प्राविधिक सुधार, कच्चे माल का अधिक अच्छा उपयोग करना और अन्य तरीकों से कम थम के द्वारा अधिक वस्तुयें पैदा करना। लागत व्यय को कम करके उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।

जब हम उत्पादन को लाभप्रद बनाने की बात करते हैं तो उसने समाजवाद के नियमों का खण्डन नहीं होता है। समाजवादी उद्योगों में भी

कहा जा सकता है कि मजदूरों का वेतन उत्पादन के अनुपात में बढ़ेगा उत्पादन से अधिक नहीं बढ़ सकता है। इस परिस्थिति में श्रमिकगण स्वयं उत्पादन बढ़ाने में रुचि रखते हैं।

उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से समाजवादी व्यवस्था को एक मुविधा यह प्राप्त है कि उसमें श्रम का सामाजिक विभाजन नियोजित ढंग से हो सकता है। पूंजीवाद में बाजार की परिस्थितियों के आधार पर स्वयं-रहून ढंग से विभिन्न उद्योगों के बीच पूंजी का वितरण होता है। यदि बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो गयी और आर्थिक संकट आ गया तो पूंजीपति वर्ग उत्पादन घटाने में दिव्यचक्षुसी लेता है। समाजवाद में संकटों के भय से छुटकारा मिल जाता है इसलिये उत्पादन गिगने या उत्पादन के साधनों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं उत्पन्न होती है।

श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समाजवाद में लगातार विज्ञान की उन्नति पर जोर दिया जाता है ताकि उत्पादन के साधनों को सुधारने के लिए उसका उपयोग किया जा सके। मजदूरों की जिंदा और जीवन स्थिति के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वह अधिक कार्य-कुशल हो जायें। इसके साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया में सामयिक रूप से अनुकूल परिवर्तन किये जाते हैं।

परिवर्द्धित पुनरोत्पादन

माक्स ने बताया कि पुनरोत्पादन दो प्रकार का होता है—साधारण पुनरोत्पादन और परिवर्द्धित अथवा विस्तारित पुनरोत्पादन। पुनरोत्पादन पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक उत्पादन के दो विभाग होते हैं। प्रथम विभाग में उत्पादन के साधन आते हैं और द्वितीय विभाग में उपभोक्ता वस्तुयें आती हैं। इन्हीं दोनों विभागों के पारस्परिक

माक्सवादी अर्थशास्त्र

समुदाय के आकार पर निर्भर होता है कि पुनरोत्पादन किस प्रकार का है। परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में प्रथम विभाग के उत्पादन का अनुपात द्वितीय विभाग की तुलना में गणनाएँ बढ़ा जाते हैं, प्रथम विभाग के उत्पादन की मापमिक्ता ही जाती है।

समाजवाद में परिवर्द्धित पुनरोत्पादन होता है। विन्डु समाजवाद के परिवर्द्धित पुनरोत्पादन और पूँजीवाद के परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में मौलिक अंतर है। समाजवादी परिवर्द्धित पुनरोत्पादन बाजार की उपज घुपन और बाजारगत के द्वारा नहीं निर्धारित होता है बल्कि उनमें दोनों विभागों के बीच का अनुपात एक योजना के माध्यम निर्धारित किया जाता है।

पूँजीवाद में राष्ट्रीय आय का एक भाग पूँजीपतियों के पास जाता रहता है और वह उनका इन्वैस्मन्ट अथवा ऐन-आ-नाम के लिए करते हैं। समाजवाद में राष्ट्रीय आय का अन्वेषण कम जाता है और उसे परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में लगाया जा सकता है। समाजवाद में परिवर्द्धित पुनरोत्पादन में समाजवादी बढ जाती है।

पूँजीवाद में परिवर्द्धित पुनरोत्पादन का मुख्य पूँजीपति वर्ग के लाभ का हाना होता है। समाजवाद में उनमें पूरे समाज को लाभ होता है। अन्वेषण जनता की अन्वेषण बढ़ती जाती है। फलतः समाजवाद में आयिक अंतर नहीं बढ़ता है। परिवर्द्धित पुनरोत्पादन से समाजवादी व्यवस्था सतत रूप से मजबूत होती जाती है जबकि पूँजीवाद में परिवर्द्धित पुनरोत्पादन के फलस्वरूप आन्तरिक अन्वेषण ही हो जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ती जाती है।

सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्द्धित पुनरोत्पादन का प्रभाव भी बदल जाता है। इस अर्थ को हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए।

आज समाजवादी अर्थव्यवस्था संसार के कई देशों में स्थापित हो चुकी है। इस प्रकार समाजवाद ने एक विश्व व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। समाजवादी देशों के आर्थिक सम्बन्ध एक ओर तो आपस में अर्थात् अन्य समाजवादी देशों से कायम होते हैं दूसरी ओर उनके आर्थिक सम्बन्ध पूंजीवादी देशों के साथ भी कायम होते हैं।

समाजवादी देशों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों का क्या आधार होगा इसका उल्लेख ८२ कम्युनिस्ट पार्टियों के मास्को घोषणापत्र में किया गया है। इस घोषणापत्र में कहा गया है कि समाजवादी देशों के आपसी आर्थिक सम्बन्धों का आधार होगा पारस्परिक सहयोग और सहायता। जिन देशों में समाजवादी व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो गयी है वह नये और पिछड़े हुए समाजवादी देशों की सहायता करते हैं, उन्हें आर्थिक और प्राविधिक सहायता पहुँचाते हैं। समाजवादी देशों में वैज्ञानिक जानकारी का आदान प्रदान चलता रहता है जिससे उन्हें प्रगति करने में आसानी हो जाती है।

समाजवादी देश इस सिद्धान्त को भी मानते हैं कि उन्हें आपस में श्रम का विभाजन करना चाहिए और अपने उद्योगों के बीच में उचित अनुपात कायम करना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार हर देश को उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका विकास वह अधिक सुविधा के साथ कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का लक्ष्य होगा समाजवादी देशों के साधनों को बचाना और उनका अधिक सदुपयोग करना। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक देश केवल कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करे और पिछड़े हुये देशों का सर्वाङ्गीण आर्थिक विकास न हो तथा वह उन्नत देशों के ऊपर निर्भर हो जायें।

समाजवादी देशों के आर्थिक सम्बन्धों में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। वह आपस में व्यापार करते हैं और वस्तुओं के दाम उनके अन्तर्राष्ट्रीय

दलों के सम्मुख बन कर रहे हैं। जहाँ भी पूँजीवादी दलों के साथ उनका झटका देखा जा सकता है क्योंकि समाजवादी दल जब अपनी वस्तुओं का जब निश्चित करने हैं तो पूँजीवादी दलों की तरह उनके दामों पर सेयर-मार्केट का असर नहीं पड़ता है। इन दलों में स्थिरता होती है और उन पर अतिरिक्त महारा के प्रभाव का असर नहीं रहता है।

पूँजीवादी दलों के साथ समाजवादी दलों के सम्बन्ध दूसरे प्रकार के होते हैं। पूँजीवादी दल भी दो प्रकार के हैं—एक तो भाग बड़े हुए साम्राज्यवादी दल हैं जहाँ महाप्रियता पूँजी का बोन बाना है और दूसरी ओर वह पूँजीवादी दल हैं जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा करना चाहते हैं और साम्राज्यवादी भाग्य में मुक्त होकर अपनी अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। प्रथम पक्षों के उभरते पूँजीवादी दलों के साथ समाजवादी दल सामाजिक और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा उनकी पूँजीवादी व्यवस्था को परास्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पिछड़े हुए पूँजीवादी दलों की ओर विश्व दृष्टिकोण में काम लिया जाता है। समाजवादी दल इनको अपना सम्भव महात्मा प्रदान करते हैं ताकि वह स्वतंत्र रूप में अपनी अर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर सकें। यद्यपि भी पूँजीवादी दलों के प्रति समाजवादी दलों की पूरी आधिकारिक नीति होती है।

×

×

×

×

समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण

समाजवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। उसमें गति-शील नहीं हो सकता है। समाजवाद स्वयं एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है। उसे पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच की सीढ़ी कहना चाहिए। पूँजीवाद से

साम्यवाद तक जाने के लिए सभी देशों को अनिवार्य रूप से समाजवाद की सीढ़ी पार करनी होगी यद्यपि समाजवादी व्यवस्था में आने के लिए पूंजीवाद के बीच से गुजरना अनिवार्य नहीं रहा है। मंगोलियाई गणतंत्र जैसे देश ने पूंजीवाद में पदार्पण किये बगैर ही समाजवाद का निर्माण कर लिया है।

समाजवाद और साम्यवाद—यह दोनों एक दूसरे की विरोधी व्यवस्थाएँ नहीं हैं जिम प्रकार कि पूंजीवाद और समाजवाद हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक समाजवाद का विरोध करते हैं और उसको रोकने की चेष्टा करते हैं। इसलिये इन दोनों व्यवस्थाओं के समर्थकों के बीच संघर्ष होता है। समाजवाद से साम्यवाद में जाने के लिये संघर्ष या उग्र सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होगी। समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण पूरे समाज के हित में होगा। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण की प्रक्रिया क्रमशः चलेगी।

अभी तक विश्व का केवल एक ऐसा देश है जहाँ समाजवाद का निर्माण हो चुका है और जिसने अब साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य अपने सामने रखा है। यहाँ अभी साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ है इसलिए साम्यवाद के पूरे आर्थिक नियमों की जानकारी हासिल करना अभी सम्भव नहीं है। फिर भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने साम्यवादी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ मास्यताओं को स्वीकार किया है जिनका उल्लेख करना जरूरी है।

साम्यवाद लगभग साथ-साथ आयेगा

पूँजीवाद का विकास विभिन्न देशों में साथ-साथ नहीं हुआ था। लेनिन ने पूँजीवाद के विकास की असमानता को दिखाते हुए कहा था कि भविष्य में समाजवादी क्रान्तियाँ भी साथ साथ नहीं होंगी, उनके समय में

काफ़ी अन्तर हो सकता है। यही हुआ भी। मोवियत मघ और अन्य देशों की श्रान्ति में लगभग ३० वर्षों का अन्तर था। उनमें समाजवाद की स्थापना भी बहुत आगे पीछे हुई। लेकिन समाजवाद से साम्यवाद में सक्रमण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की धारणा यह है कि सभी समाजवादी देश कमोबेश साथ साथ साम्यवाद स्थापित करेंगे। मास्को में होने वाले २१ कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मेलन के घोषणा पत्र में कहा गया है.—

“समाजवादी विश्व आर्थिक व्यवस्था उत्पादन के एक जैसे समाजवादी सम्बन्धों में संयुक्त है और समाजवाद के आर्थिक नियमों के आधार पर विकसित हो रही है। इसके सफल विक्रम के लिए जरूरी है कि समाजवादी निर्माण में नियोजित, मानुषात्मिक विक्रम के नियमों को लगातार लागू किया जाय, जनता की सृजनात्मक पहल कदमी को बढ़ावा दिया जाय, राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के समन्वय के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की प्रणाली में लगातार सुधार किये जायें, विश्व समाजवादी व्यवस्था में स्वेच्छित सहयोग, पारस्परिक लाभ और बँजानिक व प्राविधिक स्तरों में ज़बरदस्त सुधार के आधार पर उत्पादन में विशेषज्ञता और महयोंग को लागू किया जाय। इसके लिये जरूरी है कि सामुहिक अनुभव का अध्ययन किया जाय; एक-दूसरे के सहयोग और बन्धुत्वपूर्ण पारस्परिक सहायता को बढ़ाया जाय; इस आधार पर आर्थिक विकास के स्तरों की ऐतिहासिक भिन्नता को धीरे-धीरे खत्म किया जाय, समाजवादी व्यवस्था के सभी जनगण के कम्युनिज्म की ओर लगभग एक साथ सक्रमण के लिए भौतिक आधार तैयार किये जायें।”

साम्यवाद का आर्थिक आधार

साम्यवाद की परिभाषा करते हुए पीछे बताया जा चुका है कि साम्यवाद में प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। इसका अर्थ है कि साम्यवादी

व्यवस्था में समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होंगे। स्वभावतः इस प्रकार की व्यवस्था का आर्थिक आधार उत्पादन के साधनों के अत्यन्त उच्च विकास के ऊपर ही हो सकता है। उत्पादन के साधनों की उन्नति के बिना समाज में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन इस सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है जहाँ सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

साम्यवाद की स्थापना के लिए श्रम की उत्पादकता में और भी अधिक वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए यंत्रों में सुधार करना होगा और अभी जिन उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए यंत्र नहीं हैं उनके लिये भी यंत्र बनाने होंगे। यांत्रिक सुधार के लिए स्वचालित यंत्रों का लक्ष्य सामने रखते प्रत्येक समाजवादी देश के लिए जरूरी है ताकि वह समाजवाद से अभी बचकर साम्यवाद की मंजिल में प्रवेश कर सके। आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में यंत्रों का लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युत् शक्ति की जरूरत होती है। अब आणविक शक्ति का प्रयोग विद्युत् शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगा। उत्पादन के साधनों की वृद्धि के लिए जिन प्राकृतिक वस्तुओं की जगह पर मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से काम लिया होगा। इस तरह सच्चे मान की कमी दूर होगी। रसायन-शास्त्र ने इन दिशा में लक्ष्मी प्रगति कर ली है और अनेक वस्तुओं का कुशल उत्पादन होने लगा है। भविष्य में उन प्रकार की वस्तुओं और भी बड़े पैमाने पर बनेगी।

उत्पादन वृद्धि के लिए यांत्रिक और प्राविधिक उन्नति के साथ ही उत्पादन प्रणाली के संगठन की भी आवश्यकता होती है। भविष्य में उत्पादन के संगठन में संगठनार सुधारों की आवश्यकता होगी। इसके द्वारा समाज व्यवस्था में सुधार लाये जा सकेंगे।

दोषरु वर्गों की समाज में विशेष मुविधा प्राप्त रहती है। समाजवाद में दोषरु वर्गों का अन्त हो जाता है। इस लिए वर्गों का विरोध भी समाप्त हो जाता है। फिर भी समाज में वर्ग रहने हैं, मजदूर और किसान होते हैं तथा बुद्धि शीली वर्ग भी होता है। इन वर्गों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता होती है। साम्यवाद में यह वर्गीकरण भी समाप्त हो जायगा।

वैज्ञानिक उपनि के साथ मनीनों का गुणार सम्बन्धित है। उपनि यंत्रों के मचालन के लिए मजदूरों में वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिये। इसके साथ साथ स्वचालित यंत्रों का प्रयोग मजदूरों के शारीरिक श्रम को कम कर देना क्योंकि उनका काम मुख्यतः स्वचालित मनीनों का नियंत्रण करना रह जायगा।

पूँजीवाद में शहर और गाँव के बीच एक अन्तर्विरोध चलता करता है। समाजवाद में शहर और गाँव के बीच कोई विरोध नहीं रहता है किन्तु फिर भी शहर और गाँव में अन्तर रहता है। यह अन्तर विशेषतः सांस्कृतिक क्षेत्र में तथा जीवन की सुविधाओं में दृष्टिगोचर होता है। साम्यवाद में इन उत्पादन में यंत्रों का पूरी तरह प्रचलन हो जायगा, जिनमें किसानों के काम के डग में मौनिक परिवर्तन हो जायगा। अब कृषि भी अन्य उद्योगों की तरह एक उद्योग बन जायगी। काम के तरीकों का भेद मिट जाने से शहर और गाँव का भेद खतम होगा।

समाजवाद में दो प्रकार की सामाजिक सम्पत्ति रहती है—राजकीय सम्पत्ति और सहकारी सम्पत्ति। पहले कहा जा चुका है कि राजकीय सम्पत्ति समाजवादी सम्पत्ति का उच्चतर स्वरूप है। यद्यपि सहकारी सम्पत्ति का राजकीय सम्पत्ति में कोई विरोध नहीं होता है किन्तु सहकारी सम्पत्ति पूँजीवादी युग की निजी सम्पत्ति के अवशेष के रूप में रहती है। साम्यवाद में सम्पत्ति का यह विभेद समाप्त हो जायगा और एकमात्र सामाजिक सम्पत्ति शेष रह जायगी। सामाजिक विभेद को समाप्त करने के लिए सम्पत्ति का विभेद समाप्त होना चाहिये।



हड़ बाने और नामाधिक सम्प्रदा के सभी गोतो के अधिक बंग से प्रवाह-
 दन होने के बाद—बैसाद तब जाकर ही पूजीवारी अधिकार के सकीर्ण
 दिवित्र को पुनतः नोपा जा मरेगा और समाज अपनी पताकाओं पर
 हदित कर मरेगा : "हर किसी न उसरी योग्यतानुसार, हर किसी को
 उसी क्षम्यतानुसार !"

^

^

^

×

उब मानने ने उगर्तुक्त लब्ध निगे धे उस समय समाजवाद एक स्वप्न
 सा । जाब समाजवाद ने एक विश्व व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है ।
 दिन दना मे नही तरु पूजीवाद कायम हे, जैसे कि हमारे देश मे, वही की
 रता भी समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है । वह दिन अधिक दूर
 नही हे जबकि पूरे विश्व मे एक ही व्यवस्था होती—समाजवादी व्यवस्था ।
 समाजवादनिश्चित रूप मे मानरना को अगनी मजिन की ओर ले जायगा—
 समाजवाद की ओर ।

नवीन मानव का उदय

साम्यवाद के युग में श्रम की ओर मनुष्य का दृष्टिकोण मौलिक रूप से परिवर्तित हो जायगा। मनुष्य अपने समाज का प्रबन्ध जोर-जबर्दस्ती के आधार पर नहीं बरन् स्वेच्छा के आधार पर करेंगे। मनुष्य श्रम को अपने जीवन की आवश्यकता के रूप में देखेंगे। मनुष्य को अपने जीवन-यापन के लिए कम से कम श्रम करना पड़ेगा और उसे अपने सांस्कृतिक उत्थान का अधिकतम अवसर प्राप्त होगा। इस युग में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच का अन्तर मिट जायगा। यंत्रों की उत्पत्ति और उनके उपयोग के कारण श्रम के अनेक रूप जिन्हें आज हेय समझा जाता है वह भी समान रूप से सम्माननीय हो जायेंगे।

साम्यवाद में नारी जाति को पूर्ण अर्थ में समानता का अधिकार मिलेगा। समाजवाद में स्त्रियों को समान रूप से काम और वेतन का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु जब तक घर-गृहस्थी के कामों का बोझ हलका नहीं होता तब तक नारी जाति के जीवन में पूर्ण रूप से समानता नहीं लाई जा सकती है। साम्यवाद में न केवल यंत्रों के उपयोग से बल्कि जीवन के सामुहिक संगठन के फलस्वरूप गृहस्थी का बोझ स्त्रियों के लिए कष्टदायक नहीं रह जायगा।

साम्यवाद में मानव का जीवन कैसा होगा और इस युग का नवीन मानव किस प्रकार का होगा इसका चित्र मार्क्स के निम्नलिखित उद्धरण से मिलता है :—

“कम्युनिस्ट समाज की उच्चतर अवस्था में, व्यक्ति की श्रम-विभाजन के प्रति दासत्वपूर्ण अधीनता और उसी के साथ साथ मानसिक तथा शारीरिक श्रम के अन्तर्विरोध का लोप हो जाने के बाद, श्रम के जीवन के मात्र एक साधन ही नहीं, प्रत्युत जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता बन चुकने के बाद; व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास के साथ-साथ उत्पादक शक्तियों के भी

नवीन मानव का उदय

साम्यवाद के युग में श्रम की ओर मनुष्य का दृष्टिकोण मौलिक रूप से परिवर्तित हो जायगा। मनुष्य अपने समाज का प्रबन्ध जोर-जबरदस्ती के आधार पर नहीं बरन् स्वेच्छा के आधार पर करेंगे। मनुष्य श्रम को अपने जीवन की आवश्यकता के रूप में देखेंगे। मनुष्य को अपने जीवन-यापन के लिए कम से कम श्रम करना पड़ेगा और उसे अपने मांस्कृतिक उत्थान का अधिकतम अवसर प्राप्त होगा। उस युग में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच का अन्तर मिट जायगा। यंत्रों की उत्पत्ति और उनके उपयोग के कारण श्रम के अनेक रूप जिन्हें आज हेय समझा जाता है वह भी समान रूप से सम्माननीय हो जायेंगे।

साम्यवाद में नारी जाति को पूर्ण अर्थ में समानता का अधिकार मिलेगा। समाजवाद में स्त्रियों को समान रूप से काम और वेतन का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु जब तक घर-गृहस्थी के कामों का बोझ हलका नहीं होता तब तक नारी जाति के जीवन में पूर्ण रूप से समानता नहीं लाई जा सकती है। साम्यवाद में न केवल यंत्रों के उपयोग से बल्कि जीवन के सामुहिक संगठन के फलस्वरूप गृहस्थी का बोझ स्त्रियों के लिए कष्टदायक नहीं रह जायगा।

साम्यवाद में मानव का जीवन कैसा होगा और इस युग का नवीन मानव किस प्रकार का होगा इसका चित्र मार्क्स के निम्नलिखित उद्धरण से मिलता है :—

“कम्युनिस्ट समाज की उच्चतर अवस्था में, व्यक्ति की श्रम-विभाजन के प्रति दासत्वपूर्ण अधीनता और उसी के साथ साथ मानसिक तथा शारीरिक श्रम के अन्तर्विरोध का लोप हो जाने के बाद, श्रम के जीवन के मात्र एक साधन ही नहीं, प्रत्युत जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता बन चुकने के बाद; व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास के साथ-साथ उत्पादक शक्तियों के भी

बढ़ जाने और सामाजिक सम्प्रदाय के सभी स्रोतों के अधिक धेग से प्रवाह-मान होने के बाद—केवल तब जाकर ही पूँजीवादी अधिकार के सही-धित्व को पुनः नापा जा सकेगा और समाज अपनी पताकाओं पर अंकित कर सकेगा : “हर किसी से उसी योग्यतानुसार, हर किसी को उसी आवश्यकतानुसार ।”

^

×

×

×

जब मार्क्स ने उपर्युक्त शब्द लिखे थे उस समय समाजवाद एक स्वप्न था । आज समाजवाद ने एक विश्व व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है । जिन देशों में अभी तक पूँजीवाद कायम है, जैसे कि हमारे देश में, वहाँ की जनता भी समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है । वह दिन अधिक दूर नहीं है जबकि पूरे विश्व में एक ही व्यवस्था होती—समाजवादी व्यवस्था । समाजवाद निश्चित रूप से मानवता की अगली मजिल की ओर ले जायेगा—मार्क्सवाद की ओर ।

